Drishti IAS Presents...

PT SPRINT 2022

अर्थव्यवस्था

(जनवरी 2021 – मार्च 2022)

Answers Answers Answers Explanation Answers Explanation Answers Explanation Answers Answers Answers Explanation Answers Answers Explanation Answers Answers Explanation Answers Answers Explanation Answers Answers Explanation Answers Answers Explanation Answers Answers

Detailed Explanation

Drishti IAS, 641, Mukherjee Nagar, Opp. Signature View Apartment, New Delhi

Drishti IAS, 21 Pusa Road, Karol Bagh New Delhi - 05

Drishti IAS, Tashkent Marg, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh

Drishti IAS, Tonk Road, Vasundhra Colony, Jaipur, Rajasthan

e-mail: englishsupport@groupdrishti.com, **Website:** www.drishtiias.com

Contact: 011430665089, 7669806814, 8010440440

उत्तर

1.

उत्तर: A

व्याख्या:

- जीएसटी कराधान: 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया।
  - जीएसटी के साथ बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य के अप्रत्यक्ष करों का एक ही कर में विलय हो गया।
- क्षतिपूर्ति उपकर:
  - राज्यों को वर्ष 2022 में समाप्त होने वाले पहले पाँच वर्षों के लिये 14% की वृद्धि (आधार वर्ष 2015-16) से नीचे किसी भी राजस्व कमी के लिये क्षतिपूर्ति की गारंटी दी जाती है।
    - जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान केंद्र द्वारा राज्यों को हर दो महीने में मुआवजा उपकर से किया जाता है। अत: कथन 1 सही है।
    - क्षतिपूर्ति उपकर जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 द्वारा निर्दिष्ट किया गया था।
- सभी करदाता, जो विशिष्ट अधिसूचित वस्तुओं का निर्यात करते हैं और जिन्होंने जीएसटी संरचना योजना का विकल्प चुना है, केंद्र सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर जमा करने के लिये उत्तरदायी हैं। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- क्षतिपूर्ति उपकर कोष: जीएसटी अधिनियम में कहा गया है कि एकत्र किये गए उपकर और जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित राशि को फंड में जमा किया जाएगा।

2.

उत्तर: C

व्याख्या

- 'सकल घरेलू उत्पाद' (GDP) अर्थव्यवस्था को व्यय (या मांग) पक्ष से मापता करता है- यानी सभी व्यय जोड़कर। अत: कथन 1 सही है।
  - जीडीपी = निजी खपत + सकल निवेश + सरकारी निवेश + सरकारी खर्च + निर्यात-आयात।
- सकल मूल्य वर्द्धन (Gross Value Added- GVA) आपूर्ति पक्ष से अर्थव्यवस्था की एक तस्वीर प्रदान करता है।
  - सकल मूल्य वर्द्धन किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों, यथा- प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है।
  - सकल मूल्यवर्द्धन = GDP + उत्पादों पर सब्सिडी - उत्पादों पर कर। अत: कथन 2 सही है।

3.

उत्तर: D

व्याख्या

- K-शेप्ड रिकवरी:
  - K-शेप्ड रिकवरी (K-Shaped Recovery) तब होती है, जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग दर, समय या परिमाण में 'रिकवरी' होती है। यह विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों या लोगों के समूहों में समान 'रिकवरी' के सिद्धांत के विपरीत है।
  - K-शेप्ड रिकवरी से अर्थव्यवस्था की संरचना में व्यापक परिवर्तन होता है और आर्थिक परिणाम मंदी के पहले तथा बाद में मौलिक रूप से बदल जाते हैं।
  - इस प्रकार की रिकवरी को 'K-शेप्ड कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जब एक मार्ग पर साथ चलते हैं तो डायवर्ज़न के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कि रोमन अक्षर 'K' की दो भुजाओं से मिलती-जुलती है। अत: विकल्प D सही है।

4.

उत्तर: B

व्याख्या

- बैड बैंक के बारे में:
  - तकनीकी रूप से बैड बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (Asset Reconstruction Company-ARC) या परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (Asset Management Company- AMC) है जो वाणिज्यिक बैंकों के बैड ऋणों को अपने नियंत्रण में लेकर उनका प्रबंधन और निर्धारित समय पर धन की वसूली करती है।
  - बैड बैंक ऋण देने और जमा स्वीकार करने की प्रकिया का भाग नहीं होता है, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट ठीक करने में मदद करता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - बैड लोन का अधिग्रहण आमतौर पर ऋण के बुक वैल्यू से कम होता है और बैड बैंक बाद में जितना संभव हो उतना वसूल करने की कोशिश करता है। अत: कथन 2 सही है।
- बैड बैंक के प्रभाव:
  - वाणिज्यिक बैंकों का दृष्टिकोण: वाणिज्यिक बैंक उच्च NPA स्तर के कारण परेशान हैं, बैड बैंक की स्थापना से इससे निपटने में मदद मिलेगी।

- ऐसा इसलिये है क्योंकि बैंक अपनी सभी ऐसी संपत्तियों से छुटकारा पा लेगा, जो एक त्वरित कदम में उसके मुनाफे को कम कर रहे थे।
- जब वसूली का पैसा वापस भुगतान के रूप में दिया जाएगा, तो यह बैंक की स्थिति में सुधार करेगा। इस बीच यह फिर से उधार देना शुरू कर सकता है।

- सरकार और करदाता परिप्रेक्ष्य: चाहे डूबे हुए ऋणों से ग्रसित PSB का पुनर्पूंजीकरण हो या सुरक्षा रसीदों की गारंटी देना हो, पैसा करदाताओं की जेब से आ रहा है।
  - जबकि पुनर्पूंजीकरण और इस तरह की गारंटी को प्राय: "सुधार" के रूप में नामित किया जाता है, वे एक अच्छे रूप में बैंड अनुदान/सहायता (Band Aids) हैं।
  - PSBs में ऋण देने की प्रक्रिया में सुधार करना ही एकमात्र स्थायी समाधान है।
  - अगर बैड बैंक बाज़ार में ऐसे बैड एसेट्स को बेचने में असमर्थ रहते हैं तो वाणिज्यिक बैंकों को राहत देने की योजना ध्वस्त हो जाएगी। इसका भार वास्तव में करदाता पर पड़ेगा।

5.

उत्तर: A

व्याख्या:

- हाल ही में यूएस फेडरल रिज़र्व (central bank of US) ने ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी का संकेत दिया है। इससे भारतीय बाज़ारों में घबराहट की स्थिति पैदा हो गई है।
  - फेडरल रिज़र्व द्वारा दरों में परिवर्तन या अन्य फैसलों से न केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि यह अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीतियों पर एक निश्चित प्रभाव डालता है।
- भारत पर बढ़ी हुई ब्याज दरों का प्रभाव:
  - इक्विटी मार्केट पर प्रभाव: वैश्विक बाज़ार में डॉलर की बढ़ती कमी से बॉण्ड यील्ड (Bond Yields) में बढ़ोतरी होगी।
  - इससे पहले, भारत में ऋण और इक्विटी बाज़ारों में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का बहिर्वाह देखा गया था जो कि मज़बूत डॉलर एवं अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ तथा अन्य प्रमुख देशों के बीच व्यापार युद्ध से उत्पन्न अनिश्चितताओं का प्रतिफल था।
  - निर्यात और विदेशी मुद्रा पर प्रभाव:
    - भारत विश्व के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातक देशों में से एक है।
    - डॉलर की तुलना में कमज़ोर रुपए के परिणामस्वरूप कच्चे तेल का अधिक महँगा आयात होता है जो पूरी अर्थव्यवस्था में और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागत-संचालित मुद्रास्फीति (Cost-Driven Inflationary) को बढा सकता है जो कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।
    - दूसरी ओर भारत के निर्यात विशेष रूप से आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं को रुपए के संबंध में मज़बूत डॉलर से कुछ हद तक लाभ होगा।
    - हालाँकि निर्यात बाज़ार में मजबूत प्रतिस्पर्द्धा के कारण निर्यातकों को पूरी तरह से एक समान लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। अत: विकल्प A सही है।

6.

उत्तर: A

व्याख्या:

विशेष आहरण अधिकार (SDRs)

- विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। अत: कथन 1 सही है।
- SDR न तो एक मुद्रा है और न ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है। बल्कि यह IMF के सदस्यों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिये SDR का आदान-प्रदान किया जा सकता है।
- SDR के मूल्य की गणना 'बास्केट ऑफ करेंसी' में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर की जाती है। इस बास्केट में पाँच देशों की मुद्राएँ शामिल हैं- अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा रॅन्मिन्बी, जापानी येन और ब्रिटेन का पाउंड। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- विशेष आहरण अधिकार ब्याज (SDRi) सदस्य देशों को उनके द्वारा धारण किये जाने वाले SDR पर मिलने वाला ब्याज है।
- हाल ही में IMF ने भारत को SDR 12.57 बिलियन (लगभग 17.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर) का आवंटन किया है। अब भारत की कुल SDR होल्डिंग्स 13.66 बिलियन SDR है।

7.

उत्तर: A

व्याख्या

- परिभाषित रूप में राजकोषीय घाटा कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियों और गैर-ऋण प्राप्तियों के योग के बीच का अंतर है। यह दर्शाता है कि सरकार शुद्ध रूप में कितना खर्च कर रही है। अत: कथन 1 सही है।

- चूँकि सकारात्मक राजकोषीय घाटा राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों से अधिक व्यय की मात्रा को दर्शाता है, इसलिये इसे ऋण-सृजन पूंजी प्राप्ति द्वारा वित्तपोषित करने की आवश्यकता होती है।

- प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है।
- राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे से पूंजीगत व्यय घटाकर निकाला जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

8.

उत्तर: D

व्याख्या:

- विश्व व्यापार संगठन ने 'विकसित' और 'विकासशील' देशों को परिभाषित नहीं किया है और इसलिये सदस्य देश यह घोषणा करने के लिये स्वतंत्र हैं कि वे 'विकसित' हैं या 'विकासशील'।
  - विश्व बैंक दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को चार आय समूहों- निम्न, निम्न-मध्यम, उच्च-मध्यम और उच्च आय वाले देशों में वर्गीकृत करता है।
  - वर्गीकरण को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को अद्यतन किया जाता है और यह पिछले वर्ष के वर्तमान अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) पर आधारित होता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा कुछ अधिकार प्रदान करता है।
  - कुछ विश्व व्यापार संगठन समझौते हैं जो विकासशील देशों को समझौते को पूरी तरह से लागू करने हेतु लंबी संक्रमण अवधि के साथ प्रदान करते है ताकि विकासशील देश तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकें।
- विश्व व्यापार संगठन का सदस्य स्वयं को विकासशील देश के रूप में घोषित करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे कुछ विकसित देश के सदस्यों की एकतरफा वरीयता योजनाओं जैसे कि सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) से लाभ होगा। अत: कथन 2 सही नहीं है।

9.

उत्तर: B

व्याख्या:

- इसका मतलब है कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा यानी एक या दो चरणों में रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - बढ़ती मुद्रास्फीति के समक्ष दुनिया भर के कई केंद्रीय बैंकों ने या तो ब्याज दरों में वृद्धि की है या संकेत दिया है कि वे जल्द ही ऐसा करेंगे।
  - भारत में भी यह उम्मीद की जा रही है कि RBI रेपो रेट बढ़ाएगा लेकिन उससे पहले उम्मीद की जा रही है कि RBI रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगा और दोनों दरों के बीच के अंतर को कम करेगा।.
- सामान्यीकरण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है। अत: कथन 2 सही है।
- हालाँकि यह न केवल अतिरिक्त तरलता को कम करेगा बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उच्च ब्याज दरों के रूप में उभरकर सामने आएगा।
- इस प्रकार यह उपभोक्ताओं के बीच धन की मांग को कम कर देता है (क्योंकि यह सिर्फ बैंक में पैसा रखने हेतु अधिक उपयुक्त है) और व्यवसायों के लिये नए ऋण उधार लेना महँगा बना देता है। अत: कथन 3 सही है।

10.

उत्तर: A

व्याख्या

मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR):

- यह मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने हेतु 35 देशों के बीच एक अनौपचारिक एवं स्वैच्छिक साझेदारी है, जो 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड को 300 किमी. से अधिक दूरी तक ले जाने में सक्षम है।
- उन सदस्यों को ऐसी मिसाइलों और यूएवी प्रणालियों की आपूर्ति करने से रोका जाता है जो गैर-सदस्यों की एमटीसीआर द्वारा नियंत्रित होते हैं।
- ये निर्णय सभी सदस्यों की सहमति से लिये जाते हैं।
- यह सदस्य देशों का एक गैर-संधि संघ है, जिसमें मिसाइल प्रणालियों हेतु सूचना साझा करने, राष्ट्रीय नियंत्रण कानूनों और निर्यात नीतियों तथा इन मिसाइल प्रणालियों की ऐसी महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को सीमित करने के लिये एक नियम-आधारित विनियमन तंत्र के बारे में कुछ दिशा-निर्देश हैं।
- इसकी स्थापना अप्रैल 1987 में G-7 देशों- यूएसए, यूके, फ्राँस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान द्वारा की गई थी।
- अत: विकल्प A सही है।

11.

उत्तर: B

व्याख्या:

बजट और संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement- AFS) कहा जाता है।

- यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है (जो चालू वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है)।
- बजट में निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाता है:
  - राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान।
  - राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन।
  - व्यय अनुमान।
  - पिछले वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी भी कमी या अधिशेष का कारण।
  - आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति, अर्थात् कराधान प्रस्ताव तथा नई योजनाओं/परियोजनाओं की शुरुआत। अत: विकल्प B सही है।

12.

उत्तर: A

व्याख्या

- ब्लू इकॉनमी की अवधारणा को बेल्जियम के अर्थशास्त्री गुंटर पौली द्वारा वर्ष 2010 में प्रकाशित उनकी पुस्तक 'द ब्लू इकॉनमी: 10 इयर्स, 100 इनोवेशन्स और 100 मिलियन जॉब्स' में प्रस्तुत किया गया था। अत: कथन 1 सही है।
- यह अवधारणा आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के सृजन तथा महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिये महासागरीय संसाधनों का सतत् उपयोग को संदर्भित करती है।
- यह अवधारणा उच्च उत्पादकता हेतु महासागर विकास रणनीतियों को हरित करने की वकालत करती है। अत: कथन 2 सही है।
- ब्लू इकॉनमी सामाजिक समावेश, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ महासागरीय अर्थव्यवस्था के विकास के एकीकरण पर ज़ोर देती है, जो कि अभिनव व्यापार मॉडल के साथ संयुक्त है।
- डीप ओशन मिशन को गहरे महासागरों से जीवित एवं निर्जीव संसाधनों का दोहन करने के लिये प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के इरादे से शुरू किया गया था। यह 'ब्लू इकॉनोमी' को बढ़ावा देगा। अत: कथन 3 सही नहीं है।

13.

उत्तर: A

व्याख्या:

- उपकर या सेस करदाता द्वारा अदा किये जाने वाले मूल कर (Tax) पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर होता है। अत: कथन 1 सही है।
- उपकर मुख्यत: राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिये फंड एकत्रित करने हेतु लागू किया जाता है।
- उपकर सरकार के लिये राजस्व का स्थायी स्रोत नहीं होता है, निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य के पूरा होने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- गौरतलब है कि उपकर को सरकार द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर दोनों पर लागू किया जा सकता है।

14.

उत्तर: C

व्याख्या:

- अगस्त 2021 में सरकार द्वारा खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिये 'खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन'- ऑयल पाम (NMEO-OP) योजना की घोषणा की है और इसमें 11,000 करोड़ रुपए (पाँच साल की अवधि में) से अधिक का निवेश शामिल है।
  - NMEO-OP एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है। अत: कथन 1 सही है।
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, देश में खाद्य तेलों की कुल घरेलू मांग लगभग 250 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है।
  - देश में खपत होने वाले खाद्य तेलों का लगभग 60% आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। पाम तेल (कच्चा + परिष्कृत) का आयात कुल खाद्य तेल के आयात का लगभग 60% है, जिसमें से 54% इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात किया जाता है। अत: कथन 2 सही है।

15.

उत्तर: C

व्याख्या

- श्रम ब्यूरो द्वारा 'ऑल-इंडिया क्वार्टरली इस्टैब्लिशमेंट-बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे' को नौ चयनित क्षेत्रों के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोज़गार एवं प्रतिष्ठानों के संबंध में तिमाही आधार पर अद्यतन करने के लिये आयोजित किया जाता है। अत: कथन 1 सही है।
  - 9 क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्तराँ, आईटी/बीपीओ, वित्तीय सेवा गतिविधियाँ हैं।
- घटक:
  - त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण (QES): यह 10 या उससे अधिक श्रमिकों को रोज़गार देने वाले प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण करता है।
    - संशोधित QES का आयोजन पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2021) के दौरान किया गया था।
    - पेरोल डेटा के साथ संख्या में अंतर का हवाला देते हुए वर्ष 2018 में QES के पुराने संस्करण को निलंबित कर दिया गया था।

- 'एरिया फ्रेम इस्टैब्लिश्मेंट सर्वे' (AFES): यह नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से असंगठित क्षेत्र (10 से कम श्रमिकों के साथ) को कवर करता है। अत: कथन 2 सही है।

16.

उत्तर: A

व्याख्या:

- हाल ही में सरकार ने वर्ष 2027-28 तक सात वर्षों की अवधि के लिये 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड साइट्स में सात 'पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल' (PM Mega Integrated Textile Region and Apparel- PM MITRA) पार्कों की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है।
- 'पीएम मित्र' पार्क को सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड में एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle- SPV) के ज़रिये विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा।
- प्रत्येक 'मित्र' पार्क में एक इन्क्यूबेशन सेंटर, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस और एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट तथा अन्य टेक्सटाइल संबंधी सुविधाएँ जैसे- डिज़ाइन सेंटर एवं टेस्टिंग सेंटर होंगे। अत: विकल्प A सही है।

17.

उत्तर: C

व्याख्या:

- प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना भारतीय उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने और ग्रीनहाउस गैस को कम करने के लिये शुरू की गई थी। अत: कथन 1 सही है।
- ऊर्जा दक्षता के राष्ट्रीय मिशन के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency- BEE) द्वारा PAT के लिये वर्ष 2011 में भारत में ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (Energy Savings Certificates- ESCerts)) प्रस्तुत किये गए थे। अत: कथन 2 सही है।
  - NMEEE वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) के तहत आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक है।
- अंडर अचीवर्स (Under Achievers) द्वारा ESCerts की खरीद दो पावर एक्सचेंजों - इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) के माध्यम से की जाती है।
  - इस योजना में भाग लेने वाले उद्योगों को नामित खरीदार (Designated Shoppers) कहा जाता है।
- PAT में शामिल 13 ऊर्जा-गहन क्षेत्र: थर्मल पावर प्लांट (TPP), सीमेंट, एल्युमीनियम, लोहा और इस्पात, लुगदी तथा कागज़, उर्वरक, क्लोर-क्षार, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, वितरण कंपनियाँ, रेलवे, कपड़ा एवं वाणिज्यिक भवन (होटल व हवाई अड्डे)।

18.

उत्तर: A

व्याख्या:

- परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनी (ARC) एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 'नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स' (NPA) खरीदता है ताकि वे अपनी बैलेंसशीट को स्वच्छ रख सकें। अत: कथन 1 सही है।
  - यह बैंकों को सामान्य बैंकिंग गतिविधियों में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। बैंकों द्वारा बकाएदारों पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने के बजाय वे ARC को अपना NPAs पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर बेच सकते हैं।
  - सरफेसी अधिनियम, 2002 भारत में ARCs की स्थापना के लिये कानूनी आधार प्रदान करता है।
- वर्तमान में, कृषि क्षेत्र में NPAs से निपटने के लिये न तो एक एकीकृत तंत्र है और न ही एक भी कानून है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - कृषि एक राज्य का विषय होने के कारण, वसूली कानून, जहाँ कहीं भी कृषि भूमि को संपार्श्विक के रूप में पेश किया जाता है- अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं।

19.

उत्तर: C

व्याख्या:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2021 के दिसंबर माह के लिये मौद्रिक नीति रिपोर्ट (Monetary Policy Report- MPR) जारी की है।
  - मौद्रिक नीति रिपोर्ट को RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- MPC विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिये RBI अधिनियम, 1934 के तहत एक वैधानिक और संस्थागत ढाँचा है। अत: कथन 1 सही है।
- MPC, 4% के मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नीति ब्याज़ दर (रेपो दर) निर्धारित करती है, जिसमें दोनों तरफ 2% अंक होते हैं।
- RBI का गवर्नर MPC का पदेन अध्यक्ष है। अत: कथन 2 सही है।

20.

उत्तर: C

व्याख्या:

नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज

- NCDEX एक ऑनलाइन कमोडिटी एक्सचेंज है जो मुख्य रूप से कृषि संबंधी उत्पादों में व्यवहार करता है। अत: कथन 1 सही है।
- यह सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी (Public Limited Company) है, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 23 अप्रैल, 2003 को स्थापित किया गया था।
- इस एक्सचेंज की स्थापना भारत के कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थानों जैसे- ICICI बैंक लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आदि द्वारा की गई थी। अत: कथन 2 सही है।
- NCDEX का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, लेकिन व्यापार की सुविधा के लिये देश के कई अन्य हिस्सों में भी इसके कार्यालय हैं।

21.

उत्तर: A

व्याख्या:

- यह एक तरह का म्यूचुअल फंड है। इसमें निवेश स्थायी रूप से सतत् निवेश (Sustainable Investing) या सामाजिक रूप से उत्तरदायी निवेश (Socially Responsible Investing) के साथ किया जाता है। अत: कथन 1 सही है।
- आमतौर पर म्युचुअल फंड किसी कंपनी के अच्छे स्टॉक को दर्शाता है जिसमें आय, प्रबंधन गुणवत्ता, नकदी प्रवाह, व्यवसाय संचालन, प्रतिस्पर्द्धा आदि की क्षमता होती है।
- हालाँकि निवेश के लिये एक स्टॉक का चयन करते समय सबसे पहले 'ESG फंड शॉर्टलिस्ट कंपनियों' के पर्यावरण, सामाजिक ज़िम्मेदारी एवं कॉर्पोरेट प्रशासन पर उच्च स्कोर को देखा जाता है, इसके बाद वित्तीय कारकों पर गौर किया जाता है।
  - इसलिये 'ईएसजी फंड' एवं अन्य फंडों के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर 'निवेशक के विवेक' पर आधारित होता है अर्थात् ईएसजी फंड पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं, नैतिक व्यापार प्रथाओं एवं एक कर्मचारी-अनुकूल रिकॉर्ड वाली कंपनियों पर केंद्रित होता है।
- फंड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

22.

उत्तर: A

व्याख्या:

- भारत में बंदरगाहों को भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 के तहत परिभाषित केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत प्रमुख और छोटे बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - प्रमुख बंदरगाहों का स्वामित्व और प्रबंधन केंद्र सरकार के पास है। अत: कथन 1 सही है।
  - छोटे बंदरगाहों का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य सरकारों के पास होता है।
- कानूनी प्रावधान: भारत के प्रमुख बंदरगाह भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं और भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 व प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के तहत प्रशासित हैं।
  - संसद द्वारा घोषित प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाह, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के विषय हैं। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- प्रमुख बंदरगाहों की संख्या: देश में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 गैर-प्रमुख बंदरगाह (छोटे बंदरगाह) हैं।
  - प्रमुख बंदरगाहों में दीनदयाल (पूर्ववर्ती कांडला), मुंबई, जेएनपीटी, मरमुगाओ, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, कामराजार (पहले एन्नोर), वीओ चिदंबरनार, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता (हल्दिया सहित) शामिल हैं।

23.

उत्तर: C

व्याख्या:

- भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication) का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। इन उत्पादों की विशिष्ट विशेषता एवं प्रतिष्ठा भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। किसी उत्पाद को दिया गया टैग जो जीआई के रूप में कार्य करता है उस उत्पाद के मूल स्थान की पहचान के रूप में कार्य करता है।
  - इसका उपयोग कृषि, प्राकृतिक और निर्मित वस्तुओं के लिये किया जाता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- एक बार जीआई सुरक्षा प्रदान कर दिये जाने के बाद कोई अन्य निर्माता समान उत्पादों के विपणन हेतु नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी सुविधा प्रदान करता है।
  - किसी उत्पाद के लिये जीआई टैग होने से यह दूसरों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकता है, कानूनी सुरक्षा प्रदान करके भारतीय भौगोलिक संकेतों के निर्यात को बढ़ावा देता है और अन्य विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों में कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिये पेरिस कन्वेंशन के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के एक घटक के रूप में शामिल हैं।

- वर्ष 1883 में अपनाया गया पेरिस कन्वेंशन व्यापक अर्थों में औद्योगिक संपत्ति पर लागू होता है, जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन, उपयोगिता मॉडल, सेवा चिह्न, व्यापार नाम, भौगोलिक संकेतक और अनुचित प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करना शामिल है।
- जीआई विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के बौद्धिक संपदा अधिकारों (ट्रिप्स) के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर समझौते द्वारा भी शासित है। अत: कथन 2 सही है।
- भारत के लिये भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई में स्थित है।
- भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिये वैध होता है। इसे समय-समय पर 10-10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि हेतु नवीनीकृत किया जा सकता है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

24.

उत्तर: D

व्याख्या:

विभिन्न कॉलर वर्कर:

- ब्लू-कॉलर वर्कर: इसमें मज़दूर वर्ग शारीरिक श्रम के माध्यम से आय अर्जन करता है। अत: युग्म 1 सही सुमेलित है।
- व्हाइट-कॉलर वर्कर: यह एक वेतनभोगी पेशेवर है, जो आमतौर पर कार्यालय के प्रबंधन का कार्य करता करता है। अत: युग्म 2 सही सुमेलित है।
- गोल्ड-कॉलर वर्कर: इस प्रकार के वर्कर का उपयोग अत्यधिक कुशल ज्ञान वाले लोगों को संदर्भित करने हेतु किया जाता है जो कंपनी के लिये अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। उदाहरण: वकील, डॉक्टर, शोध वैज्ञानिक आदि।
- ग्रे-कॉलर वर्कर: यह व्हाइट या ब्लू-कॉलर के रूप में वर्गीकृत नहीं किये गए नियोजित लोगों को संदर्भित करता है।
  - हालाँकि ग्रे-कॉलर का प्रयोग उन लोगों का वर्णन करने के लिये भी किया जाता है जो सेवानिवृत्ति की आयु से परे काम करते हैं। उदाहरण: अग्निशामक, पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, सुरक्षा गार्ड आदि।
- ग्रीन-कॉलर वर्कर: ये ऐसे वर्कर हैं जो अर्थव्यवस्था के पर्यावरणीय क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
  - उदाहरण: वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे- सौर पैनल, ग्रीनपीस, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर आदि में काम करने वाले वर्कर।
- पिंक-कॉलर वर्कर: यह एक ऐसा रोज़गार है जिसे पारंपरिक रूप से महिलाओं का काम माना जाता है और अक्सर कम वेतन मिलता है।
- स्कारलेट-कॉलर वर्कर: यह एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर पोर्नोग्राफी उद्योग में काम करने वाले लोगों, विशेष रूप से इंटरनेट पोर्नोग्राफी के क्षेत्र में महिला उद्यमियों को संदर्भित करने के लिये किया जाता है।
- रेड-कॉलर वर्कर: सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारी। अत: युग्म 3 सही सुमेलित है।
- ओपन-कॉलर वर्कर: यह एक ऐसा वर्कर है जो घर से खासकर इंटरनेट के ज़रिये काम करता है।

25.

उत्तर: B

व्याख्या

- भारत में श्वेत क्रांति की अवधारणा 'डॉ. वर्गीज़ कुरियन' द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- उनके अधीन गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) जैसे कई महत्त्वपूर्ण संस्थान स्थापित किये गए थे।
- ग्राम दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समितियों को इस क्रांति की आधारशिला माना जाता हैं। 'ऑपरेशन फ्लड' के दौरान उनकी प्रमुख भूमिका को विकास के इंजन के रूप में देखा जाता है। अत: कथन 2 सही है।
- नीति ने संयुक्त उद्यमों: विलय और अधिग्रहण के माध्यम से भारतीय डेयरी क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय डेयरी निगमों के प्रवेश का भी समर्थन किया है।

26.

उत्तर: A

व्याख्या:

- डंपिंग शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी देश द्वारा दूसरे देश को माल का निर्यात उस कीमत से कम कीमत पर किया जाता है जो वह आमतौर पर अपने घरेलू बाज़ार में वसूलता है।
  - यह एक अनुचित व्यापार प्रथा है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकृत प्रभाव पड़ सकता है।
- डंपिंग रोधी शुल्क का अधिरोपण माल की डंपिंग और उसके व्यापार विकृत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति को सुधारने का एक उपाय है।
- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के एंटी-डंपिंग शुल्क से संबंधित प्रावधान:
  - वैधता: एक एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होने की तारीख से पाँच साल की अवधि के लिये वैध है जब तक कि इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है।
  - सनसेट रिव्यू: इसे सनसेट या समाप्ति समीक्षा जाँच के माध्यम से पाँच वर्ष की अवधि के लिये और बढ़ाया जा सकता है।
    - एक सनसेट रिव्यू/सूर्यास्त समीक्षा/समाप्ति समीक्षा एक कार्यक्रम या एक एजेंसी के निरंतर अस्तित्व की आवश्यकता का मूल्यांकन है। यह कार्यक्रम या एजेंसी की प्रभावशीलता और प्रदर्शन का आकलन करने की अनुमति देता है।

- इस तरह की समीक्षा स्वप्रेरणा से या घरेलू उद्योग से या उसकी ओर से प्राप्त विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर शुरू की जा सकती है। अत: विकल्प A सही है।

27.

उत्तर: A

व्याख्या:

- गिग इकॉनमी एक मुक्त बाज़ार प्रणाली है जिसमें पद अस्थायी होते हैं और संगठन अल्पकालिक जुड़ाव के लिये स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं।
  - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, गिग वर्कर्स को एक नई व्यावसायिक श्रेणी के रूप में मान्यता देती है। अत: कथन 1 सही है।
    - यह गिग वर्कर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के बाहर काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों से आय अर्जन करता है।
  - गिग वर्कर आमतौर पर ब्लू-कॉलर वर्कर होते हैं।
- ग्रे-कॉलर वर्कर: यह व्हाइट या ब्लू-कॉलर के रूप में वर्गीकृत नहीं किये गए नियोजित लोगों के संतुलन को संदर्भित करता है।
  - हालाँकि ग्रे-कॉलर उन लोगों का वर्णन करने के लिये प्रयोग किया जाता है जो सेवानिवृत्ति की आयु से परे काम करते हैं। उदाहरण: अग्निशामक, पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, सुरक्षा गार्ड आदि। अत: कथन 2 सही नहीं है।

28.

उत्तर: B

व्याख्या:

- जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से पेश किया गया था। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - जीएसटी देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है।
- यह अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है।
  - जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्द्धित कर (वैट), सेवा कर, विलासिता कर आदि जैसे अप्रत्यक्ष करों को शामिल कर लिया है। अत: कथन 2 सही है।
- यह अनिवार्य रूप से एक उपभोग कर है और अंतिम उपभोग बिंदु पर लगाया जाता है।
  - इसने दोहरे कराधान, करों के व्यापक प्रभाव, करों की बहुलता, वर्गीकरण के मुद्दों आदि को कम करने में मदद की है और एक आम राष्ट्रीय बाज़ार का नेतृत्व किया है।
  - इसे 'वन नेशन वन टैक्स' के नारे के साथ पेश किया गया था।

29.

उत्तर: A

व्याख्या:

- मूल्यह्रास तब होता है जब एक मुद्रा के मूल्य में अस्थायी विनिमय दर में गिरावट होती है।
  - रुपए के मूल्यह्रास का मतलब है कि रुपया अब पहले की तुलना में कमज़ोर है।
- भारतीय रुपए के मूल्यह्रास का प्रभाव:
  - सकारात्मक प्रभाव: एक कमज़ोर मुद्रा महामारी के समय नए आर्थिक सुधार के बीच निर्यात को प्रोत्साहित कर सकती है।
  - नकारात्मक प्रभाव: यह आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम उत्पन्न करता है और केंद्रीय बैंक के लिये ब्याज दरों को रिकॉर्ड स्तर पर लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल बना सकता है। अत: कथन 1 और कथन 2 सही हैं।
- मुद्रा अभिमूल्यन : यह किसी अन्य मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि है।
  - मुद्रा अभिमूल्यन किसी देश की निर्यात गतिविधि को हतोत्साहित करता है क्योंकि विदेशों से वस्तुएँ खरीदना सस्ता हो जाता है, जबकि विदेशी व्यापारियों द्वारा देश की वस्तुएँ खरीदना महँगा हो जाता है। अत: कथन 3 सही नहीं है। अत: विकल्प A सही है।

30.

उत्तर: C

व्याख्या:

- जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC), वर्ष 1978 में संसद द्वारा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, 1961 के पारित होने के बाद जमा बीमा निगम (Deposit Insurance Corporation- DIC) तथा क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Credit Guarantee Corporation of India- CGCI) के विलय के बाद अस्तित्व में आया।
- यह भारत में बैंकों के लिये जमा बीमा और ऋण गारंटी के रूप में कार्य करता है। अत: कथन 1 सही है।
- यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अत: कथन 2 सही है।

31.

उत्तर: B

व्याख्या:

- स्मर्फिंग धन-शोधन की एक तकनीक है जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी को कई छोटे लेनदेन में शामिल किया जाता है। इन एकाधिक खातों से धन को स्रोत से दूर ले जाने के लिये एक ऑफशोर बैंक खाते में

स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार का लेन-देन आमतौर पर एक निश्चित सीमा से ऊपर के लेनदेन की निगरानी करने वाले अधिकारियों द्वारा नोटिस से बचने के लिये किया जाता है।

- स्मर्फिंग संरचना का एक रूप है, जिसमें अपराधी वित्तीय रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से नीचे रहने के लिये छोटे, संचयी लेनदेन का उपयोग करते हैं। अत: विकल्प B सही है।

32.

उत्तर: C

व्याख्या

- 'त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई' (PCA) ढाँचा उचित समय पर वाणिज्यिक बैंकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है और प्रभावी बाज़ार अनुशासन सुनिश्चित करता है। अत: कथन 1 सही है।
- यह ढाँचा भारत में परिचालित सभी बैंकों पर लागू होता है, जिसमें शाखाओं या सहायक कंपनियों के माध्यम से परिचालन करने वाले विदेशी बैंक भी शामिल हैं। अत: कथन 2 सही है।
  - हालाँकि भुगतान बैंकों और 'छोटे वित्त बैंकों' (SFBs) को उन ऋणदाताओं की सूची से हटा दिया गया है, जहाँ रिज़र्व बैंक द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

33.

उत्तर: C

व्याख्या

- 'परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी' एक विशेष वित्तीय संस्थान है, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 'गैर-निष्पादित संपत्तियों' (NPAs) खरीदता है ताकि वे अपनी बैलेंसशीट को सुस्पष्ट रख सकें।
  - NPA एक ऋण या अग्रिम है जिसके लिये मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिये अतिदेय है।
- आमतौर पर ARC के एक हिस्से को नकद अग्रिम (RBI द्वारा अनिवार्य रूप से 15%) के रूप में भुगतान करके बैंकों के NPA खरीदते हैं, और शेष राशि (85%) के लिये प्रतिभूति 'रसीद' (Security Receipts) जारी करते हैं।
- सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट'(SARFAESI), 2002 भारत में ARCs की स्थापना के लिये कानूनी आधार प्रदान करता है। अत: कथन 1 सही है।
  - सरफेसी अधिनियम न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना गैर-निष्पदनकारी संपत्ति के पुनर्निर्माण में मदद करता है। इस अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में ARCs का गठन और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ पंजीकृत किया गया।
- RBI को ARCs को विनियमित करने की शक्ति मिली है। अत: कथन 2 सही है।

34.

उत्तर: D

व्याख्या:

- तकनीकी वस्त्र कार्यात्मक वस्त्र होते हैं जो ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि सहित विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग होते हैं। अत: कथन 1 सही है।
- भारत में तकनीकी वस्त्रों के विकास ने विगत पाँच वर्षों में गति प्राप्त की है, जो वर्तमान में प्रतिवर्ष 8% की दर से बढ़ रहा है।
  - आगामी पाँच वर्षों के दौरान इस वृद्धि को 15-20% के दायरे में लाने का लक्ष्य है।
  - मौजूदा विश्व बाज़ार 250 अरब अमेरिकी डॉलर (18 लाख करोड़ रुपए) का है और इसमें भारत की हिस्सेदारी 19 अरब अमेरिकी डॉलर है।
  - भारत इस बाज़ार (8% शेयर) में 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ एक महत्त्वाकांक्षी भागीदार है।
  - सबसे बड़े भागीदारों में यूएसए, पश्चिमी यूरोप, चीन और जापान (20-40%) हैं।
- भारत सरकार स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देती है। अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र निर्माताओं जैसे- अहलस्ट्रॉम, जॉनसन एंड जॉनसन आदि ने पहले ही भारत में परिचालन शुरू कर दिया है। अत: कथन 2 सही है।
- इसका उद्देश्य निर्यात में सुधार करना और अप्रत्यक्ष रूप से वस्त्र उद्योग क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है।
- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS के तहत तकनीकी सलाहकार निगरानी समिति (TAMC) के मार्गदर्शन में कपड़ा और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के निर्माण से संबंधित संस्थाओं को प्रौद्योगिकी उन्नयन और CIS की पेशकश की जाती है। अत: कथन 3 सही है।

35.

उत्तर: D

व्याख्या:

भुगतान संतुलन के घटक (BoP):

- एक देश का BoP खाता तैयार करने के लिये विश्व के अन्य हिस्सों के बीच इसके आर्थिक लेन-देन को चालू खाते, पूंजी खाते, वित्तीय खाते और त्रुटियों तथा चूक के तहत वर्गीकृत किया जाता है। यह विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserve) में परिवर्तन को भी दर्शाता है।

- चालू खाता: यह दृश्यमान (जिसे व्यापारिक माल भी कहा जाता है- व्यापार संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है) और अदृश्यमान वस्तुओं (गैर-व्यापारिक माल भी कहा जाता है) के निर्यात तथा आयात को दर्शाता है।
  - अदृश्यमान में सेवाएँ, विप्रेषण और आय शामिल हैं।
- पूंजी खाता: यह किसी देश के पूंजीगत व्यय और आय को दर्शाता है।
  - यह एक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक निवेश दोनों के शुद्ध प्रवाह का सारांश देता है।
  - बाहरी वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowing), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment), विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment) आदि पूंजी खाते के हिस्से हैं।
- त्रुटियाँ और चूक: कभी-कभी भुगतान संतुलन की स्थिति न होने के कारण इस असंतुलन को BoP में त्रुटियों और चूक (Errors and Omissions) के रूप में दिखाया जाता है। यह सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन को सही ढंग से रिकॉर्ड करने में देश की अक्षमता को दर्शाता है।
- विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन: मुद्रा भंडार में होने वाले उतार-चढ़ाव में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा धारित विदेशी मुद्रा आस्तियों में परिवर्तन और विशेष आहरण अधिकार (SDR) परिवर्तन शामिल हैं। अत: विकल्प D सही है।

36.

उत्तर: B

व्याख्या:

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने एकीकृत लोकपाल योजना लॉन्च की है। यह आरबीआई (RBI) की तीन लोकपाल योजनाओं- वर्ष 2006 की बैंकिंग लोकपाल योजना, वर्ष 2018 की एनबीएफसी (NBFCs) के लिये लोकपाल योजना और वर्ष 2019 की डिजिटल लेन-देन की लोकपाल योजना को समाहित करता है।
- एकीकृत लोकपाल योजना भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाएँ जैसे- बैंक, एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करेगी, अगर शिकायत का समाधान ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है या विनियमित इकाई द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है। अत: कथन 1 सही है।
  - इसमें गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक भी शामिल हैं जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। यह योजना आरबीआई लोकपाल तंत्र के क्षेत्राधिकार को तटस्थ बनाकर 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' दृष्टिकोण अपनाती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- यह योजना अपवर्जनों की निर्दिष्ट सूची के साथ शिकायत दर्ज करने के आधार के रूप में 'सेवा में कमी' को परिभाषित करती है।
  - अत: शिकायतों को अब केवल "योजना में सूचीबद्ध आधारों के अंतर्गत शामिल नहीं" होने के कारण खारिज नहीं किया जाएगा।
  - यह योजना क्षेत्राधिकार तटस्थ है और किसी भी भाषा में शिकायतों के प्रारंभिक निपटान के लिये चंडीगढ़ में एक केंद्रीकृत रिसीप्ट और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है।
- एकीकृत योजना के तहत उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग के प्रभारी आरबीआई के कार्यकारी निदेशक अपीलीय प्राधिकारी होंगे। अत: कथन 3 सही नहीं है।

37.

उत्तर: A

व्याख्या:

- 'सर्बरस' एक बैंकिंग ट्रोजन है जो मुख्य रूप से क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे वित्तीय डेटा चोरी करने हेतु उपयोग किया जाता है।
  - ट्रोजन एक प्रकार का कोड या सॉफ़्टवेयर है, जो डेटा या नेटवर्क को नुकसान पहुँचाता है, बाधित करता है, चोरी करता है या हानिकारक कार्रवाई करता है।
    - बैंकिंग ट्रोजन एक ऐसा प्रोग्राम है, जिसका उपयोग ऑनलाइन बैंकिंग और भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने वाले ग्राहकों के बारे में गोपनीय जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जाता है।
- 'सर्बरस' का कार्य:
  - यह कोविड -19 महामारी का लाभ उठाता है और एक उपयोगकर्त्ता को दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर वाले लिंक को डाउनलोड करने हेतु लुभाने के लिये एसएमएस भेजता है।
  - यह अपने एप्लिकेशन को आमतौर पर फिशिंग अभियानों के माध्यम से फैलाता है, ताकि उपयोगकर्त्ताओं को इसे अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल करने के लिये प्रेरित किया जा सके।
    - ऐसा प्रतीत होता है कि लिंक वाला ईमेल या टेक्स्ट संदेश बैंक जैसे किसी विश्वसनीय स्रोत से आया है।
    - लिंक उपयोगकर्त्ता को एक जाली वेबसाइट पर ले जाता है और एक बार लॉगिन नाम और पासवर्ड जैसे विवरण दर्ज करने के बाद, लॉगिन क्रेडेंशियल हैकर तक पहुँच जाते हैं। अत: विकल्प A सही है।

38.

उत्तर: D

व्याख्या:

- क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लाभ:
  - तीव्र और सस्ते लेन-देन: अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन को निष्पादित करने के लिये क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करना सस्ता है क्योंकि

क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन को उनके गंतव्य तक पहुँचने से पहले बिचौलियों की शृंखला द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। अत: कथन 1 सही है।

- निवेश गंतव्य: क्रिप्टोकरेंसी की आपूर्ति सीमित है- आंशिक रूप से सोने की तरह। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में अन्य वित्तीय साधनों की तुलना में क्रिप्टोकरेंसी की कीमत तेज़ी से बढ़ी है।
  - इसके कारण लोगों का झुकाव क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने का अधिक देखा जा सकता है। अत: कथन 2 सही है।
- मुद्रास्फीति विरोधी मुद्रा: क्रिप्टोकरेंसी की उच्च मांग के कारण इसकी कीमतें काफी हद तक 'वृद्धिमान प्रक्षेप वक्र' (Growing Trajectory) द्वारा निर्धारित होती हैं। इस परिदृश्य में लोग इसे खर्च करने की तुलना में अपने पास रखना अधिक पसंद करते हैं। अत: कथन 3 सही है।
  - इससे मुद्रा पर अपवस्फीतिकारी प्रभाव (Deflationary Effect) उत्पन्न होगा।

39.

उत्तर: C

व्याख्या:

- केयर्न इंडिया पश्चिमी राजस्थान के 'लोअर बाड़मेर हिल फॉर्मेशन' में शेल अन्वेषण शुरू करने के लिये अमेरिका स्थित हॉलिबर्टन के साथ साझेदारी करेगी।
- शेल गैस: पारगम्य चट्टानों से आसानी से निकाले जा सकने वाले पारंपरिक हाइड्रोकार्बन के विपरीत शेल गैस कम पारगम्य चट्टानों के नीचे पाई जाती है। अत: कथन 1 सही है।
- वर्तमान में भारत में शेल तेल और गैस का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन नहीं होता है। अत: कथन 2 सही है।
  - सरकारी स्वामित्व वाली ओएनजीसी ने वर्ष 2013 में गुजरात में कैम्बे बेसिन और आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन में शेल तेल की संभावनाएँ तलाशी थीं।
  - हालाँकि यह निष्कर्ष निकाला गया कि इन घाटियों में देखे गए तेल प्रवाह की मात्रा "व्यावसायिकता" का संकेत नहीं देती है और भारतीय शेल्स की सामान्य विशेषताएँ उत्तरी अमेरिकी शेल्स से काफी अलग हैं।

40.

उत्तर: A

व्याख्या:

- प्रेषित धन या रेमिटेंस का आशय प्रवासियों द्वारा मूल देश में मित्रों और रिश्तेदारों को किये गए वित्तीय या अन्य तरह के हस्तांतरण से है।
  - यह मूलत: दो मुख्य घटकों का योग है - निवासी और अनिवासी परिवारों के बीच नकद या वस्तु के रूप में व्यक्तिगत स्थानांतरण और कर्मचारियों का मुआवज़ा, जो उन श्रमिकों की आय को संदर्भित करता है जो सीमित समय के लिये दूसरे देश में काम करते हैं।
  - प्रेषण या प्रेषित धन, प्राप्तकर्त्ता देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करता है, लेकिन यह ऐसे देशों को उन पर अधिक निर्भर भी बना सकता है। अत: कथन 1 सही है।
- विश्व बैंक के 'माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ' (Migration and Development Brief) के अनुसार, भारत वर्ष 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर (पिछले वर्ष से 4.6% की वृद्धि) प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषित धन (Remittances) प्राप्तकर्त्ता रहा है।
  - भारत के पश्चात् चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा स्रोत बन गया है, जो कुल प्रेषित धन के 20% से अधिक के लिये ज़िम्मेदार है।

41.

उत्तर: C

व्याख्या:

- सामरिक पेट्रोलियम भंडार प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या अन्य आपदाओं के कारण आपूर्ति में व्यवधान के जोखिम जैसे किसी भी कच्चे तेल से संबंधित संकट से निपटने के लिये कच्चे तेल के विशाल भंडार होते हैं।
  - ओपेक (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन) तेल संकट के बाद समर्पित रणनीतिक भंडार की अवधारणा को पहली बार वर्ष 1973 में अमेरिका में लाया गया था। अत: कथन 1 सही है।
- IEA के अनुसार, 90 दिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिये SPR स्तरों को बनाए रखने के आमतौर पर तीन तरीके हैं।
- रिफाइनरों के पास वाणिज्यिक स्टॉक,
- सरकार और एजेंसी के शेयर,
- देशों को संतुलन के अनुसार चुनना।
- अत: कथन 2 सही है।
- 3 सबसे बड़े सामरिक पेट्रोलियम भंडार जापान, अमेरिका, चीन के पास हैं। अत: कथन 3 सही नहीं है।

42.

उत्तर: C

व्याख्या:

- बैंकों का समेकन वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर उनकी उपस्थिति को मज़बूत करने में मदद करता है।

- साझा नेटवर्क की उपस्थिति से परिचालन लागत को कम भी किया जा सकेगा और इस बढ़ी हुई परिचालन दक्षता से बैंकों की उधार लागत भी कम हो जाएगी
- बड़े बैंकों में सरकारी खजाने पर निर्भर रहने के बजाय बाज़ार से संसाधन जुटाने की बेहतर क्षमता होती है।
- जिन बैंकों का विलय हो रहा है, उनसे शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने में देरी देखे जाने की संभावना है क्योंकि ऐसे बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी सभी निर्णयों को ठंडे बस्ते में डाल देंगे और इससे सिस्टम में क्रेडिट डिलीवरी में गिरावट आएगी।
- अत: विकल्प C सही नहीं है।

43.

उत्तर: A

व्याख्या

डिजिटल सेवा कर (DSTs)

- यह कर गूगल, अमेज़न और एप्पल जैसी डिजिटल बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने के बदले प्राप्त राजस्व पर अधिरोपित किया जाता है। अत: कथन 1 सही है।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) वर्तमान में 130 से अधिक देशों के साथ वार्ता कर रहा है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली को अनुकूलित करना है। इस वार्ता का एक लक्ष्य अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की कर चुनौतियों का समाधान करना है।
- बीते दिनों सरकार ने 2 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले गैर-निवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा प्रदान किये गए व्यापार और सेवाओं पर 2 प्रतिशत डिजिटल सेवा कर (DST) लगाते हुए वित्त विधेयक 2020-21 में एक संशोधन किया था। अत: कथन 2 सही नहीं है।

44.

उत्तर: C

व्याख्या

- पशुपालन और डेयरी मंत्रालय प्रतिवर्ष 26 नवंबर को 'राष्ट्रीय दुग्ध दिवस' (NMD) मनाता है।
- राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 'डॉ. वर्गीज कुरियन' (भारत के 'मिल्क मैन') की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - 'राष्ट्रीय दुग्ध दिवस-2021' डॉ. कुरियन की 100वीं जयंती को संदर्भित करता है।
- ऑपरेशन फ्लड ने वर्ष 2016-17 में भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनने में मदद की।
  - वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, जिसका वैश्विक उत्पादन 22% है। अत: कथन 2 सही है।
- डॉ वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति में उनके योगदान के लिये भारत के मिल्क मैन के रूप में जाना जाता है। अत: कथन 3 सही है।

45.

उत्तर: D

व्याख्या

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग:

- यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का मुख्य कानूनी निकाय है।

इसकी स्थापना वर्ष 1966 में इस उद्देश्य से की गई थी कि यह सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्त्वपूर्ण कारक है।

- अपने कई मॉडल कानूनों, कन्वेंशनों, और कार्य समूहों के बीच मज़बूत वार्ता के माध्यम से 'UNCITRAL' ने सदस्य देशों को उनकी परिस्थितियों के लिये उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक एवं व्यापार कानून के सिद्धांतों की तुलना, जाँच, वार्ता तथा उन्हें अपनाने हेतु एक मूल्यवान मंच प्रदान किया है।
- भारत उन आठ देशों में से एक है, जो 'UNCITRAL' की स्थापना से ही उसके सदस्य हैं।
- UNCITRAL मॉडल सीमा पार दिवाला मुद्दों से निपटने के लिये सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत कानूनी ढाँचा है।
  - इसे ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर समेत 49 देशों ने अपनाया है। अत: विकल्प D सही है।

46.

उत्तर: A

व्याख्या

'ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट' स्कीम

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई यह योजना एक एकीकृत और व्यापक प्रमाणन प्रणाली है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- यह योजना उत्पादों और प्रक्रियाओं दोनों में उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रदूषण शमन, ऊर्जा दक्षता, वित्तीय स्थिति, मानव संसाधन तथा डिज़ाइन एवं बौद्धिक संपदा अधिकार सहित तकनीकी रूप से सक्षम बनाने हेतु उत्तरदायी है।
- इसका मिशन 'ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो प्रभाव' के सिद्धांतों के आधार पर भारत में 'ZED' संस्कृति को विकसित और कार्यान्वित करना है।
- ज़ीरो डिफेक्ट
  - ज़ीरो डिफेक्ट अवधारणा ग्राहक केंद्रित है।

- शून्य गैर-अनुरूपता या गैर-अनुपालन
- शून्य अपशिष्ट

- ज़ीरो इफेक्ट
  - शून्य वायु प्रदूषण, तरल निर्वहन, ठोस अपशिष्ट
  - प्राकृतिक संसाधनों का शून्य अपव्यय
  - अत: कथन 1 सही है।

47.

उत्तर: C

व्याख्या:

- कॉफी को भारत में सत्रहवीं शताब्दी के अंत में पेश किया गया था। डचों (जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया) ने पूरे देश में कॉफी की खेती को फैलाने में मदद की।
  - लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश राज के आगमन के साथ ही वाणिज्यिक कॉफी की खेती पूरी तरह से फली-फूली। अत: विकल्प A सही नहीं है।
- भारत में कॉफी पश्चिमी और पूर्वी घाटों के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में घने प्राकृतिक वृष्टि छाया क्षेत्र में उगाई जाती है।
  - कॉफी मुख्य रूप से एक निर्यात उन्मुख वस्तु है और देश में उत्पादित 65% से 70% कॉफी का निर्यात किया जाता है, जबकि शेष की खपत देश में होती है। अत: विकल्प B सही नहीं है।
- भारत में कॉफी की पारंपरिक खेती पश्चिमी घाट के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है।
  - कर्नाटक कुल कॉफी उत्पादन के लगभग 70% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक है। अत: विकल्प C सही है।
  - कॉफी की खेती आंध्र प्रदेश और ओडिशा के गैर-पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ उत्तर-पूर्व राज्यों में भी तेज़ी से बढ़ रही है।
- भारत में कॉफी की अरेबिका और रोबस्टा किस्मों की खेती की जाती है।
  - अरेबिका हल्की कॉफी है, लेकिन इसकी फलियाँ अधिक सुगंधित होने के कारण रोबस्टा फलियों की तुलना में इसका बाज़ार मूल्य अधिक है। अत: विकल्प D सही नहीं है।
  - अरेबिका की खेती रोबस्टा की तुलना में अधिक ऊँचाई पर की जाती है।

48.

उत्तर: A

व्याख्या:

- क्रिप्टोक्यूरेंसी एक विशिष्ट प्रकार की आभासी मुद्रा है, जो क्रिप्टोग्राफ़िक एन्क्रिप्शन तकनीकों (Cryptographic Encryption Techniques) द्वारा विकेंद्रीकृत और संरक्षित है। अत: कथन 1 सही है।
  - बिटकॉइन, एथेरियम, रिपल क्रिप्टोकरेंसी के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं।
- फिलहाल भारत में क्रिप्टोकरेंसी हेतु कोई कानूनी विधान नहीं है। भारत में, क्रिप्टोकरेंसी अभी भी अवैध नहीं है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया था, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) द्वारा लगाया गया था।

49.

उत्तर: B

व्याख्या:

माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ:

- यह माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट, (Migration and Remittances Unit, Development Economics) विश्व बैंक के प्रमुख अनुसंधान और डेटा शाखा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (Development Economics) द्वारा तैयार किया गया है।
  - इसका उद्देश्य पिछले छह महीनों में प्रवासन और रेमिटेंस प्रवाह तथा संबंधित नीतियों के क्षेत्र में प्रमुख विकास पर एक अद्यतन प्रदान करना है।
  - यह विकासशील देशों को रेमिटेंस प्रेषण प्रवाह के लिये मध्यम अवधि का अनुमान भी प्रदान करता है।
  - यह डेटा में वर्ष में दो बार तैयार किया जाता है। अत: विकल्प B सही है।

50.

उत्तर: A

व्याख्या

- 'ट्रस्ट' को एक प्रत्ययी व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहाँ एक तृतीय पक्ष, जिसे ट्रस्टी के रूप में संदर्भित किया जाता है, ट्रस्ट के माध्यम से लाभान्वित व्यक्तियों या संगठनों की ओर से संपत्ति धारित करता है। अत: कथन 1 सही है।

- ट्रस्ट एक अलग कानूनी इकाई नहीं होती है, इसकी कानूनी प्रकृति 'ट्रस्टी' में निहित होती है। कभी-कभी, 'सेटलर' एक 'संरक्षक' की नियुक्ति करता है, जिसके पास ट्रस्टी की निगरानी करने की शक्ति होती है और वह ट्रस्टी को हटाकर एक नई नियुक्ति भी कर सकता है।
- भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 ट्रस्ट की अवधारणा को कानूनी आधार प्रदान करता है। भारतीय कानून, ट्रस्ट को 'लाभार्थियों' के लाभ हेतु संपत्ति का प्रबंधन और उपयोग करने के लिये ट्रस्टी के दायित्व के रूप में मान्यता देते हैं। भारत 'ऑफशोर' ट्रस्टों को भी मान्यता देता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

51.

उत्तर: C

व्याख्या

- 'सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग' किसी देश या सॉवरेन संस्था की साख का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है।
  - यह निवेशकों को राजनीतिक जोखिम सहित किसी विशेष देश के ऋण में निवेश से जुड़े जोखिम के स्तर के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। अत: कथन 1 सही है।
- सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग की भूमिका विदेशी ऋण बाज़ारों में बॉण्ड जारी करने के अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने में महत्त्वपूर्ण है। अत: कथन 2 सही है।
- किसी देश के अनुरोध पर एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसके आर्थिक और राजनीतिक वातावरण का मूल्यांकन करके इसे रेटिंग प्रदान करती है।
  - मूडीज एक Baa3 या उच्चतर रेटिंग को निवेश ग्रेड का मानता है और Ba1 तथा उससे नीचे की रेटिंग को "जंक" ग्रेड माना जाता है।
  - S&P उन देशों को BBB या उच्च रेटिंग देता है जिन्हें वह निवेश ग्रेड मानता है, और BB+ या उससे कम के ग्रेड को "जंक" ग्रेड माना जाता है।

52.

उत्तर: D

व्याख्या:

- सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन, आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, परियोजनाएँ या अन्य अचल संपत्ति को विनिवेश कहा जाता है।
- सरकार राजकोषीय बोझ को कम करने या अन्य नियमित स्रोतों से राजस्व की कमी को पूरा करने जैसे विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये धन जुटाने हेतु विनिवेश करती है।
- रणनीतिक विनिवेश एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के स्वामित्व और नियंत्रण का किसी अन्य इकाई (ज़्यादातर निजी क्षेत्र की इकाई) को हस्तांतरण है।
  - साधारण विनिवेश के विपरीत रणनीतिक बिक्री का तात्पर्य एक प्रकार का निजीकरण है।
- वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री के लिये नोडल विभाग है।
- भारत में विनिवेश के मुख्य उद्देश्य:
  - राजकोषीय बोझ को कम करना
  - सार्वजनिक वित्त में सुधार
  - निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना
  - वित्तपोषण वृद्धि और विकास कार्यक्रम
  - बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा को बनाए रखना और बढ़ावा देना
- अत: विकल्प D सही है।

53.

उत्तर: A

व्याख्या

- 'श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय' के तहत 'श्रम ब्यूरो' ने वर्ष 2021 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) के लिये 'त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण' (QES) के परिणाम जारी किये हैं। अत: कथन 1 सही है।
- 'त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण' (QES) 'ऑल-इंडिया क्वार्टरली एस्टाब्लिशमेंट-बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे' (AQEES) का हिस्सा है।
  - इसमें कुल 9 क्षेत्रों के संगठित खंड में 10 या अधिक श्रमिकों को रोज़गार देने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं। अत: कथन 2 सही है।
  - ये 9 क्षेत्र हैं- विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं रेस्तरां, आईटी/बीपीओ और वित्तीय सेवा गतिविधियाँ। अत: कथन 3 सही नहीं है।

54.

उत्तर: A

व्याख्या:

- टैक्स हैवन आमतौर पर एक अपतटीय देश होता है जहाँ राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर वातावरण में विदेशी नागरिकों एवं व्यवसायों को बहुत कम या कोई कर नहीं देना पड़ता है। अत: कथन 1 सही है।
  - टैक्स हैवन देशों की विशेषताओं में आमतौर पर कम आय कर, सूचना की न्यूनतम रिपोर्टिंग, पारदर्शिता दायित्वों की कमी, प्रत्यक्ष उपस्थिति की आवश्यकता नहीं और टैक्स हैवन वाहनों का विपणन शामिल है।

- सामान्य तौर पर टैक्स हैवन देशों के नागरिकों और व्यवसायों को उनकी कर नीतियों का लाभ लेने के लिये निवास या व्यावसायिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- व्यक्तियों और निगमों को संभावित रूप से विदेशों में आय पर लगाए गए कम या बिना करों से लाभ हो सकता है जहाँ कानून के अनुसार कमियाँ, क्रेडिट या अन्य विशेष कर विचारों की अनुमति दी जा सकती है।

- दुनिया भर में विदेशी/अपतटीय निवेश रिपोर्टिंग के प्रवर्तन को बढ़ाने के लिये कुछ कार्यक्रम हैं।
- जी20 देशों के साथ OECD द्वारा विकसित वित्तीय खाता की सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान के लिये मानक, पारस्परिक आधार पर कर उद्देश्यों के लिये वित्तीय खाता जानकारी के स्वचालित आदान-प्रदान पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति का प्रतिनिधित्व करता है। अत: कथन 3 सही है।

55.

उत्तर: C

व्याख्या

- हाल ही में भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिये समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्त्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या 'नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्लान' लॉन्च किया है। अत: कथन 1 सही है।
- गति शक्ति योजना के तहत वर्ष 2019 में शुरू की गई 110 लाख करोड़ रुपए की 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' को समाहित किया जाएगा।

इसका लक्ष्य 11 औद्योगिक गलियारे और दो नए रक्षा गलियारे (एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में) बनाना भी है। इसके तहत सभी गाँवों में 4G कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। साथ ही गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 17,000 किलोमीटर की क्षमता जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। अत: कथन 2 सही है।

56.

उत्तर: D

व्याख्या

- हाल ही में चीन के 'राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो' ने बताया है कि मौजूदा वर्ष की तीसरी तिमाही में चीन की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि धीमी होकर 4.9% पर पहुँच गई है।
- भारत पर प्रभाव
  - आयात: चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021 के पहले नौ महीनों में लगभग 50% बढ़ा है।
    - इसके अलावा भारत स्मार्टफोन और ऑटोमोबाइल घटकों, दूरसंचार उपकरण, सक्रिय दवा सामग्री तथा अन्य रसायनों आदि के लिये भी चीन से आयात पर निर्भर है।
    - इस प्रकार चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट आने से भारत के उपभोक्ता बाज़ार और बुनियादी अवसंरचना के विकास पर असर पड़ेगा।
  - निर्यात: इसके अलावा यदि चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, तो इससे भारत के लौह अयस्क निर्यात, जिसमें से अधिकांश चीन को निर्यात होता है, पर भी प्रभाव पड़ सकता है।
  - निवेश: चीन की धीमी अर्थव्यवस्था, भारत से निवेश के बहिर्वाह को गति प्रदान कर सकती है। यदि भारत आर्थिक सुधारों में तेज़ी लाता है, तो यह अगला वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन सकता है। अत: विकल्प D सही है।

57.

उत्तर: D

व्याख्या:

- ब्रेंट क्रूड ऑयल का उत्पादन उत्तरी सागर में शेटलैंड द्वीप (Shetland Islands) और नॉर्वे के बीच तेल क्षेत्रों में होता है। अत: कथन 1 सही है।
- वेस्ट क्रूड इंटरमीडिएट (WTI) ऑयल क्षेत्र मुख्यत: अमेरिका (टेक्सास, लुइसियाना और नॉर्थ डकोटा) में अवस्थित हैं।
- आमतौर पर ब्रेंट क्रूड ऑयल के लिये शिपिंग की लागत कम होती है, क्योंकि इसका उत्पादन समुद्र के पास होता है, जिससे इसे कार्गो जहाज़ों में तुरंत लादा जा सकता है। अत: कथन 3 सही है।
- WTI कच्चे तेल की शिपिंग का मूल्य अधिक होता है क्योंकि इसका उत्पादन भूमि वाले क्षेत्रों में होता है, जहाँ भंडारण की सुविधा सीमित है।
- OPEC द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्रेंट क्रूड ऑयल मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क मूल्य (Benchmark Price) है, जबकि अमेरिकी तेल कीमतों के लिये WTI क्रूड ऑयल मूल्य एक बेंचमार्क है।
  - भारत मुख्य रूप से क्रूड ऑयल का आयात OPEC देशों से करता है, अत: भारत में तेल की कीमतों के लिये ब्रेंट बेंचमार्क है। अत: कथन 2 सही है।

58.

उत्तर: D

व्याख्या:

- हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB) के लिये कैलेंडर की घोषणा की है, जो अक्तूबर 2021 से मार्च 2022 तक चार चरणों में जारी किया जाएगा।

- सरकार ने सोने की मांग को कम करने और घरेलू बचत के एक हिस्से (जिसका उपयोग स्वर्ण की खरीद के लिये किया जाता है) को वित्तीय बचत में बदलने के उद्देश्य से नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना की शुरुआत की थी। अत: कथन 1 सही है।
- गोल्ड/स्वर्ण बॉण्ड सरकारी प्रतिभूति (GS) अधिनियम, 2006 के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किये जाते हैं।
  - ये भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं। अत: कथन 2 सही है।
  - बॉण्ड की बिक्री वाणिज्यिक बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL), नामित डाकघरों (जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है) और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के ज़रिये या तो सीधे अथवा एजेंटों के माध्यम से की जाती है। अत: कथन 3 सही है।

59.

उत्तर: A

व्याख्या:

- "ओसाका ट्रैक" एक ऐसी प्रक्रिया है जो डिजिटल अर्थव्यवस्था विशेष रूप से डेटा प्रवाह और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाने के प्रयासों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
- भारत, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया ने ओसाका में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में "डिजिटल अर्थव्यवस्था" पर "ओसाका ट्रैक" का बहिष्कार किया है, क्योंकि इसने वैश्विक व्यापार वार्ताओं में सर्वसम्मति-आधारित निर्णयों के "बहुपक्षीय" सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से कम कर दिया और विकासशील देशों में डिजिटल-औद्योगीकरण के लिये "नीतिगत स्थान" से इनकार कर दिया। अत: विकल्प A सही है।

60.

उत्तर: C

व्याख्या:

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण:

- इसकी स्थापना अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत की गई थी। अत: कथन 1 सही है।
- इसका मुख्यालय गांधीनगर (गुजरात) की गिफ्ट सिटी (GIFT City) में स्थित है। अत: कथन 2 सही है।
- इसके अंतर्गत IFSC में ऐसी सभी वित्तीय सेवाओं, उत्पादों और संस्थाओं को विनियमित किया जाएगा।
- यह केंद्र सरकार को ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों की भी सिफारिश कर सकता है जिन्हें IFSC में अनुमति दी जा सकती है।

61.

उत्तर: C

व्याख्या

- हाल ही में केंद्रीय मंत्री (विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा) ने 'इंडियन एनर्जी एक्सचेंज' के अंतर्गत एक नया बाज़ार खंड 'ग्रीन डे-अहेड मार्केट' (GDAM) लॉन्च किया है।
  - भारत दुनिया का एकमात्र बड़ा विद्युत बाज़ार है, जिसने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा हेतु 'ग्रीन डे अहेड मार्केट' (जीडीएएम) प्रारंभ किया है। अत: कथन 2 सही है।
- यह 'डे-अहेड' आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापार हेतु संचालित एक बाज़ार है।
  - नोडल एजेंसी के रूप में 'नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर' (NLDC), 'पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड' (POSOCO) ने GDAM के शुभारंभ के लिये अपेक्षित प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढाँचे की स्थापना की है।
- GDAM के साथ कोई भी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कंपनी एक्सचेंज पर नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना और बिक्री कर सकती है। अत: कथन 1 सही है।
- यह पारंपरिक 'डे-अहेड मार्केट' के साथ एकीकृत तरीके से कार्य करेगा।
  - यह एक्सचेंज अलग-अलग 'बिडिंग विंडो' के माध्यम से बाज़ार सहभागियों के लिये पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों हेतु एक साथ बिडिंग का प्रावधान प्रस्तुत करेगा।

62.

उत्तर: B

व्याख्या:

- हाल ही में मुंबई में स्वामी (सस्ते और मध्यम-आय वर्ग के आवासों के लिये विशेष विंडो) कोष के तहत एक आवासीय परियोजना को पूरा करने के लिये किये गए निवेश का पहला पूर्ण निष्कासन की घोषणा की है।
  - इसके अंतर्गत सात परियोजनाओं में 1,500 से अधिक घरों को पहले ही पूरा कर लिया गया है और हर साल कम-से-कम 10,000 घरों को पूरा करने का लक्ष्य है।
- इसका उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम बनाने और घर खरीदारों को अपार्टमेंट की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिये वित्तपोषण प्रदान करना। अत: कथन 1 सही है।

- यह एक सरकार समर्थित कोष है जिसे सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) के साथ पंजीकृत श्रेणी- II एआईएफ (वैकल्पिक निवेश कोष) ऋण कोष के रूप में वर्ष 2019 में स्थापित किया गया था। अत: कथन 2 सही है।
- एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) सीएपी वेंचर्स कोष का निवेश प्रबंधक है जो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स तथा एसबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- कोष के प्रायोजक के रूप में भारत सरकार का सचिव,आर्थिक मामलों के विभाग तथा वित्त मंत्रालय को शामिल किया गया है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

63.

उत्तर: B

व्याख्या:

- आमतौर पर पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) एक कार्टेल के रूप में काम करता था और एक अनुकूल बैंड में कीमतें तय करता था।
- ओपेक का नेतृत्व सऊदी अरब करता है, जो दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है (वैश्विक मांग का 10% अकेले ही निर्यात करता है)। अत: कथन 1 सही है।
  - ओपेक के कुल 13 देश सदस्य हैं। ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला और वेनेज़ुएला। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- ओपेक तेल उत्पादन बढ़ाकर कीमतों में कमी ला सकता है और उत्पादन में कटौती कर कीमतें बढ़ा सकता है।
- वैश्विक तेल मूल्य निर्धारण मुख्य रूप से एक अच्छी तरह से काम करने वाली प्रतिस्पर्द्धा के बजाय वैश्विक तेल निर्यातकों के बीच साझेदारी पर निर्भर करता है।
- OPEC द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्रेंट क्रूड ऑयल मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क मूल्य है, जबकि अमेरिकी तेल कीमतों के लिये WTI क्रूड ऑयल मूल्य एक बेंचमार्क है। अत: कथन 3 सही है।

64.

उत्तर: C

व्याख्या:

- FATF, वर्ष 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित एक अंतर-सरकारी निकाय है।
  - यह किसी देश के धन-शोधन-विरोधी और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण ढाँचे की ताकत का आकलन करता है, हालाँकि यह व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है।
- इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) मुख्यालय में स्थित है। अत: कथन 1 सही है।
- सदस्य देश:
  - FATF में वर्तमान में 39 सदस्य हैं जिनमें दो क्षेत्रीय संगठन - यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल हैं। भारत FATF का सदस्य है। अत: कथन 2 सही है।

65.

उत्तर: A

व्याख्या:

- भारत ने वर्ष 1998 में 'अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (ILO) के 'एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन (1964) की पुष्टि की, जिसके तहत अनुसमर्थन करने वाले देशों को 'पूर्ण, उत्पादक और स्वतंत्र रूप से चुने गए रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये डिज़ाइन की गई एक सक्रिय नीति' को लागू करने की आवश्यकता है। ज्ञात हो कि भारत के पास अभी तक कोई 'राष्ट्रीय रोज़गार नीति' (NEP) नहीं है। अत: कथन 1 सही है।
- 'त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण' (QES) में कम-से-कम 10 श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों को ही शामिल किया गया है, इस प्रकार यह केवल औपचारिक अर्थव्यवस्था संबंधित डेटा ही प्रदान करता है।
  - यह देखते हुए कि अनौपचारिक श्रमिक (बिना लिखित अनुबंध के) भारत में श्रम शक्ति का लगभग 90% हिस्सा हैं, 'त्रैमासिक रोज़गार सर्वेक्षण' इस प्रकार श्रम बाज़ार की केवल एक आंशिक तस्वीर प्रदान करता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

66.

उत्तर: D

व्याख्या:

- GI एक संकेतक है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों की पहचान करने हेतु किया जाता है। अत: कथन 1 सही है।
- इसका उपयोग कृषि, प्राकृतिक और निर्मित वस्तुओं के लिये किया जाता है।
- 'माल भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999' भारत में माल के संबंध में भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण एवं अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
- यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं (TRIPS) का भी एक हिस्सा है। अत: कथन 2 सही है।
- इसे भौगोलिक संकेतकों के रजिस्ट्रार पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक द्वारा प्रसाशित किया जाता है। अत: कथन 3सही है।

67.

उत्तर: D

व्याख्या

- यह अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है, जिन्हें अंतिम उपयोगकर्त्ता द्वारा खरीदा जाता है और एक निश्चित अवधि में किसी देश में उत्पादन किया जाता है।
- जीडीपी के आँकड़े बताते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास के चार इंजनों की क्या स्थिति है। ये चार इंजन हैं:
  - निजी अंतिम उपभोग व्यय (C)
  - निवेश (I)
  - सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (G)
  - शुद्ध निर्यात" (NX) (निर्यात-आयात)
- GDP = C + I + G + NX अत: विकल्प D सही है।

68.

उत्तर: A

व्याख्या:

- बेसल III मानदंड एक अंतर्राष्ट्रीय नियामक समझौता है जिसने वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद बैंकिंग क्षेत्र के भीतर विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंधन में सुधार के लिये डिज़ाइन किये गए सुधारों का एक सेट पेश किया।
  - बेसल- III मानदंडों के तहत बैंकों को पूंजी का एक निश्चित न्यूनतम स्तर बनाए रखने के लिये कहा गया था और उन्हें जमा से प्राप्त होने वाले सभी धन को उधार नहीं देने के लिये कहा गया था।
- बेसल- III मानदंडों के अनुसार, बैंकों की नियामक पूंजी को टियर-1 और टियर-2 में बाँटा गया है, जबकि टियर-1 को कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET-1) और अतिरिक्त टियर-1 (AT-1) पूंजी में विभाजित किया गया है। अत: विकल्प A सही है।

69.

उत्तर: D

व्याख्या

- 'AT1 बॉण्ड' जिसे 'परपेचुअल बॉण्ड'(Perpetual Bond) भी कहा जाता है, की कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है, किंतु इनमें कॉल विकल्प होता है। ऐसे बॉण्ड के जारीकर्त्ता बॉण्ड को कॉल या रिडीम कर सकते हैं यदि उन्हें सस्ती दर पर पैसा मिल रहा है, खासकर तब जब ब्याज दरें गिर रही हों।
  - ये बैंकों और कंपनियों द्वारा जारी किये गए किसी भी अन्य बॉण्ड्स की तरह ही हैं, लेकिन अन्य बॉण्डों की तुलना में इनमें थोड़ी अधिक ब्याज़ दर का भुगतान किया जाता है।
  - बैंक ये बॉण्ड 'बेसल-III' मानदंडों को पूरा करने के उद्देश्य से अपने मूल पूंजी आधार को बढ़ाने के लिये जारी करते हैं। अत: कथन 2 सही है।
  - ये बॉण्ड भी सूचीबद्ध होते हैं और एक्सचेंजों पर इन्हें खरीदा या बेचा जाता है। इसलिये यदि किसी 'AT1' बॉण्डधारक को पैसे की ज़रूरत है, तो वह इसे सेकेंडरी मार्केट में बेच सकता है।
  - निवेशक इन बॉण्ड्स को जारीकर्त्ता बैंक को वापस नहीं कर सकते हैं यानी इसके धारकों के लिये कोई 'पुट ऑप्शन' उपलब्ध नहीं है।
  - 'AT-1' बॉण्ड जारी करने वाले बैंक किसी विशेष वर्ष के लिये ब्याज भुगतान को रोक भी सकते हैं या बॉण्ड के अंकित मूल्य को भी कम कर सकते हैं। अत: कथन 3 सही है।
- 'एडिशनल टियर-1' (AT1) बॉण्ड भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित किये जाते हैं। यदि रिज़र्व बैंक को लगता है कि किसी बैंक को बचाव की ज़रूरत है, तो वह बैंक को अपने निवेशकों से परामर्श किये बिना अपने बकाया AT-1 बॉण्ड को 'बट्टे खाते में डालने' (Write Off) के लिये कह सकता है। अत: कथन 1 सही है।

70.

उत्तर: B

व्याख्या:

- हाल ही में वित्त मंत्री ने वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (FSDC) की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की।
  - FSDC वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर-सांविधिक/गैर-वैधानिक शीर्ष परिषद है तथा इसकी स्थापना वर्ष 2010 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- FSDC की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर गठित रघुराम राजन समिति (2008) द्वारा किया गया था। अत: कथन 2 सही है।
  - इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है तथा इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामकों (RBI, SEBI, PFRDA और IRDA) के प्रमुख, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हैं।
- वर्ष 2018 में, सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के ज़िम्मेदार राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) के अध्यक्ष तथा राजस्व सचिव को शामिल करने के उद्देश्य से FSDC का पुनर्गठन किया।

- FSDC उप-समिति की अध्यक्षता RBI के गवर्नर द्वारा की जाती है।
- आवश्यकता पड़ने पर यह परिषद विशेषज्ञों को भी अपनी बैठक में आमंत्रित कर सकती है।

71.

उत्तर: B

व्याख्या:

- क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है जिसे क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जिसके कारण इसका जाली रूप बनाना लगभग असंभव हो जाता है।
  - उधार देना और उधार लेना क्रिप्टोकरेंसी द्वारा दी जाने वाली वैकल्पिक सेवाएँ हैं।
- निवेशक डिजिटल करेंसी की अपनी होल्डिंग्स पर ब्याज अर्जित कर सकते हैं, अक्सर वे बैंक में नकद जमा पर बहुत अधिक या ऋण वापस करने के लिये क्रिप्टो के साथ संपार्श्विक के रूप में उधार लेते हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - कानून के अनुसार, बैंकों के लिये नकद रिज़र्व रखना आवश्यक होता है ताकि यदि कुल ऋण में से कुछ बैड लोन में परिवर्तित भी हो जाए तो यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक अपना धन निकाल सकें, जबकि क्रिप्टो बैंकों के पास इस प्रकार का कोई भी रिज़र्व नहीं होता है और वे जिन संस्थानों को उधार देते हैं उनमें जोखिमपूर्ण गतिविधियों की संभावना रहती है।
- इस प्रकार के जमा की गारंटी केंद्रीय बैंक के समर्थित जमा बीमा निगम द्वारा नहीं दी जाती है। साइबर हमले, बाज़ार की प्रतिकूल स्थिति या अन्य परिचालन या तकनीकी कठिनाइयों के कारण निकासी या स्थानांतरण पर अस्थायी या स्थायी रोक लग सकती है।
- स्टेबलकॉइन: स्टेबल करेंसी वह क्रिप्टोकरेंसी है जो आमतौर पर डॉलर से जुड़ी होती है। वे ब्लॉकचेन लेन-देन हेतु डिजिटल रूप में सरकार द्वारा जारी धन का स्थिर मूल्य प्रदान करने के लिये हैं, लेकिन निजी संस्थाओं द्वारा जारी किये जाते हैं। अत: कथन 2 सही है।

72.

उत्तर: B

व्याख्या:

सतत्ख विकास लक्ष्य (SDG) 12 के बारे में:

- सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 12 का उद्देश्य विश्व में हर जगह संवहनीय/सतत् खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना है।
- सतत् खपत और उत्पादन से तात्पर्य "सेवाओं एवं संबंधित उत्पादों के उपयोग से है, जो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं तथा प्राकृतिक संसाधनों और भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को खतरे में न डालते हुए विषाक्त पदार्थों के उपयोग में कमी के साथ-साथ जीवन चक्र पर अपशिष्ट और प्रदूषकों के उत्सर्जन के प्रभाव को कम करते हैं।
- SDG 12 के लक्ष्य
  - प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना और वर्ष 2030 तक प्राकृतिक संसाधनों के कुशल और टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करना।
  - प्रदूषण को समाप्त करना, समग्र अपशिष्ट उत्पादन को कम करना और रसायनों एवं ज़हरीले कचरे के प्रबंधन में सुधार करना।
  - हरित बुनियादी ढाँचे और प्रथाओं को व्यवहार में लाने के लिये कंपनियों के बीच तालमेल का समर्थन करना।
  - यह सुनिश्चित करना कि हर जगह हर किसी को प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के तरीकों से पूरी तरह से अवगत कराया जाए और अंतत: उद्देश्यपूर्ण तरीकों को अपनाया जाए। अत: विकल्प B सही है।

73.

उत्तर: C

व्याख्या:

- निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) भारत में निर्यात बढ़ाने में मदद करने हेतु जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के लिये पूरी तरह से स्वचालित मार्ग है। अत: कथन 1 सही है।
  - ITC कच्चे माल, उपभोग्य सामग्रियों, वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर दिये जाने वाले कर पर प्रदान किया जाता है जिसका उपयोग वस्तुओं या सेवाओं के निर्माण में किया जाता था। यह दोहरे कराधान और करों के व्यापक प्रभाव से बचने में मदद करता है।
- इसे जनवरी 2021 में MEIS जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं था, के स्थान पर शुरू किया गया था। RoDTEP योजना सुनिश्चित करती है कि भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अनुरूप बना रहे। अत: कथन 2 सही है।
  - विभिन्न क्षेत्रों के लिये टैक्स रिफंड दरें 0.5% से 4.3% तक होती हैं।
  - छूट का दावा माल ढुलाई के प्रतिशत के रूप में निर्यात की बोर्ड वेल्यू पर करना होगा।

74.

उत्तर: D

व्याख्या:

- हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने अक्तूबर-दिसंबर 2020 के लिये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) का त्रैमासिक बुलेटिन जारी किया।
  - यह डेटासेट आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट से अलग है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है। शहरी क्षेत्रों के लिये बेरोज़गारी के आँकड़े त्रैमासिक आधार पर जारी किये जाते हैं। अत: कथन 3 सही है।
    - अधिक नियत समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की शुरुआत की। अत: कथन 1 सही है।
- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): LFPR को कुल आबादी में श्रम बल के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों (अर्थात् कार्यरत या काम की तलाश में या काम के लिये उपलब्ध) के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।
  - कामगार-जनसंख्या अनुपात (WPR): WPR को कुल आबादी में रोज़गार प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

75.

उत्तर: D

व्याख्या:

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों को मंज़ूरी दी है। इनमें से कुछ सुधार निम्नलिखित हैं:
- स्पेक्ट्रम संबंधी सुधार:
  - स्पेक्ट्रम की नीलामी सामान्यत: प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही (फिक्स्ड कैलेंडर) में आयोजित की जाएगी।
  - भविष्य में स्पेक्ट्रम की नीलामी मौजूदा 20 वर्ष के बजाय 30 वर्ष की अवधि हेतु की जाएगी। अत: कथन 2 सही है।
- AGR का युक्तिकरण:
  - AGR को पहले कंपनी के मुख्य दूरसंचार व्यवसाय से जुड़े होने के बजाय सभी राजस्व पर आधारित होने के रूप में व्याख्यायित किया गया था।
  - सरकार ने स्वीकार किया है कि यह व्याख्या समस्याग्रस्त थी, जिससे कंपनियों पर भविष्य का वित्तीय बोझ कम होगा।
  - दूरसंचार कंपनियों को सरकार को वैधानिक शुल्क के रूप में AGR (गैर-दूरसंचार राजस्व को छोड़कर) का एक पूर्व-निर्धारित प्रतिशत का भुगतान करना पड़ता है। अत: कथन 3 सही है।
- FDI सुधार:
  - इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को 49% की मौजूदा सीमा को स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक की अनुमति दी गई है। अत: कथन 1 सही है।

76.

उत्तर: B

व्याख्या:

- बैड बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (Asset Reconstruction Company-ARC) या परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (Asset Management Company-AMC) है जो वाणिज्यिक बैंकों के बैड ऋणों को अपने नियंत्रण में लेकर उनका प्रबंधन और निर्धारित समय पर धन की वसूली करती है। अत: कथन 1 सही है।
- बैड बैंक ऋण देने और जमा स्वीकार करने की प्रकिया का भाग नहीं होता है, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट ठीक करने में मदद करता है। अत: कथन 2 सही है।
- बैड लोन का अधिग्रहण आमतौर पर ऋण के बुक वैल्यू से कम होता है और बैड बैंक बाद में जितना संभव हो उतना वसूल करने की कोशिश करता है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

77.

उत्तर: D

व्याख्या

- 'पर्याप्त अर्थव्यवस्था दर्शन' (SEP) थाईलैंड की संस्कृति के मूल सिद्धांतों पर आधारित है।
- थाईलैंड का मानना है कि 'पर्याप्त अर्थव्यवस्था दर्शन' (SEP) का उसका घरेलू विकास दृष्टिकोण 'सतत् विकास लक्ष्यों' (SDGs) को प्राप्त करने हेतु एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में काम कर सकता है।
- यह विकास के लिये एक अभिनव दृष्टिकोण है, जिसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं और स्थितियों के लिये एक व्यावहारिक अनुप्रयोग के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
  - यह थाईलैंड की 'मौलिक प्रशासन नीति' का भी हिस्सा है।
  - इसे वर्ष 1997 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद थाईलैंड द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

- यह एक ऐसा दर्शन है, जो बाह्य झटकों से स्वयं को प्रतिरक्षित करने हेतु आंतरिक मार्गदर्शन करता है और इसे किसी भी स्थिति एवं किसी भी स्तर पर लागू किया जा सकता है। अत: विकल्प D सही है।

78.

उत्तर: D

व्याख्या:

- विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते के तहत सब्सिडी को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:
  - ग्रीन बॉक्स:
    - इसके अंतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी सामान्यत: व्यापार में या तो विकृति उत्पन्न करती नहीं है या फिर न्यूनतम विकृति उत्पन्न करती है।
    - इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, स्थानीय विकास कार्यक्रमों, अनुसंधान, आपदा राहत इत्यादि हेतु सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता को शामिल किया जाता है
    - इसलिये ग्रीन बॉक्स सब्सिडी पर प्रतिबंध नहीं होता है, बशर्ते यह नीति-विशिष्ट मानदंडों के अनुरूप हो।
  - अंबर बॉक्स:
    - इसके अंतर्गत ब्लू एवं ग्रीन बॉक्स के अलावा वे सभी सब्सिडियाँ आती हैं जो कृषि उत्पादन एवं व्यापार को विकृत करती हैं।
    - इस सब्सिडी में सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण तथा कृषि उत्पादों की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता आदि को शामिल किया जाता है।
  - ब्लू बॉक्स:
    - यह "शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स"(Amber Box With Conditions) है। इसे एसी स्थितियों में कमी लेन हेतु डिज़ाइन किया गया है जो व्यापार में विकृति उत्पन्न करती हैं।
    - आम तौर पर एम्बर बॉक्स में शामिल उस सब्सिडी को नीले बॉक्स में रखा जाता है जिसे प्राप्त करने के लिये किसानों को अपना उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है।
  - डवलपमेंट बॉक्स:
    - कृषि समझौता विकासशील देशों को घरेलू सहायता प्रदान करने में अतिरिक्त लचीलेपन कीअनुमति देता है।
    - सब्सिडी के प्रकार जो विकासात्मक श्रेणी में फिट होते हैं, सहायता के उपाय हैं, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने हेतु डिज़ाइन किएये गए हो जो विकासशील देशों के विकास कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग हैं। अत: विकल्प D सही है।

79.

उत्तर: C

व्याख्या:

- हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने देश में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिये ज़िला स्तरीय समितियों के गठन का आदेश जारी किया है।
  - सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को विद्युत मंत्रालय को सूचित करते हुए इन ज़िला विद्युत समितियों की स्थापना को अधिसूचित और सुनिश्चित करना होगा।
  - यह सरकार की सभी विद्युत संबंधी योजनाओं और लोगों को सेवाओं के प्रावधान पर इसके प्रभाव की निगरानी करेगा। इसकी तीन माह में कम-से-कम एक बार ज़िला मुख्यालय पर बैठक होगी। अत: कथन 3 सही है।
- भारत का विद्युत् क्षेत्र दुनिया के सबसे विविध क्षेत्रों में से एक है। विद्युत उत्पादन के स्रोत पारंपरिक स्रोतों जैसे- कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा से लेकर पवन, सौर एवं कृषि तथा घरेलू कचरे जैसे व्यवहार्य गैर-पारंपरिक स्रोतों तक हैं।
- भारत दुनिया में विद्युत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- विद्युत क्षेत्र में स्वत: मार्ग के तहत 100% एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की अनुमति है। अत: कथन 2 सही है।
- विद्युत समवर्ती सूची का विषय है (संविधान की सातवीं अनुसूची)। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - विद्युत मंत्रालय देश में विद्युत ऊर्जा के विकास हेतु प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है।
  - यह विद्युत अधिनियम, 2003 और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 का प्रशासन करता है।

80.

उत्तर: C

व्याख्या:

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) का एक उन्नत संस्करण है, जो कैशलेस भुगतान को तेज़ और आसान बनाने के लिये चौबीस घंटे सक्रिय फंड ट्रांसफर सेवा है। अत: कथन 1 सही नहीं है।

- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने वर्ष 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ UPI को लॉन्च किया।

- NEFT एक राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है जो "वन-टू-वन" धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है।
  - NEFT का उपयोग करके हस्तांतरित की जा सकने वाली धनराशि की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। अत: कथन 2 सही है।
- RuPay एक NPCI संचालित भुगतान प्रणाली है।
  - यह भारत का अपनी तरह का पहला घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क है, जिसे पूरे भारत में एटीएम, पीओएस उपकरणों और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर व्यापक स्वीकृति प्राप्त है।
  - इस कार्ड का उपयोग सिंगापुर, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और सऊदी अरब में लेन-देन के लिये भी किया जा सकता है। अत: कथन 3 सही है।

81.

उत्तर: D

व्याख्या:

- हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2021 रैंकिंग में भारत की स्थिति में दो स्थानों का सुधार हुआ है तथा भारत 46वें स्थान पर आ गया है।
- सूचकांक विश्व अर्थव्यवस्थाओं को उनकी नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंक प्रदान करता है जिसमें लगभग 80 संकेतक शामिल होते हैं तथा इन्हें इनोवेशन इनपुट (Innovation Inputs) और आउटपुट (Outputs) में समूहीकृत किया जाता है।
  - इनोवेशन इनपुट: संस्थान, मानव पूंजी और अनुसंधान, आधारभूत संरचना, बाज़ार कृत्रिमता (Market sophistication), व्यावसायिक विशेषज्ञता।
  - इनोवेशन आउटपुट: ज्ञान और प्रौद्योगिकी रचनात्मकता। अत: विकल्प D सही है।
  - रैंकिंग में शीर्ष पाँच देश : स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, अमेरिका और यू.के. नवाचार रैंकिंग में लगातार शीर्ष पर बने हुए हैं, ये देश पिछले तीन वर्षों से शीर्ष 5 में शामिल हैं।
    - कोरिया गणराज्य वर्ष 2021 में पहली बार GII के शीर्ष 5 देशों की सूची में शामिल हुआ है।
- एशियाई देश: चार एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ शीर्ष 15 में शामिल हैं जिनमें सिंगापुर (8), चीन (12), जापान (13) और हॉन्गकॉन्ग (14) शामिल हैं।

82.

उत्तर: B

व्याख्या:

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) में पूंजी लगाने और इनिशियल पब्लिक ऑफर के द्वारा इसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने को मंजूरी दी है।
- सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 से पाँच वर्षों में ECGC में 4,400 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई जाएगी।
- ECGC लिमिटेड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व में है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - वर्ष 1957 के प्रारंभ में भारत सरकार द्वारा निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना की थी।
  - वर्ष 1962-64 की अवधि के दौरान बैंकों को बीमा कवर की शुरुआत के 1 वर्ष बाद इसका नाम परिवर्तित कर एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया।
  - अगस्त 2014 में इसे बदलकर ECGC लिमिटेड कर दिया गया।
- उद्देश्य: ECGC की स्थापना वाणिज्यिक और राजनीतिक कारणों से विदेशी खरीदारों द्वारा गैर-भुगतान जोखिमों के खिलाफ निर्यातकों को ऋण बीमा सेवाएँ प्रदान करके निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
- पूंजी प्रवाह इसे निर्यात-उन्मुख उद्योगों, विशेष रूप से श्रम-केंद्रित क्षेत्रों में अपने कवरेज का विस्तार करने में मदद करेगा।
  - निर्यात ऋण बीमा बाजार में लगभग 85% बाजार हिस्सेदारी के साथ ECGC भारत में एक मार्केट लीडर है जो वित्त वर्ष 2021 में 6.02 लाख रुपए या 28% व्यापार निर्यात में सहायता प्रदान करता है।
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) ECGC के ग्राहक बाज़ार में 97% हिस्सेदारी साझा करते हैं। अत: कथन 2 सही है।
  - ECGC को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है ताकि वह और फंड जुटाया जा सके।
- भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम ने ऋण की उपलब्धता बढ़ाने और ऋण देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिये निर्यात ऋण बीमा योजना (ECIS) की शुरुआत की है जिसे निर्विक (निर्यात ऋण विकास योजना) कहा जाता है। अत: कथन 3 सही है।

83.

उत्तर: D

व्याख्या:

- हाल ही में असम की जुडिमा (Judima) वाइन राइस, भौगोलिक संकेतक (GI) टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर में पहली पारंपरिक शराब बन गई है।
  - जुडिमा, असम की डिमासा जनजाति द्वारा घरेलू/स्थानीय चावल से निर्मित शराब है।
  - यह जीआई टैग प्राप्त करने वाला कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ के पहाड़ी ज़िलों का दूसरा उत्पाद है।
- जुडिमा, चिपचिपा चावल या स्टिकी राइस (बोरा नामक चिपचिपा चावल) से निर्मित शराब है, जिसमें उबले हुए और पारंपरिक जड़ी बूटियों को मिश्रित किया जाता है जिसे थेम्ब्रा [Thembra (Acacia pennata)] कहा जाता है।
  - यह शराब राज्य (असम) की डिमासा जनजाति की विशेषता है और इसका एक विशिष्ट मीठा स्वाद है जिसे तैयार करने में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है तथा इसे वर्षों तक संग्रहीत किया जा सकता है। अत: विकल्प D सही है।

84.

उत्तर: C

व्याख्या:

- मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (NEIA) योजना को जारी रखने और पाँच वर्षों में 1,650 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान को भी मंजूरी दी।
- राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (NEIA) योजना:
  - NEIA ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2006 में रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्त्व के दृष्टिकोण से भारत से परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिये की गई थी।
  - राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (NEIA), ECGC द्वारा मध्यम और दीर्घकालिक (एमएलटी)/परियोजना को (आंशिक/पूर्ण) सहायता देकर निर्यात को बढ़ावा देता है। अत: कथन 1 सही है।
- एक्ज़िम बैंक ने अप्रैल 2011 में ECGC लिमिटेड के साथ मिलकर NEIA योजना के तहत एक नई पहल की शुरुआत की अर्थात् बायर्स क्रेडिट, जिसके तहत बैंक भारत से परियोजना निर्यात हेतु वित्त और अन्य सुविधाएँ प्रदान करता है। अत: कथन 2 सही है।
  - बायर्स क्रेडिट अद्वितीय क्रेडिट सुविधा कार्यक्रम है जो भारतीय निर्यातकों को नए भौगोलिक क्षेत्रों का पता लगाने के लिये प्रेरित करता है।
  - इस कार्यक्रम के माध्यम से विदेशी खरीदार भारतीय निर्यातक के पक्ष में एक "लेटर ऑफ क्रेडिट" खोल सकता है और आस्थगित भुगतान शर्तों पर भारत से सामान एवं सेवाओं का आयात कर सकता है।

85.

उत्तर: D

व्याख्या:

- भारत और सिंगापुर के केंद्रीय बैंक "त्वरित, कम लागत, सीमा पार से फंड ट्रांसफर" हेतु अपने संबंधित फास्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम - यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और 'पेनाऊ' (PayNow) को लिंक करेंगे।
  - लिंकेज को जुलाई 2022 तक चालू करने का लक्ष्य है।
  - यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)- पेनाऊ(PayNow) लिंकेज भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार भुगतान हेतु बुनियादी ढाँचे के विकास में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- लिंकेज एनपीसीआई इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (NIPL) एवं नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (एनईटीएस, सिंगापुर) के पूर्व के प्रयासों पर आधारित है, जो भारत और सिंगापुर के मध्य कार्ड तथा क्यूआर कोड का उपयोग कर भुगतान की सीमा पार अंतर-संचालनीयता को बढ़ावा देता है और दोनों देशों के मध्य व्यापार, यात्रा व प्रेषण को बढ़ावा देगा।
  - यह पहल भुगतान प्रणाली विज़न दस्तावेज़ 2019-21(Payment Systems Vision Document 2019-21) में उल्लिखित सीमा पार प्रेषण हेतु गलियारों और शुल्कों की समीक्षा करने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप है। अत: विकल्प D सही है।

86.

उत्तर: A

व्याख्या:

- हाल ही में भारत के कृषि मंत्री ने जी-20 कृषि मंत्रियों के सम्मेलन को आभासी (Virtual) रूप से संबोधित किया।
  - यह अक्तूबर 2021 में इटली द्वारा आयोजित किये जाने वाले G-20 लीडर्स समिट 2021 के हिस्से के रूप में संपन्न होने वाली मंत्रिस्तरीय बैठकों में से एक है।
- G20 कृषि मंत्रियों ने "फ्लोरेंस सस्टेनेबिलिटी चार्टर" (Florence Sustainability Charter) नामक एक अंतिम वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये।
  - यह जानकारी साझा करने और स्थानीय ज़रूरतों के अनुकूल आंतरिक उत्पादन क्षमता विकसित करने में मदद हेतु खाद्य एवं कृषि पर जी-20 सदस्यों तथा विकासशील देशों के बीच सहयोग को मज़बूत करेगा, इस प्रकार यह कृषि व ग्रामीण समुदायों के बीच लचीलेपन एवं रिकवरी में योगदान देगा। अत: विकल्प A सही है।

87.

उत्तर: D

व्याख्या:

- नीति आयोग के मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के तेल आयात बिल, ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को कम करना और कोयला भंडार और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट को मेथनॉल में परिवर्तित करना है।
- इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में BHELने 1.2 टीपीडी फ्लुइडाइज्ड बेड गैसीफायर का उपयोग कर उच्च राख वाले भारतीय कोयले से 0.25 टीपीडी (टन प्रति दिन) मेथनॉल बनाने की सुविधा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है।
- मेथनॉल एक कम कार्बन, हाइड्रोजन वाहक ईंधन है जो उच्च राख कोयले, कृषि अवशेषों, थर्मल पावर प्लांटों से CO_2 और प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। COP-21 (पेरिस समझौता) हेतु भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिये यह सबसे अच्छा मार्ग है। अत: विकल्प D सही है।

88.

उत्तर: B

व्याख्या:

- डिजिटल पेमेंट हेतु यह एक कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीका है। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया (QR) कोड या एसएमएस स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर है, जो उपयोगकर्त्ताओं के मोबाइल पर भेजा जाता है।
  - उपयोगकर्त्ता कार्ड, डिजिटल भुगतान एप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस की आवश्यकता के बिना इस वाउचर को भुनाने में सक्षम होंगे।
  - यह सेवाओं के प्रायोजकों को बिना किसी भौतिक इंटरफेस के डिजिटल मोड में लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं के साथ जोड़ता है।
  - तंत्र यह भी सुनिश्चित करता है कि लेन-देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए।
  - सिस्टम प्री-पेड प्रकृति का है और इसलिये किसी भी मध्यस्थ के बिना सेवा प्रदाता को समय पर भुगतान का आश्वासन देता है।
- वास्तव में ई-रूपी अभी भी मौजूदा भारतीय रुपए द्वारा समर्थित है क्योंकि अंतर्निहित परिसंपत्ति और इसके उद्देश्य की विशिष्टता इसे एक आभासी मुद्रा से अलग बनाती है तथा इसे वाउचर-आधारित भुगतान प्रणाली के करीब रखती है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- इससे कल्याण सेवाओं की लीक-प्रूफ डिलीवरी (Leak-Proof Delivery) सुनिश्चित होने की उम्मीद है और इसका उपयोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उर्वरक सब्सिडी आदि योजनाओं के तहत मातृ एवं बाल कल्याण योजनाओं, दवाओं व निदान के तहत दवाएँ तथा पोषण सहायता प्रदान करने हेतु योजनाओं के तहत सेवाएँ देने के लिये भी किया जा सकता है। अत: कथन 2 सही है।
- यहाँ तक कि निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारी कल्याण और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में इन डिजिटल वाउचर का लाभ उठा सकता है। अत: कथन 3 सही है।

89.

उत्तर: D

व्याख्या:

- वस्त्र क्षेत्र हेतु 'उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन' योजना का उद्देश्य उच्च मूल्य वाले मानव निर्मित फाइबर (MMF) कपड़े, वस्त्र और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - 5 वर्ष की अवधि में इस क्षेत्र को उत्पादन पर 10,683 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- वस्त्र और वस्त्र उद्योग श्रम प्रधान क्षेत्र है जो भारत में 45 मिलियन लोगों को रोज़गार देता है, रोज़गार के मामले में इस क्षेत्र का कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा स्थान है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

90.

उत्तर : B

व्याख्या:

- अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- अनुसूचित बैंक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिये बैंक की चुकता पूंजी और जुटाई गई धनराशि कम-से-कम 5 लाख रुपए होनी चाहिये। अत: कथन 2 सही है।
- अनुसूचित बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से कम ब्याज वाले ऋण और समाशोधन गृहों में सदस्यता के लिये उत्तरदायी हैं।
- राष्ट्रीयकृत, अंतर्राष्ट्रीय, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत आते हैं। अत: कथन 3 सही है।

91.

उत्तर: B

व्याख्या:

- सकल मूल्यवर्द्धित (GVA) यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों (जैसे कृषि, बिजली आदि) में कितना मूल्य जोड़ा गया (धन के संदर्भ में)।

- यह बताता है कि कौन से विशिष्ट क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और कौन से मूल्यवर्द्धन हेतु संघर्ष कर रहे हैं।

- GDP और GVA के मध्य अंतर:
  - कुल मांग या कुल आपूर्ति को मापने की तुलना में कुल उत्पादन समान होना चाहिये।
    - हालाँकि हर अर्थव्यवस्था में एक सरकार होती है, जो कर लगाती है और सब्सिडी भी प्रदान करती है।
  - GDP को GAV से प्राप्त डेटा और विभिन्न उत्पादों पर लगने वाले करों को जोड़कर तथा सभी उत्पादों पर मिलने वाली सब्सिडी को घटाकर प्राप्त किया जाता है।
    - दूसरे शब्दों में GDP = (GVA) + (सरकार द्वारा अर्जित कर) - (सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी)। अत: विकल्प 2 सही है।
  - इन दो निरपेक्ष मूल्यों के बीच का अंतर सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में बताता है।
    - अगर सरकार सब्सिडी पर खर्च की तुलना में करों से अधिक राजस्व अर्जित करती है, तो सकल घरेलू उत्पाद GVA से अधिक होगा। अत: कथन 1 सही नहीं है।
    - दूसरी ओर, यदि सरकार अपने कर राजस्व से अधिक सब्सिडी प्रदान करती है, तो GVA का पूर्ण स्तर सकल घरेलू उत्पाद के पूर्ण स्तर से अधिक होगा।

92.

उत्तर: C

व्याख्या:

- MPS (जिसे फ्री फ्लोट भी कहा जाता है) नियम के लिये भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उनके इक्विटी शेयरों का कम-से-कम 25% गैर-प्रवर्तकों, अर्थात् जनता के पास है। अत: कथन 1 सही है।
- सार्वजनिक शेयरधारक व्यक्तिगत या वित्तीय संस्थान हो सकते हैं और वे आमतौर पर सार्वजनिक पेशकश या द्वितीयक बाज़ारों के माध्यम से शेयरों की खरीद करते हैं।अत: कथन 2 सही है।
- न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की अवधारणा सूचीबद्ध कंपनियों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने हेतु पेश की गई थी।
  - वर्ष 2010 में सेबी ने निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिये 25% सार्वजनिक फ्लोट पर ज़ोर देने हेतु प्रतिभूति अनुबंध विनियमन नियमों में संशोधन किया।
- भारत में औसत प्रमोटर होल्डिंग (Promoter Holding) वैश्विक स्तर पर सबसे ज़्यादा है।
  - वर्ष 2019-20 के बजट में सरकार ने न्यूनतम सार्वजनिक फ्लोट (Minimum Public Float) को 25% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव किया था।

93.

उत्तर: D

व्याख्या

- सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत अप्रैल 1992 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
  - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाज़ार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना है।
- अप्रैल 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी बाज़ार के नियामक के रूप में किया गया था।
  - प्रारंभ में सेबी एक गैर-वैधानिक निकाय था जिसे किसी भी तरह की वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी।
  - सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से यह एक स्वायत्त निकाय बना तथा इसे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।
- सेबी एक अर्ध-विधायी और अर्ध-न्यायिक निकाय भी है जो विनियमों का मसौदा तैयार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, नियम पारित कर सकता है तथा जुर्माना लगा सकता है।
- यह तीन श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कार्य करता है-
  - जारीकर्त्ता- एक बाज़ार उपलब्ध कराके जिसमें जारीकर्त्ता अपना वित्त बढ़ा सकते हैं।
  - निवेशक- सही और सटीक जानकारी की आपूर्ति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करके।
  - मध्यवर्ती/बिचौलिये- बिचौलियों के लिये एक प्रतिस्पर्द्धी पेशेवर बाज़ार को सक्षम करके। अत: विकल्प D सही है।

94.

उत्तर: C

व्याख्या:

- पूंजीगत लाभ एक पूंजीगत संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को संदर्भित करता है और इसे तब महसूस किया जाता है जब संपत्ति बेची जाती है। यह वृद्धि या लाभ 'आय' की श्रेणी में आता है।
- इसलिये उस वर्ष में उस राशि के लिये पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना आवश्यक होगा जिसमें पूंजीगत संपत्ति का हस्तांतरण होता है। इसे पूंजीगत लाभ कर कहा जाता है, जो अल्पकालिक या दीर्घकालिक दोनों हो सकता है। अत: कथन 1 सही है।
  - दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर: यह एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई संपत्ति की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर लगाया जाता है। कर देने वाले वर्गों (Tax Bracket) के आधार पर ये दरें 0%, 15% या 20% हैं।

- लघु अवधि पूंजीगत लाभ कर: यह एक वर्ष या उससे कम समय के लिये रखी गई संपत्ति पर लागू होता है और सामान्य आय के रूप में कर लगाया जाता है।

- पूंजीगत हानियों को घटाकर पूंजीगत लाभ को कम किया जा सकता है, जो तब होता है जब एक कर योग्य संपत्ति को मूल खरीद मूल्य से कम पर बेचा जाता है। कुल पूंजीगत लाभ में से किसी भी पूंजीगत हानि को घटाकर "शुद्ध पूंजीगत लाभ" के रूप में जाना जाता है। अत: कथन 2 सही है।
- पूंजीगत परिसंपत्ति संपत्ति के महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं जैसे कि घर, कार, निवेश संपत्तियाँ, स्टॉक, बॉण्ड और यहाँ तक कि संग्रहणता (Collectibles) या कला।

95.

उत्तर: C

व्याख्या:

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण

- केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के तहत 'राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण' (NCLT) का गठन किया था। अत: कथन 1 सही है।
  - यह भारत में पंजीकृत कंपनियों को नियंत्रित करने हेतु एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है और इसने 'कंपनी लॉ बोर्ड' का स्थान लिया है।
- यह नागरिक प्रक्रिया संहिता में निर्धारित नियमों से बाध्य है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है, साथ ही यह अधिनियम के अन्य प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन है। अत: कथन 2 सही है।
- राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत 'राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण' (NCLT) के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिये किया गया था।
  - NCLAT के किसी भी आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

96.

उत्तर: B

व्याख्या:

- भारत 5334 बड़े बांधों के संचालन के साथ चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है।
  - ये बाँध देश की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु महत्त्वपूर्ण हैं।
  - भारतीय बाँध और जलाशय सालाना लगभग 300 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण करके देश के आर्थिक और कृषि विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- भारत सरकार ने विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से अप्रैल 2012 में 'बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना' की शुरुआत की थी।
  - यह राज्य क्षेत्रक योजना थी, जिसमें एक केंद्रीय घटक भी शामिल था।
    - इसमें 10 कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ सात राज्यों (झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड) में स्थित 223 बाँधों के पुनर्वास का प्रावधान किया गया था।
  - सभी बाँधों के लिये महत्त्वपूर्ण डेटा प्राप्त करने और पुनर्वास प्रोटोकॉल की उचित निगरानी एवं विकास के लिये 'बाँध स्वास्थ्य एवं पुनर्वास निगरानी एप्लीकेशन' (धर्म-DHARM) नामक एक वेब-आधारित उपकरण विकसित किया गया है।अत: कथन 2 सही है।
- बाँध पुनर्वास और सुधार परियोजना' के पहले चरण की सफलता के आधार पर जल शक्ति मंत्रालय ने बाह्य रूप से वित्तपोषित योजना के चरण-II और चरण-III की शुरुआत की है।

इस योजना को अक्तूबर 2020 में मंज़ूरी दी गई थी।

  - योजना के दूसरे चरण को दो बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों - विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) द्वारा सह-वित्तपोषित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक द्वारा 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तपोषण किया जा रहा है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - योजना के वित्तपोषण पैटर्न में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 80:20 (विशेष श्रेणी के राज्य), 70:30 (सामान्य श्रेणी के राज्य) और 50:50 (केंद्रीय एजेंसियाँ) है।

97.

उत्तर: A

व्याख्या:

- पाम तेल वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक खपत वाला वनस्पति तेल है।
  - इसका उपयोग डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन और जैव ईंधन के उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जाता है।
  - कमोडिटी के शीर्ष उपभोक्ता भारत, चीन और यूरोपीय संघ (EU) हैं। अत: कथन 1 सही है।
  - भारत विश्व में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसमें से पाम तेल का आयात इसके कुल वनस्पति तेल आयात का लगभग 55% है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- भारत सालाना खपत किये जाने वाले लगभग 2.4 करोड़ टन खाद्य तेल के आधे से भी कम का उत्पादन करता है।

- यह इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल, ब्राज़ील तथा अर्जेंटीना से सोया तेल एवं रूस व यूक्रेन से सूरजमुखी का तेल आयात करता है।
- भारत में 94.1% पाम तेल का उपयोग खाद्य उत्पादों (विशेष रूप से खाना पकाने के प्रयोजनों के लिये) में किया जाता है। यह पाम तेल को भारत की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण बनाता है।

98.

उत्तर: A

व्याख्या:

- सार्वजनिक उद्यम (PE) सर्वेक्षण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) की 100 प्रतिशत विस्तृत गणना है।
  - यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) को लेकर सूचना का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है और सूचित नीति निर्माण के आधार पर कार्य करता है। अत: कथन 1 सही है।
- इसे वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा जारी किया जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) को भारी उद्योग मंत्रालय से फिर से वित्त मंत्रालय को आवंटित कर दिया है।
- लोक उद्यम विभाग (DPE) ने दूसरी लोकसभा की प्राक्कलन समिति की 73वीं रिपोर्ट (1959-60) की सिफारिशों पर वित्तीय वर्ष 1960-61 से सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण जारी करना शुरू किया। अत: कथन 3 सही नहीं है।

99.

उत्तर: B

व्याख्या:

- भारत सरकार ने घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस निर्माण को बढ़ावा देने के लिये रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (DTIS) शुरू की है।
  - इसमें 6-8 ग्रीनफील्ड रक्षा परीक्षण अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना की परिकल्पना की गई है जो रक्षा और एयरोस्पेस से संबंधित उत्पादन के लिये आवश्यक हैं।
    - इसमें निजी उद्योग के साथ साझेदारी में परीक्षण सुविधाएँ स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
    - इस योजना के तहत परियोजनाओं को 'अनुदान-सहायता' के रूप में 75 प्रतिशत तक सरकारी वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।
- परियोजना लागत का शेष 25 प्रतिशत स्पेशल प्रोपज़ल व्हीकल (SPVs) घटकों द्वारा वहन किया जाएगा, जिनमें भारतीय निजी संस्थाएँ और राज्य सरकारें शामिल होंगी।
- मेक इन इंडिया के तहत भारत ने देश में रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता को कम करने हेतु विनिर्माण आधार के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है।
  - इसके लिये उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे (Defence Industrial Corridors-DICs) स्थापित करने की घोषणा की गई है। अत: कथन 2 सही है।
  - नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने और भारतीय उद्योग को एयरोस्पेस तथा रक्षा क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये संशोधित मेक- II प्रक्रियाएँ, रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार (iDEX) और रक्षा निवेशक सेल की स्थापना जैसी कई पहलें की गई हैं।

100.

उत्तर : D

व्याख्या :

- मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित व्यापक आर्थिक नीति है। इसमें मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर का प्रबंधन शामिल है, यह मुद्रास्फीति, खपत, वृद्धि और तरलता जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये इस्तेमाल की जाने वाली मांग पक्ष आधारित आर्थिक नीति है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) विभिन्न तरीकों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिये केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग किये जाने वाले उपाय मात्रात्मक या गुणात्मक उपकरण हो सकते हैं।
- मात्रात्मक उपकरण नकद आरक्षित अनुपात (CRR), या बैंक दर या खुला बाज़ार परिचालन (OMO) को परिवर्तित कर मुद्रा आपूर्ति की सीमा को नियंत्रित करते हैं।
  - गुणात्मक साधनों में वाणिज्यिक बैंकों को हतोत्साहित करने या उधार देने को प्रोत्साहित करने के लिये केंद्रीय बैंक द्वारा अनुनय शामिल है जो नैतिक दबाव, मार्जिन आवश्यकता आदि के माध्यम से किया जाता है। अत: विकल्प D सही है।

101.

उत्तर: A

व्याख्या

- हाल ही में भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' (NMP) की शुरुआत की है। NMP के अनुमान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक चार साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्ति में 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता मौजूद है।

- यह योजना प्रधानमंत्री की रणनीतिक विनिवेश नीति के अनुरूप है, जिसके तहत सरकार केवल कुछ ही विशिष्ट क्षेत्रों में उपस्थिति बनाए रखेगी और शेष को निजी क्षेत्र के लिये खोल दिया जाएगा। अत: कथन 1 सही है।

- इसका उद्देश्य ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को शामिल करना और उन्हें राजस्व अधिकार हस्तांतरित करना है, हालाँकि इसके तहत परियोजनाओं के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, साथ ही इसके माध्यम से उत्पन्न पूंजी का उपयोग देश भर में बुनियादी अवसंरचनाओं के निर्माण के लिये किया जाएगा। अत: कथन 2 सही नहीं है।

102.

उत्तर : D

व्याख्या :

- EASE रिफॉर्म एजेंडा सरकार और PSB द्वारा संयुक्त रूप से जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था।
- इसे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के माध्यम से कमीशन किया गया था और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा निर्मित किया गया था।
- EASE सुधार एजेंडा के तहत विभिन्न चरण:
  - EASE 1.0: EASE 1.0 रिपोर्ट ने पारदर्शी रूप से गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) के समाधान में PSB के प्रदर्शन में महत्त्वपूर्ण सुधार दिखाया।
  - EASE 2.0: EASE 2.0 को EASE 1.0 की नींव पर बनाया गया था और सुधार यात्रा को अपरिवर्तनीय बनाने, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को मज़बूत करने तथा परिणामों को लागू करने के लिये छह विषयों में नए सुधार कार्य बिंदु प्रस्तुत किये गए। EASE 2.0 के छह विषय हैं:
    - ज़िम्मेदार बैंकिंग;
    - ग्राहक प्रतिक्रिया;
    - क्रेडिट ऑफ-टेक,
    - उद्यमी मित्र के रूप में पीएसबी (MSMEs के क्रेडिट प्रबंधन के लिये सिडबी पोर्टल);
    - वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण;
    - शासन और मानव संसाधन (HR)।
  - Ease 3.0: यह तकनीक का उपयोग करते हुए सभी ग्राहक अनुभवों में बैंकिंग को आसान बनाने का प्रयास करता है।
  - EASE 4.0 : यह ग्राहक-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिये PSB को तकनीक-सक्षम, सरलीकृत और सहयोगी बैंकिंग के लिये प्रतिबद्ध करता है। अत: विकल्प D सही है।

103.

उत्तर: C

व्याख्या

- 'स्वेट इक्विटी' का आशय एक कंपनी के कर्मचारी या संस्थापक की ओर से कंपनी को दिये गए गैर-मौद्रिक योगदान से होता है। प्राय: वित्तीय संकट से प्रभावित स्टार्टअप और व्यवसायों के मालिक आमतौर पर अपनी कंपनियों के लिये फंड जुटाने हेतु 'स्वेट इक्विटी' का उपयोग करते हैं। अत: कथन 1 और 2 दोनों सही हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (88) के अनुसार, 'स्वेट इक्विटी' शेयरों का अर्थ ऐसे इक्विटी शेयर से है, जो किसी कंपनी द्वारा अपने निदेशकों या कर्मचारियों को छूट पर जारी किये जाते हैं।
- यह बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्य वर्द्धन की प्रकृति में जानकारी प्रदान करने या अधिकार उपलब्ध कराने के लिये भी जारी किये जाएंगे।

104.

उत्तर: C

व्याख्या

- इन्फ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट
  - इन्हें कई निवेशकों की छोटी रकम को उन परिसंपत्तियों में निवेश करने के लिये डिज़ाइन किया गया है जो एक अवधि में नकदी प्रवाह उत्पन्न करते हैं। इस नकदी प्रवाह का एक हिस्सा निवेशकों को लाभांश के रूप में वितरित किया जाएगा।
    - ये ऐसे उपकरण हैं जो म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं। अत: कथन 1 सही है।
  - InvITs की संरचना इस प्रकार की जाती है कि निवेशकों को पूर्वानुमेय नकदी प्रवाह (Predictable Cash Flows) के साथ बुनियादी ढाँचे की संपत्ति में निवेश करने का अवसर मिल सके, जबकि परिसंपत्ति के मालिक उन परिसंपत्तियों से भविष्य में होने वाले राजस्व नकदी प्रवाह को रोकने हेतु अग्रिम संसाधन जुटा सकते हैं, जिन्हें बदले में नई परिसंपत्तियों में लगाया जा सकता है या कर्ज़ के रूप में चुकाने हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है।
  - InvITs को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) विनियम, 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - InvIT 'इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग' (IPO) में न्यूनतम निवेश राशि 10 लाख रुपए है, इसलिये यह उच्च आय वाले व्यक्तियों, संस्थागत और गैर-संस्थागत निवेशकों के लिये उपयुक्त है। अत: कथन 3 सही है।
    - InvITs को स्टॉक की तरह ही IPO के माध्यम से एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया जाता है।

105.

उत्तर: A

व्याख्या:

- लघु वित्त बैंक वे वित्तीय संस्थान हैं जो देश के उन क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं जहाँ बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
  - लघु वित्त बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं। अत: कथन 1 सही है।
  - इन्हें बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में अपने कम-से-कम 25% बैंकिंग आउटलेट खोलने की आवश्यकता होती है।
- SFB को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण (Adjusted Net Bank Credit) का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (Priority Sector Lending- PSL) में देना आवश्यक है। अत: कथन 2 सही है।
- SFB निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं:
  - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934,
  - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949,
  - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999,
  - भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007,
  - क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005,
  - जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961,
  - अन्य प्रासंगिक कानून तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और अन्य नियामकों द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देश। अत: कथन 3 सही नहीं है।

106.

उत्तर: A

व्याख्या:

- भारत ने बंकर तेल प्रदूषण क्षति, (बंकर कन्वेंशन) के लिये नागरिक दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की पुष्टि की। कन्वेंशन तेल रिसाव से होने वाले नुकसान हेतु पर्याप्त, त्वरित और प्रभावी मुआवज़ा सुनिश्चित करता है। .
  - कन्वेंशन को 23 मार्च, 2001 को अपनाया गया था और यह 21 नवंबर, 2008 को लागू हुआ था।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा प्रशासित था।
- वर्ष 2015 में भारत ने बंकर कन्वेंशन की पुष्टि की। अत: विकल्प A सही है।

107.

उत्तर: C

व्याख्या:

- भुगतान प्रणाली संचालकों के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही के एक ढाँचे के अनुसार, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक ऑडिट, अनुपालन व निर्णय लेने के कार्यों जैसे KYC मानदंडों के अनुपालन का निर्धारण करने सहित आउटसोर्सिंग कोर प्रबंधन कार्यों की अनुमति नहीं है। अत: कथन 1 सही नहीं है परन्तु कथन 2 सही है।
  - इसका उद्देश्य ग्राहकों और आईटी-आधारित सेवाओं जैसे ऑनबोर्डिंग कार्यों सहित भुगतान तथा निपटान संबंधी गतिविधियों की आउटसोर्सिंग में जोखिमों के प्रबंधन के लिये न्यूनतम मानकों को स्थापित करना है।
- भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS), RBI के केंद्रीय बोर्ड की एक उप-समिति, भारत में भुगतान प्रणाली पर नीति निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। अत: कथन 3 सही है।

108.

उत्तर: A

व्याख्या:

- अनौपचारिक क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जिस पर न तो सरकार द्वारा किसी प्रकार का कर लगाया जाता है और न ही उसकी निगरानी की जाती है।
  - यह काफी हद तक औपचारिक शिक्षा, आसान प्रवेश, स्थिर नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों की कमी और संचालन के एक छोटे पैमाने के बाहर प्राप्त कौशल की विशेषता है।
  - औपचारिक अर्थव्यवस्था के विपरीत अनौपचारिक क्षेत्र के घटकों को सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। अत: कथन 1 सही है।
  - भारत के अनुमानित 450 मिलियन अनौपचारिक श्रमिकों में इसके कुल कार्यबल का 90% शामिल है, जिसमें 5-10 मिलियन कर्मचारी वार्षिक रूप से जोड़े जाते हैं।
- सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ पहलें
  - प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM)
  - श्रम सुधार
  - प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (PMRPY)
  - पीएम स्वनिधि: स्ट्रीट वेंडर्स के लिये माइक्रो क्रेडिट स्कीम अत: कथन 2 सही है।
- हाल ही में विश्व बैंक (World Bank) ने वर्तमान महामारी संकट से उबरने के लिये भारत के अनौपचारिक श्रमिक वर्ग का समर्थन करने हेतु 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण कार्यक्रम को मंज़ूरी दी है। अत: कथन 3 सही नहीं है।
  - यह ऋण राज्यों को वर्तमान महामारी, भविष्य की जलवायु और आपदा के झटकों से निपटने हेतु अधिक नम्यता प्रदान करेगा।

109.

उत्तर: C

व्याख्या:

- NPA उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफॉल्ट हैं या मूलधन या ब्याज के भुगतान बकाया है।
  - ज़्यादातर मामलों में ऋण को गैर-निष्पादित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि में नहीं किया गया हो। अत: कथन 1 सही है।
  - सकल गैर-निष्पादित संपत्ति उन सभी ऋणों का योग है जो वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा नहीं चुकाए गए हैं।
  - निवल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ वह राशि है जो सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से कटौती के बाद प्राप्त होती है।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात जोखिम भारित आस्तियों और चालू देनदारियों के संबंध में बैंक की पूंजी का अनुपात है। इसे कैपिटल-टू-रिस्क वेटेड एसेट रेशियो (CRAR) के रूप में भी जाना जाता है। अत: कथन 2 सही है।
  - वाणिज्यिक बैंकों को अतिरिक्त लीवरेज लेने और प्रक्रिया में दिवालिया होने से रोकने के लिये केंद्रीय बैंकों द्वारा इसके संबंध में निर्णय लिया जाता है।
- प्रोविज़निंग कवरेज अनुपात खराब ऋणों के कारण संभावित नुकसान को कवर करने के लिये बैंकों द्वारा अलग रखी जाने वाली निधियों के निर्धारित प्रतिशत को संदर्भित करता है।

110.

उत्तर: A

व्याख्या:

- GST परिषद वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिये एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 279A) है। अत: कथन 1 सही है।
- इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करता है और अन्य सदस्य केंद्रीय राजस्व या वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं।
  - इसे एक संघीय निकाय के रूप में माना जाता है जहाँ केंद्र और राज्य दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

111.

उत्तर: C

व्याख्या

- हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes & Customs- CBIC) ने अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों (Authorised Economic Operators- AEO) के आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग की व्यवस्था शुरु की है। AEO विश्व सीमा शुल्क संगठन (World Customs Organization- WCO) के तत्त्वावधान में एक कार्यक्रम (वर्ष 2007) है, जो वैश्विक व्यापार को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने हेतु मानकों का एक सुरक्षित ढाँचा प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा को बढ़ाना और माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगी एक इकाई को WCO द्वारा आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा मानकों के अनुपालन के रूप में अनुमोदित किया जाता है और AEO का दर्जा प्रदान किया जाता है। अत: विकल्प C सही है।

112.

उत्तर.: C

व्याख्या.:

- हाल ही में भौगोलिक संकेत (GI) प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूँ की पहली खेप गुजरात से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। गेहूँ की भालिया किस्म को जुलाई 2011 में भौगोलिक संकेत (GI) प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ था। यह फसल मुख्य तौर पर गुजरात के भाल क्षेत्र में उगाई जाती है जिसमें अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर, भरूच ज़िले शामिल हैं।
- हाल में GI टैग प्राप्त करने वालों में झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग, तेलंगाना की तेलिया रुमाल, तिरूर वेटिला (केरल), डिंडीगुल लॉक और कंडांगी साड़ी (तमिलनाडु), ओडिशा रसगुल्ला, शाही लीची (बिहार) आदि शामिल हैं। अत: युग्म 2 और 4 सही सुमेलित हैं।

113.

उत्तर: B

व्याख्या

- सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-Sec) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली एक व्यापार योग्य साधन होती हैं।
- ये सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करती हैं। ऐसी प्रतिभूतियाँ अल्पकालिक (आमतौर पर एक वर्ष से भी कम समय की मेच्योरिटी वाली इन प्रतिभूतियों को ट्रेज़री बिल कहा जाता है जिसे वर्तमान में तीन रूपों में जारी किया जाता है, अर्थात् 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन) या दीर्घकालिक (आमतौर पर एक वर्ष या उससे अधिक की मेच्योरिटी वाली इन प्रतिभूतियों को सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ कहा जाता है) होती हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।

- भारत में केंद्र सरकार ट्रेज़री बिल और बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों को जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDL) कहा जाता है। अत: कथन 2 सही है।

114.

उत्तर: D

व्याख्या:

- वित्तीय वर्ष 20 में भारत की उर्वरक खपत लगभग 61 मिलियन टन थी, जिसमें से 55% यूरिया था और अनुमान है कि वित्त वर्ष 2015 में इसमें 5 मिलियन टन की वृद्धि हुई थी।
- चूँकि गैर-यूरिया (MoP, DAP, जटिल) किस्मों की लागत अधिक होती है, कई किसान वास्तव में ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया का उपयोग करना पसंद करते हैं।
- सरकार ने यूरिया की खपत को कम करने के लिये कई उपाय किये हैं। इसने गैर-कृषि उपयोग हेतु यूरिया के अवैध प्रयोग को कम करने के लिये नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत की।
  - उर्वरक विभाग (DoF) ने सभी घरेलू उत्पादकों के लिये नीम कोटेड यूरिया (NCU) के रूप में 100% यूरिया का उत्पादन अनिवार्य कर दिया है। अत: कथन 1 सही है।
- गैर-यूरिया उर्वरकों के उदाहरण: डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी)।
  - गैर-यूरिया उर्वरकों की MRP कंपनियों द्वारा नियंत्रित या तय की जाती है। हालाँकि केंद्र इन पोषक तत्त्वों पर एक फ्लैट प्रति टन सब्सिडी का भुगतान करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी कीमत "उचित स्तर" पर है।
  - सभी गैर-यूरिया आधारित उर्वरकों को पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत विनियमित किया जाता है। अत: कथन 2 सही है।

115.

उत्तर: A

व्याख्या:

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index-CPI) खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य में हुए परिवर्तन को मापता है।
  - इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office- NSO) द्वारा जारी किया जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - यह उन वस्तुओं और सेवाओं जैसे- भोजन, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की कीमत में अंतर की गणना करता है, जिसे भारतीय उपभोक्ता उपयोग के लिये खरीदते हैं।
  - इसके कई उप-समूह हैं जिनमें खाद्य और पेय पदार्थ, ईंधन तथा प्रकाश, आवास एवं कपड़े, बिस्तर व जूते शामिल हैं।
  - इसके निम्नलिखित चार प्रकार हैं:
    - औद्योगिक श्रमिकों (Industrial Workers-IW) के लिये CPI
    - कृषि मज़दूर (Agricultural Labourer-AL) के लिये CPI
    - ग्रामीण मज़दूर (Rural Labourer- RL) के लिये CPI
    - CPI (ग्रामीण/शहरी/संयुक्त)
  - इनमें से प्रथम तीन के आँकड़े श्रम और रोज़गार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो (labor Bureau) द्वारा संकलित किये जाते हैं, जबकि चौथे प्रकार की CPI को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical Organisation-CSO) द्वारा संकलित किया जाता है।
  - सामान्य तौर पर CPI के लिये आधार वर्ष 2012 है। हालाँकि औद्योगिक श्रमिकों हेतु CPI (CPI-IW) आधार वर्ष 2016 है।
- मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) मुद्रास्फीति (रेंज 4+/-2% के भीतर) को नियंत्रित करने के लिये CPI डेटा का उपयोग करती है।
  - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अप्रैल 2014 में CPI को मुद्रास्फीति के अपने प्रमुख उपाय के रूप में अपनाया था। अत: कथन 1 सही है।

116.

उत्तर: D

व्याख्या:

- SEZ किसी देश के भीतर स्थित ऐसे क्षेत्र हैं जो प्राय: शुल्क मुक्त (राजकोषीय रियायत) होते हैं और यहाँ मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोज़गार पैदा करने के लिये अलग-अलग व्यापार और वाणिज्यिक कानून होते हैं।
  - एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (Export Processing Zones- EPZ) वर्ष 1965 में कांडला, गुजरात में स्थापित किया गया था। अत: कथन 3 सही है।
    - EPZ एक प्रकार का SEZ है।
    - यह विदेशी संस्थाओं से निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करके वाणिज्यिक और औद्योगिक निर्यात को बढ़ाने के लिये स्थापित एक क्षेत्र है।

- सरकार ने वर्ष 2000 में EPZ की सफलता को सीमित करने वाली ढाँचागत और नौकरशाही चुनौतियों के निवारण के लिये विदेश व्यापार नीति के तहत SEZ की स्थापना शुरू की। अत: कथन 2 सही है।
  - विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया और वर्ष 2006 में SEZ नियमों के साथ लागू हुआ।
  - हालाँकि SEZ की स्थापना का कार्य वर्ष 2000 से 2006 तक (विदेश व्यापार नीति के तहत) भारत में चालू था।
  - भारत के SEZ को चीन के सफल मॉडल के साथ मिलकर संरचित किया गया था।
- SEZ के लिये उपलब्ध प्रमुख प्रोत्साहन और सुविधाएँ:
  - SEZ इकाइयों के विकास, संचालन और रखरखाव के लिये शुल्क मुक्त आयात/माल की घरेलू खरीद।
  - आयकर, न्यूनतम वैकल्पिक कर आदि जैसे विभिन्न करों से छूट। अत: कथन 1 सही है।
  - मान्यता प्राप्त बैंकिंग के माध्यम से बिना किसी परिपक्वता प्रतिबंध के SEZ इकाइयों द्वारा एक वर्ष में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की बाहरी वाणिज्यिक उधारी।
  - केंद्र और राज्य स्तर पर अनुमोदन के लिये एकल खिड़की अनुमोदन।

117.

उत्तर: D

व्याख्या:

- भारत की मौजूदा SEZ नीति का अध्ययन करने के लिये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा बाबा कल्याणी के नेतृत्व वाली समिति का गठन किया गया था और नवंबर 2018 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं।
- इसे विश्व व्यापार संगठन (WTO) को अनुकूल बनाने और अधिकतम क्षमता का उपयोग करने तथा SEZs के संभावित उत्पादन को अधिकतम करने हेतु वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने की दिशा में SEZ नीति का मूल्यांकन करने के व्यापक उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था।
- अत: विकल्प D सही है।

118.

उत्तर: D

व्याख्या :

- एशिया और प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific- ESCAP) एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये संयुक्त राष्ट्र की एक क्षेत्रीय विकास शाखा है।
  - यह 53 सदस्य देशों और 9 एसोसिएट सदस्यों से बना एक आयोग है। भारत भी इसका सदस्य है। अत: कथन 1 सही है।
  - इसकी स्थापना वर्ष 1947 में की गई थी।
  - इसका मुख्यालय थाईलैंड के बैंकॉक शहर में है।
- डिजिटल एवं सतत् व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण,2021 प्रत्येक दो वर्ष में UNESCAP द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) के व्यापार सुविधा समझौते में शामिल 58 व्यापार सुविधा उपायों का आकलन करना शामिल है। अत: कथन 2 सही है।
  - 58 उपायों में इंटरनेट पर मौजूदा आयात-निर्यात नियमों का प्रकाशन, जोखिम प्रबंधन, टैरिफ वर्गीकरण पर अग्रिम निर्णय, आगमन पूर्व प्रसंस्करण, स्वतंत्र अपील तंत्र, शीघ्र शिपमेंट, स्वचालित सीमा शुल्क प्रणाली आदि शामिल हैं।
- किसी देश का उच्च स्कोर कारोबारियों को निवेश संबंधी निर्णय लेने में भी मदद करता है।
- संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोग (UN Regional Commission) संयुक्त रूप से डिजिटल और सतत् व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण आयोजित करते हैं।
- सर्वेक्षण में वर्तमान में पूरे विश्व की 143 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। एशिया प्रशांत के लिये यह UNESCAP द्वारा आयोजित किया जाता है।
  - दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया क्षेत्र (63.12%) और एशिया प्रशांत क्षेत्र (65.85%) की तुलना में भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है।
  - भारत का समग्र स्कोर फ्राँस, यूके, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड आदि सहित कई आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) देशों से भी अधिक है और समग्र स्कोर यूरोपीय संघ (EU) के औसत स्कोर से अधिक है। अत: कथन 3 सही है।

119.

उत्तर: D

व्याख्या

- 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय' सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत 'सांख्यिकीय सेवा अधिनियम 1980' के तहत स्थापित सरकार की केंद्रीय सांख्यिकीय एजेंसी है।
  - यह सरकार और अन्य उपयोगकर्त्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सांख्यिकीय सूचना सेवाएँ प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है, जिसके आधार पर नीति-निर्माण, नियोजन, निगरानी और प्रबंधन संबंधी निर्णय लिये जा सकें।

- इसमें आधिकारिक सांख्यिकीय सूचना एकत्र करना, संकलित करना और प्रसारित करना शामिल है।

- NSO द्वारा संकलित अन्य रिपोर्ट और सूचकांक:
  - औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)
  - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)
  - सतत् विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट
  - आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अत: विकल्प D सही है।

120.

उत्तर: B

व्याख्या :

- सामरिक पेट्रोलियम भंडार कच्चे तेल से संबंधित किसी भी संकट जैसे- प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या अन्य आपदाओं के दौरान आपूर्ति में व्यवधान से निपटने के लिये कच्चे तेल के विशाल भंडार होते हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम (International Energy Programme- IEP) पर समझौते के अनुसार, कम-से-कम 90 दिनों के लिये शुद्ध तेल आयात के बराबर आपातकालीन तेल का स्टॉक रखना अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA) के प्रत्येक सदस्य देश का दायित्व है।
  - भारत वर्ष 2017 में IEA का सहयोगी सदस्य बना। अत: कथन 2 सही है।

121.

उत्तर: A

व्याख्या

- 'जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम' (DICGC) वर्ष 1978 में जमा बीमा निगम (Deposit Insurance Corporation- DIC) तथा क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Credit Guarantee Corporation of India- CGCI) के विलय के बाद अस्तित्व में आया।
  - यह भारत में बैंकों के लिये जमा बीमा और ऋण गारंटी के रूप में कार्य करता है।
  - यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अत: कथन 1 सही है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों, भारत में शाखाओं वाले विदेशी बैंकों और सहकारी बैंकों सहित अन्य बैंकों को DICGC से जमा बीमा कवर लेना अनिवार्य है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

122.

उत्तर: D

व्याख्या:

- हाल ही में सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) कार्यक्रम के तहत सरकार ने दो अतिरिक्त सुविधाएँ स्थापित करने की मंज़ूरी दे दी है।
  - वर्ष 2020 में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को देखते हुए भारत ने अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार को भरना शुरू कर दिया।
- नई सुविधाओं में भूमिगत भंडारण की कुल 6.5 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) भंडारण क्षमता के साथ वाणिज्यिक-सह-सामरिक सुविधाएँ होंगी:
  - चंदीखोल (ओडिशा) (4 MMT)
  - पाडुर (कर्नाटक) (2.5 MMT)
- इन्हें SPR कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल में बनाया जाएगा।
- कार्यक्रम के पहले चरण के तहत भारत सरकार ने 3 स्थानों पर 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) की कुल क्षमता के साथ सामरिक पेट्रोलियम भंडारण (SPR) सुविधाएँ स्थापित की हैं:
  - विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) (1.33 MMT)।
  - मंगलौर (कर्नाटक) (1.5 MMT)।
  - पाडुर (कर्नाटक) (2.5 MMT)।
- पहले चरण के तहत स्थापित पेट्रोलियम भंडार की प्रकृति सामरिक महत्त्व के लिये है। इन भंडारों में संग्रहीत कच्चे तेल का उपयोग तेल की कमी की स्थिति में किया जाएगा और ऐसा तब होगा जब भारत सरकार की ओर से इसकी घोषणा की जाएगी।
- भारत में सामरिक कच्चे तेल की भंडारण सुविधाओं के निर्माण कार्य का प्रबंधन भारतीय सामरिक पेट्रोलियम भंडार लिमिटेड (ISPRL) द्वारा किया जा रहा है।
- ISPRL पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत तेल उद्योग विकास बोर्ड (OIDB) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अत: विकल्प D सही है।

123.

उत्तर: A

व्याख्या:

- भारत में केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) प्रणाली और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) प्रणाली तथा किसी भी अन्य प्रणाली के रूप में शामिल होंगे जिस पर समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

- RTGS: यह लाभार्थियों के खाते में वास्तविक समय पर धनराशि के हस्तांतरण की सुविधा को सक्षम बनाता है और इसका प्रयोग मुख्य तौर पर बड़े लेन-देनों के लिये किया जाता है।
- NEFT: यह एक देशव्यापी भुगतान प्रणाली है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है।

- विकेंद्रीकरण भुगतान प्रणाली में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समाशोधन व्यवस्था [चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS)] के साथ-साथ अन्य बैंक [एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम (ECCS) केंद्रों की जाँच] और किसी अन्य प्रणाली के रूप शामिल होंगे जिसमें समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णय लिया जाएगा। अत: विकल्प A सही है।

124.

उत्तर: A

व्याख्या:

- ऋण दर की सीमांत लागत (MCLR) अप्रैल 2016 में प्रभावी हुआ। यह फ्लोटिंग-रेट ऋणों के लिये एक बेंचमार्क ऋण दर है। यह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक ग्राहकों को उधार दे सकते हैं। अत: कथन 1 सही है।
- यह दर चार घटकों- धन की सीमांत लागत, नकद आरक्षित अनुपात, परिचालन लागत और परिपक्वता अवधि पर आधारित है।
- MCLR वास्तविक जमा दरों से जुड़ा हुआ है। इसलिये जब जमा दरों में वृद्धि होती है, तो यह इंगित करता है कि बैंकों की ब्याज दर बढ़ने की संभावना है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

125.

उत्तर: A

व्याख्या:

- भौगोलिक संकेत (GI) एक प्रकार का विशिष्ट संकेतक है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न किसी विशिष्ट विशेषताओं वाले सामानों की पहचान करने हेतु किया जाता है। अत: कथन 1 सही है।
- इसका उपयोग कृषि, प्राकृतिक और विनिर्मित वस्तुओं के लिये किया जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- 'माल का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999' भारत में माल से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
- भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिये वैध होता है, हालाँकि इसे समय-समय पर 10-10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिये नवीनीकृत किया जा सकता है। अत: कथन 3 सही नहीं है।
- यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं (TRIPS) का भी एक हिस्सा है।
- यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं (TRIPS) का भी एक हिस्सा है।

126.

उत्तर: D

व्याख्या:

- कर्मचारी डिपॉज़िट-लिंक्ड बीमा (Employees' Deposit-Linked Insurance- EDLI) निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये EPFO द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक बीमा कवर है। अत: कथन 1 सही है।
  - इसे वर्ष 1976 में लॉन्च किया गया था।
- कोई भी कर्मचारी जिसके पास EPF खाता है, वह स्वत: ही EDLI योजना के लिये पात्र हो जाता है। अत: कथन 2 सही है।
  - यह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत पंजीकृत सभी संगठनों पर लागू होता है।
- ईडीएलआई योजना का प्रबंधन नियोक्ता द्वारा भुगतान किये गए मासिक वेतन के 0.5% के आधार पर किया जाता है और इसमें कर्मचारी का योगदान नहीं होता है। कर्मचारी द्वारा पंजीकृत नामांकित व्यक्ति योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिये पात्र है।

127.

उत्तर: A

व्याख्या:

- भारत में ऑपरेशन फ्लड (श्वेत क्रांति) डॉ. वर्गीज़ कुरियन (Dr Verghese Kurein) के दिमाग की उपज थी। उनके अधीन गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) जैसे कई महत्त्वपूर्ण संस्थान स्थापित किये गए थे।
  - श्वेत क्रांति NDDB द्वारा 1970 के दशक में शुरू की गई थी और ऑपरेशन फ्लड की आधारशिला ग्राम दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समितियाँ हैं।
- उद्देश्य:
  - दूध उत्पादन में वृद्धि। अत: कथन 1 सही है।
  - ग्रामीण क्षेत्र की आय में वृद्धि।
  - उपभोक्ताओं को उचित दाम पर दूध उपलब्ध कराना।
- महत्त्व:
  - इसने डेयरी किसानों को अपने स्वयं के हाथों बनाए गए संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिये अपने स्वयं के विकास को निर्देशित करने में मदद की।

- इसने वर्ष 2016-17 में भारत को विश्व में सबसे बड़ा दूध का उत्पादक बनने में मदद की है।
- वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, जिसका वैश्विक उत्पादन 22% है इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और ब्राज़ील का स्थान है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

128.

उत्तर: B

व्याख्या:

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों की उत्पादन लागत से कम-से-कम डेढ़ गुना अधिक होती है।
  - 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' किसी भी फसल के लिये वह 'न्यूनतम मूल्य' है, जिसे सरकार किसानों के लिये लाभकारी मानती है और इसलिये इसके माध्यम से किसानों का 'समर्थन' करती है।
- 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' द्वारा सरकार को 22 अधिदिष्ट फसलों (Mandated Crops) के लिये 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) तथा गन्ने के लिये 'उचित और लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की जाती है।
  - केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा MSP के स्तर और CACP द्वारा की गई अन्य सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेती है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- अधिदिष्ट फसलों में 14 खरीफ फसलें, 6 रबी फसलें और दो अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।
- इसके अलावा लाही और नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSPs) का निर्धारण क्रमश: सरसों और सूखे नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (MSPs) के आधार पर किया जाता है।
- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। अत: कथन 2 सही है।

129.

उत्तर: A

व्याख्या:

- भारत का विद्युत क्षेत्र विश्व में सबसे विविध क्षेत्रों में से एक है। विद्युत् उत्पादन के स्रोतों की श्रेणी पारंपरिक स्रोतों जैसे- कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा से लेकर व्यवहार्य गैर-पारंपरिक स्रोत जैसे- पवन, सौर और कृषि तथा घरेलू कचरे तक है।
- भारत विश्व में विद्युत् का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- विद्युत एक समवर्ती सूची (संविधान की सातवीं अनुसूची) का विषय है। अत: कथन 1 सही है।
- विद्युत मंत्रालय देश में विद्युत ऊर्जा के विकास के लिये प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है।
  - यह विद्युत अधिनियम, 2003 और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 को प्रशासित करता है।
- सरकार ने वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा में 175 गीगावाट क्षमता हासिल करने के लिये अपना रोडमैप जारी किया है, जिसमें 100 गीगावाट सौर ऊर्जा और 60 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है।
  - सरकार वर्ष 2022 तक रूफटॉप सौर परियोजनाओं के माध्यम से 40 गीगावाट (GW) विद्युत उत्पन्न करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 'रेंट ए रूफ' (Rent a Roof) नीति तैयार कर रही है।
  - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित सभी मामलों के लिये नोडल मंत्रालय है।
- विद्युत क्षेत्र में स्वत: मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI) की अनुमति है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

130.

उत्तर: B

व्याख्या

- निगम कर उस शुद्ध आय या लाभ पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है जो उद्यमी अपने व्यवसायों से कमाते हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में सार्वजनिक और निजी तौर पर पंजीकृत दोनों प्रकार की कंपनियाँ, निगम कर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं। अत: कथन 2 सही है।
- यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार एक विशिष्ट दर पर लगाया जाता है। अत: कथन 3 सही है।
- सितंबर 2019 में भारत ने मौजूदा कंपनियों के लिये निगम कर की दरों को 30% से घटाकर 22% और नई निर्माण कंपनियों के लिये 25% से 15% कर दिया था।
  - सरचार्ज और सेस को मिलाकर मौजूदा कंपनियों के लिये प्रभावी टैक्स दर अब 35% से कम होकर 25.17% हो गई है।

131.

उत्तर : C

व्याख्या :

- माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन (MFI) वित्तीय सेवा का एक रूप है, जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को लघु ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है। अत: कथन 1 सही है।
- माइक्रोफाइनेंस प्रदान करने वाले संस्थानों की संख्या और माइक्रोफाइनेंस ग्राहकों को उपलब्ध कराए गए क्रेडिट की मात्रा दोनों में वृद्धि के मामले में पिछले दो दशकों में भारतीय माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। अत: कथन 3 सही नहीं है।
- माइक्रो क्रेडिट विभिन्न संस्थागत चैनलों के माध्यम से वितरित किया जाता है, जैसे,
  - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCB) [लघु वित्त बैंक (SFB) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) सहित]
  - सहकारी बैंक,
  - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)
  - माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) NBFC के साथ-साथ अन्य रूपों में पंजीकृत हैं। अत: कथन 2 सही नहीं है।

132.

उत्तर: B

व्याख्या:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
- MSMEs क्षेत्र को बढ़ावा देने संबंधी पहलें
  - नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा हेतु एक योजना (ASPIRE): यह योजना 'कृषि आधारित उद्योग में स्टार्टअप के लिये फंड ऑफ फंड्स', ग्रामीण आजीविका बिज़नेस इनक्यूबेटर (LBI), प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (TBI) के माध्यम से नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देती है। अत: युग्म 3 सही सुमेलित है।
- उद्यम पंजीकरण पोर्टल: यह नया पोर्टल देश में एमएसएमई की संख्या पर डेटा एकत्र करने में सरकार की सहायता करता है।
  - MSME समाधान: यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई/राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतान के बारे में सीधे मामले दर्ज करने में सक्षम बनाता है। अत: युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है।
- एमएसएमई संबंध: यह एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। इसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसई से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये शुरू किया गया था। अत: युग्म 2 सही सुमेलित है।

133.

उत्तर: B

व्याख्या:

- लघु बचत योजनाएँ, भारत में घरेलू बचत के प्रमुख स्रोत हैं और इसमें 12 उपकरण/प्रपत्र (Instrument) शामिल हैं।
  - जमाकर्त्ताओं को उनके धन पर सुनिश्चित ब्याज मिलता है।
  - सभी लघु बचत प्रपत्रों से संग्रहीत राशि को राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) में जमा किया जाता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों का निर्धारण समान परिपक्वता वाले बेंचमार्क सरकारी बॉण्डों के अनुरूप तिमाही आधार पर किया जाता है। अत: कथन 2 सही है।
  - वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दरों की समीक्षा की जाती है।

134.

उत्तर: A

व्याख्या:

- प्रो. प्रशांत चंद्र महालनोबिस को आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है, उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान (Indian Statistical Institute- ISI) की स्थापना की, योजना आयोग को आकार दिया (जिसे 1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया) और बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण के लिये कार्यप्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया।
- उन्होंने रैंडम सैंपलिंग की विधि का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण करने तथा परिकलित रकबे/पहले से अनुमानित क्षेत्रफल और फसल की पैदावार का आकलन करने हेतु नवीन तकनीकों की शुरुआत की।
  - उन्होंने 'फ्रैक्टाइल ग्राफिकल एनालिसिस' नामक एक सांख्यिकीय पद्धति भी तैयार की, जिसका उपयोग विभिन्न समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बीच तुलना करने के लिये किया जाता है। अत: कथन 1 सही है।
- वर्ष 1955 में वह योजना आयोग के सदस्य बने और वर्ष 1967 तक उस पद पर बने रहे।
- उन्होंने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961) तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत में औद्योगीकरण और विकास का खाका तैयार किया। अत: कथन 2 सही नहीं है।

135.

उत्तर: D

व्याख्या:

- भारत में राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) की स्थापना 1999 में की गई थी।

- चूंकि NSSF सार्वजनिक खाते में काम करता है, इसलिये इसका लेनदेन केंद्र के राजकोषीय घाटे को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है।

- राष्ट्रीय लघु बचत कोष (निगरानी और निवेश) नियम, 2001 के तहत वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) इस कोष को प्रशासित करता है। जिसे राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 283(1) के तहत बनाया गया है। अत: कथन 1 और 2 सही हैं।
- NSSF का उद्देश्य भारत के संचित निधि से छोटी बचत लेन-देन को हटाना और पारदर्शी तथा आत्मनिर्भर तरीके से उनका संचालन सुनिश्चित करना है। अत: कथन 3 सही है।

136.

उत्तर: A

व्याख्या:

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) घरेलू उपभोग के लिये बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्यवर्द्धित कर है।
  - GST का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है।
  - GST, जिसने लगभग सभी घरेलू अप्रत्यक्ष करों (पेट्रोलियम, मादक पेय और स्टांप शुल्क प्रमुख अपवाद हैं) को एक मंच के अंतर्गत समाहित कर दिया, शायद यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कर सुधार है। इसे 1 जुलाई, 2017 की मध्यरात्रि को परिचालन में लाया गया था।
- GST की विशेषताएँ:
  - आपूर्ति पक्ष पर लागू: वस्तु के निर्माण या वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर पुरानी अवधारणा के विपरीत वस्तुओं या सेवाओं की 'आपूर्ति' पर जीएसटी लागू है।
  - गंतव्य आधारित कराधान: GST मूल-आधारित कराधान के सिद्धांत के विपरीत गंतव्य-आधारित उपभोग कराधान के सिद्धांत पर आधारित है। अत: कथन 1 सही है।
  - दोहरा GST: यह केंद्र और राज्यों पर एक साथ, एक समान आधार पर लगाया जाने वाला कर है। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी (CGST) कहा जाता है और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले को राज्य जीएसटी (SGST) कहते हैं।
    - वस्तुओं या सेवाओं के आयात को अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में माना जाएगा तथा यह लागू सीमा शुल्क के अतिरिक्त एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) के अधीन होगा।
  - पारस्परिक रूप से तय की जाने वाली जीएसटी दरें: CGST, SGST व IGST केंद्र और राज्यों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत दरों पर लगाए जाते हैं। जीएसटी परिषद की सिफारिश पर दरें अधिसूचित की जाती हैं। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - बहुगामी दरें: जीएसटी चार दरों (5%, 12%, 18% और 28%) पर लगाया जाता है। जीएसटी परिषद द्वारा इन बहुतायत चरणों (Slabs) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं की अनुसूची या सूची तैयार की जाती है।
    - इसमें अलग से जीएसटी के तहत मोटे कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थरों पर 0.25% की एक विशेष दर तथा सोने पर 3% की दर निश्चित की गई है।

137.

उत्तर: A

व्याख्या:

- हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) का 23वाँ अंक जारी किया।
- FSR जो कि द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित होती है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC- आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में) की उप-समिति द्वारा वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन तथा जोखिम के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाती है।
- रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। अत: विकल्प A सही है।

138.

उत्तर : D

व्याख्या :

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने टॉयकथॉन 2021 (Toycathon 2021) में प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए लोगों से "वोकल फॉर लोकल टॉयज" यानी "स्थानीय खिलौनों की ओर रुख करने" का आग्रह किया।
- Toycathon 2021 पहल शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय और तकनीकी शिक्षा के लिये अखिल भारतीय परिषद (AICTE) द्वारा की गई।.
  - भारतीय मूल्य प्रणाली के आधार पर नवीन खिलौनों की अवधारणा का विकास करना जो बच्चों में सकारात्मक व्यवहार और अच्छे मूल्यों को बढ़ाएगा।
    - भारत को एक वैश्विक खिलौना विनिर्माण केंद्र (आत्मनिर्भर अभियान) के रूप में बढ़ावा देना। अत: विकल्प D सही है।

139.

उत्तर: A

व्याख्या:

- एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को हुई थी।
- ADB में कुल 68 सदस्य शामिल हैंI भारत ADB का एक संस्थापक सदस्य है। अत: कथन 1 सही है।
  - कुल सदस्यों में से 49 सदस्य देश एशिया-प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से हैं।
  - इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- 31 दिसंबर 2019 तक ADB के पाँच सबसे बड़े शेयरधारकों में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (प्रत्येक कुल शेयरों के 15.6% के साथ), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (6.4%), भारत (6.3%) और ऑस्ट्रेलिया (5.8%) शामिल हैं। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है।अत: कथन 3 सही नहीं है।

140.

उत्तर: B

व्याख्या:

- IIP एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में बदलाव को मापता है।
- यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह एक समग्र संकेतक है, जो कि निम्न रूप से वर्गीकृत किये गए उद्योग समूहों की वृद्धि दर को मापता है:
  - व्यापक क्षेत्र, अर्थात्-खनन, विनिर्माण और बिजली।
  - बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स जैसे उपयोग आधारित क्षेत्र।
- IIP के लिये आधार वर्ष 2011-2012 है। अत: कथन 2 सही है।
- IIP का महत्त्व:
  - इसका उपयोग नीति निर्माण के लिये वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक आदि सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
  - IIP त्रैमासिक और अग्रिम जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) अनुमानों की गणना के लिये बेहद प्रासंगिक है।

141.

उत्तर: B

व्याख्या:

- राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) को वर्ष 1999 में भारत की लोक लेखा निधि (Public Account of India) के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - इस कोष का उद्देश्य भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से छोटी बचत लेन-देन को जोड़ना और पारदर्शी तथा आत्मनिर्भर तरीके से उनका संचालन सुनिश्चित करना है।
    - राष्ट्रीय लघु बचत कोष सार्वजनिक खाते के रूप में संचालित होता है, इसलिये इसका लेन-देन सीधे केंद्र के वित्तीय घाटे को प्रभावित नहीं करता है।
- इस कोष को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत कोष (कस्टडी और निवेश) नियम, 2001 के तहत संविधान के अनुच्छेद 283 (1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित किया जाता है। अत: कथन 2 सही है।

142.

उत्तर: D

व्याख्या:

- मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद, वर्ष 1999 में बीमा उद्योग को विनियमित करने और विकसित करने के लिये एक स्वायत्त निकाय के रूप में बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) का गठन किया गया था। अत: कथन 1 सही है।
- अप्रैल 2000 में IRDA को एक सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया था। अत: कथन 2 सही है।
- IRDA के प्रमुख उद्देश्यों में बीमा बाज़ार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ता की पसंद और कम प्रीमियम के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के साथ ही प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना भी शामिल है।
- इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अत: कथन 3 सही है।

143.

उत्तर: C

व्याख्या:

- हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (G-SAP) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) की खरीद का निर्णय लिया है, जिसके परिणामस्वरूप बेंचमार्क पर यील्ड के 10-वर्षीय बॉन्ड में 6% से कम की गिरावट दर्ज़ की गई।

- RBI ने वर्ष 2021-22 के लिये एक द्वितीयक बाज़ार सरकारी प्रतिभूति (G-sec) अधिग्रहण कार्यक्रम या G-SAP 1.0 लागू करने का निर्णय लिया है।
- यह RBI के 'खुला बाज़ार परिचालनों'(OMOs) का हिस्सा है। अत: कथन 1 सही है।
- इस कार्यक्रम के तहत RBI सरकारी प्रतिभूतियों की खुली बाज़ार खरीद का संचालन करेगी।

- इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अवधि संरचना और जारीकर्त्ताओं को ध्यान में रखते हुए अन्य वित्तीय बाज़ार साधनों के मूल्य निर्धारण में इसकी केंद्रीय भूमिका को देखते हुए सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में अस्थिरता से बचना है।
- यह बॉण्ड बाज़ार सहभागियों को वित्त वर्ष 2021-22 में RBI के समर्थन की प्रतिबद्धता के संबंध में निश्चितता प्रदान करेगा।
- इस संरचित कार्यक्रम की घोषणा से रेपो दर और 10 वर्ष के सरकारी बॉण्ड यील्ड के बीच के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। अत: कथन 2 सही है।
  - यह बदले में वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्र और राज्यों की उधार लेने की कुल लागत को कम करने में मदद करेगा।
- यह व्यवस्थित तरलता की स्थिति के बीच 'यील्ड कर्व' (Yield Curve) के स्थिर और व्यवस्थित विकास को सक्षमता प्रदान करेगा।

144.

उत्तर: B

व्याख्या:

- RBI ने वर्ष 1999 में जनता, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से प्राप्त प्रतिपुष्टि (Feedback) के आधार पर विनियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिये पहले विनियमन समीक्षा प्राधिकरण (RRA) की स्थापना की थी। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह नियामक निर्देशों को सुव्यवस्थित करने, जहाँ भी संभव हो रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं तथा आवश्यकताओं को कम करके और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने आदि विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अत: कथन 2 सही है।
  - इसके अलावा यह विनियमित संस्थाओं से भी प्रतिपुष्टि प्राप्त करेगा।
  - विनियमित संस्थाओं में वाणिज्यिक बैंक, शहरी सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ शामिल हैं।

145.

उत्तर: C

व्याख्या:

- मुद्रास्फीति का तात्पर्य दैनिक या आम उपयोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं, जैसे- भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन, परिवहन आदि की कीमतों में वृद्धि से है।
- मुद्रास्फीति के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य परिवर्तन को मापा जाता है।
  - मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी का संकेत है। इससे अंतत: आर्थिक विकास में मंदी आ सकती है।
  - हालाँकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये मुद्रास्फीति के संतुलित स्तर की आवश्यकता होती है।
- भारत में मुद्रास्फीति की गणना दो मूल्य सूचियों के आधार पर की जाती है- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)।, जो क्रमश: थोक और खुदरा मूल्य स्तर के परिवर्तनों को मापते हैं। अत: कथन 1 सही है।
- कोर मुद्रास्फीति का आशय वस्तुओं और सेवाओं की लागत में बदलाव से है, लेकिन इसमें खाद्य और ऊर्जा क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं की लागत को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इनकी कीमतें अधिक अस्थिर होती हैं। अत: कथन 2 सही है।
  - इसका उपयोग उपभोक्ता आय पर बढ़ती कीमतों के प्रभाव को निर्धारित करने के लिये किया जाता है।

146.

उत्तर: (B)

व्याख्या

- सरकार ने सोने की मांग को कम करने और घरेलू बचत के एक हिस्से (जिसका उपयोग स्वर्ण की खरीद के लिये किया जाता है) को वित्तीय बचत में बदलने के उद्देश्य से नवंबर 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (Sovereign Gold Bond) योजना की शुरुआत की थी। अत: कथन 1 सही है।
- निर्गमन: गोल्ड/स्वर्ण बॉण्ड सरकारी प्रतिभूति (GS) अधिनियम, 2006 के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किये जाते हैं।
  - ये भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं। अत: कथन 2 सही है।
- इन बॉण्डों की बिक्री निवासी व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs), न्यासों/ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों तक ही सीमित है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

147.

उत्तर: A

व्याख्या:

- AIF का अर्थ भारत में स्थापित या निगमित कोई भी फंड है जो एक निजी रूप से जमा निवेश वाहन है जो अपने निवेशकों के लाभ के लिये एक परिभाषित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने के लिये परिष्कृत निवेशकों, चाहे भारतीय हो या विदेशी, से धन एकत्र करता है। अत: कथन 1 सही है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) विनियम (AIF), 2012 के विनियम 2(1)(बी) में AIF की परिभाषा निर्धारित की गई है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - एक कंपनी या एक सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnership- LLP) के माध्यम से एक वैकल्पिक निवेश कोष स्थापित किया जा सकता है।

148.

उत्तर: B

व्याख्या:

- अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुसंगत मूल सूची को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- इसमें निम्नलिखित श्रेणियाँ शामिल हैं:
  - परिवहन और संचालन: सड़कें और पुल, अंतर्देशीय जलमार्ग, हवाई अड्डा, आदि।
  - ऊर्जा: विद्युत उत्पादन, विद्युत संचरण, आदि।
  - जल और स्वच्छता: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल उपचार संयंत्र, आदि।
  - संचार: दूरसंचार आदि।
- सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना: शिक्षा संस्थान (शेयर पूंजी), खेल अवसंरचना, अस्पताल (शेयर पूंजी), पर्यटन अवसंरचना, आदि। अत: कथन 2 सही है।
- हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा एक्जीबिशन/प्रदर्शनी स्थलों और कन्वेंशन/सम्मेलन केंद्रों (Convention Centres) को 'बुनियादी ढाँचे' का दर्जा दिया गया है।
  - एक्जीबिशन-कम-कन्वेंशन सेंटर/प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र को एक नई वस्तु के रूप में सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (Social and Commercial Infrastructure) की श्रेणी में इन्फ्रास्ट्रक्चर उप-क्षेत्रों (Infrastructure Sub-Sectors) की सामंजस्यपूर्ण मूल सूची में शामिल किया गया है।
- वर्ष 2020 में सरकार ने बुनियादी ढाँचे के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्रों की सूची में किफायती किराया आवास योजनाओं (Affordable Rental Housing Project) को शामिल किया था।

149.

उत्तर: C

व्याख्या:

- ई-वे बिल, जी.एस.टी. के तहत एक बिल प्रणाली है जो वस्तुओं के हस्तांतरण की स्थिति में जारी की जाती है। इसमें हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं का विवरण तथा उस पर लगने वाले जी.एस.टी. की पूरी जानकारी होती है।
- इसे अप्रैल 2018 से 50,000 रुपए से अधिक मूल्य के माल के अंतर्राज्यीय परिवहन पर आरोपित करना अनिवार्य बना दिया गया है, जिसमें सोने जैसी कीमती वस्तुओं को छूट दी गई है। अत: कथन 1 सही है।
  - यह माल का परिवहन जीएसटी कानून के अंतर्गत करने और इसकी आवाजाही को ट्रैक तथा कर चोरी की जाँच सुनिश्चित करने वाला एक उपकरण है।
- अधिसूचित ई-वे बिल नियमों के अनुसार प्रत्येक आपूर्तिकर्त्ता को माल की आवाजाही के लिये ई-वे बिल पोर्टल पर पूर्व ऑनलाइन पंजीकरण की आवश्यकता होती है।
  - कर अधिकारियों को कर चोरी की जाँच के लिये ट्रांजिट के दौरान किसी भी समय ई-वे बिल की जाँच करने का अधिकार है। अत: कथन 2 सही है।

150.

उत्तर: C

व्याख्या:

- GI एक संकेतक है इसका उपयोग ऐसे उत्पादों के लिये किया जाता है, जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है।
- इसका उपयोग कृषि, प्राकृतिक और निर्मित वस्तुओं के लिये किया जाता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- भारत में वस्तु के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम [Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act], 1999 वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण तथा बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
- अधिनियम का संचालन महानियंत्रक पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क द्वारा किया जाता है जो भौगोलिक संकेतकों का पंजीयक (Registrar) है।
  - भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई (तमिलनाडु) में स्थित है।

- भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिये वैध होता है। समय-समय पर इसे 10-10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिये नवीनीकृत किया जा सकता है। अत: कथन 2 सही है।
  - यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights- TRIPS) का भी एक हिस्सा है। अत: कथन 3 सही है।

151.

उत्तर: C

व्याख्या:

- पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority- PFRDA) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिये संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक प्राधिकरण है।
  - यह वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Service) के अंतर्गत काम करता है। अत: कथन 1 सही है।
- यह विभिन्न मध्यवर्ती एजेंसियों जैसे- पेंशन फंड मैनेज़र (Pension Fund Manager), सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (Central Record Keeping Agency) आदि की नियुक्ति का कार्य करता है।
  - यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System- NPS) के तहत पेंशन उद्योग को विकसित, बढ़ावा और नियंत्रित करता है तथा अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana- APY) का प्रबंधन भी करता है। अत: कथन 2 सही है।

152.

उत्तर: C

व्याख्या

- करेंसी स्वैप अथवा मुद्रा विनिमय का आशय दो देशों के बीच पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान-प्रदान हेतु किये गए समझौते या अनुबंध से है। अत: कथन 1 सही है।
- इन विनिमय समझौतों में विनिमय दर या अन्य बाज़ार संबंधी जोखिमों का कोई खतरा नहीं रहता है, क्योंकि लेनदेन की शर्तें अग्रिम रूप से निर्धारित होती हैं। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये श्रीलंका के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंज़ूरी दी है। अत: कथन 3 सही है।
  - वर्तमान संदर्भ में मुद्रा स्वैप को प्रभावी रूप से ऋण के रूप में देखा जा सकता है, जो बांग्लादेश द्वारा श्रीलंका को डॉलर के रूप में दिया जाएगा, साथ ही इसमें यह समझौता भी शामिल है कि ऋण और उसके साथ ब्याज का भुगतान श्रीलंकाई रुपए में किया जाएगा।

153.

उत्तर: B

व्याख्या

- किसी देश के भुगतान संतुलन (BoP) को आमतौर पर एक वर्ष की विशिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व के साथ किसी देश के सभी आर्थिक लेनदेन के व्यवस्थित विवरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। BoP खाते तैयार करने के लिये एक देश और दुनिया के बाकी हिस्सों के बीच आर्थिक लेन-देन को चालू खाता, पूंजी खाता, वित्तीय खाता और त्रुटियाँ एवं चूक आदि में समूहीकृत किया जाता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- भुगतान संतुलन के घटक
  - चालू खाता: यह दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं (वस्तुओं और सेवाओं) के निर्यात और आयात को दर्शाता है। अत: कथन 2 सही है।
  - पूंजी खाता: यह एक देश के पूंजीगत व्यय और आय को दर्शाता है। यह एक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक निवेश दोनों के शुद्ध प्रवाह का सारांश देता है।
  - त्रुटि एवं चूक: कभी-कभी भुगतान संतुलन संतुलित नहीं होता है। इस असंतुलन को भुगतान संतुलन में त्रुटियों और चूक के रूप में दिखाया जाता है।

154.

उत्तर: A

व्याख्या:

- स्वामी फंड सरकार समर्थित फंड है जिसे सेबी के साथ पंजीकृत श्रेणी- II AIF (वैकल्पिक निवेश कोष) ऋण फंड के रूप में स्थापित किया गया था, इसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। अत: कथन 1 सही है।
- स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड (SWAMIH Investment Fund) का गठन RERA-पंजीकृत किफायती और मध्यम आय वर्ग की आवास परियोजनाओं के निर्माण को पूरा करने के लिये किया गया था, जो धन की कमी के कारण रुकी हुई है। अत: कथन 2 सही है।
- फंड का निवेश प्रबंधक SBICAP वेंचर्स (SBICAP Ventures) है जो कि SBI कैपिटल मार्केट्स के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

- SBI कैपिटल मार्केट्स, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
- भारत सरकार की ओर से कोष का प्रायोजक वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (न कि सेबी) का सचिव है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

155.

उत्तर: D

व्याख्या:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के प्रकाशन:

- उपभोक्ता आत्मविश्वास सर्वेक्षण (Consumer Confidence Survey- CCS): त्रैमासिक प्रकाशन।
- परिवारों की मुद्रास्फीति अपेक्षाओं का सर्वेक्षण (Inflation Expectations Survey of Households-IESH): त्रैमासिक प्रकाशन।
- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report): अर्द्धवार्षिक
- मौद्रिक नीति रिपोर्ट (Monetary Policy Report): अर्द्धवार्षिक
- विदेशी मुद्रा भंडार पर रिपोर्ट (Report on Foreign Exchange Reserves): अर्द्धवार्षिक

156.

उत्तर: D

व्याख्या:

- सामाजिक उद्यम एक लाभांश है जो गैर-लाभांश भुगतान करने वाली कंपनी ने किसी एक विशिष्ट सामाजिक समस्या को संबोधित करने के लिये स्थापित किया हो। अत: कथन 1 सही है।
- संघीय बजट 2019-20 में पूंजी निर्माण के लिये सामाजिक उद्यम, स्वैच्छिक और कल्याणकारी संगठनों को सूचीबद्ध करते हुए सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) को एक मंच के रूप में गठित करने का प्रस्ताव रखा गया था। अत: कथन 2 सही है।
  - इसे SEBI के विनियामक दायरे के तहत गठित करने का प्रस्ताव दिया गया था।
  - इस पहल का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु इक्विटी या ऋण या म्यूचुअल फंड की एक इकाई के रूप में पूंजी निर्माण कार्यों में संलग्न सामाजिक और स्वैच्छिक संगठनों की सहायता करना हैं। अत: कथन 3 सही है।
  - सिंगापुर, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों में SSE पहले से ही स्थापित है। ये देश स्वास्थ्य, पर्यावरण और परिवहन जैसे क्षेत्रों में संचालित फर्मों को SSE जे माध्यम से पूंजी निर्माण के लिये अनुमति देते हैं।

157.

उत्तर: C

व्याख्या:

- FSSAI के अनुसार "जैविक खेती" (Organic Farming) रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंथेटिक हार्मोन आदि के उपयोग के बिना कृषि उत्पादन की एक प्रणाली है।
  - भारत के सिक्किम राज्य को विश्व का प्रथम जैविक राज्य होने का गौरव हासिल है और इसे संयुक्त राष्ट्र के फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड (Future Policy Gold Award), 2018 से भी सम्मानित किया जा चुका है। अत: कथन 2 सही है।
- अप्रैल-फरवरी (2020-21) के दौरान भारत के जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात बीते वर्ष (2019-20) इसी अवधि की तुलना में बढ़कर 7078 करोड़ रुपए (51% की बढ़ोतरी) हो गया है। वहीं मात्रा के आधार पर जैविक खाद्य उत्पादों के निर्यात में 39% की वृद्धि हुई। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - भारत के जैविक उत्पादों को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, इज़रायल और दक्षिण कोरिया सहित 58 देशों में निर्यात किया जाता है।
- वर्तमान में उन जैविक उत्पादों का निर्यात किया जाता है, जिनका 'नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन' (National Programme for Organic Production) की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकिंग और लेबलिंग की गई हो। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन (NPOP) का कार्यान्वयन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा किया जाता है। अत: कथन 3 सही नहीं है।
  - APEDA, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
  - इसे मुख्य तौर पर निर्यात संवर्द्धन और अनुसूचित उत्पादों अर्थात् सब्जियों, मांस उत्पादों, डेयरी उत्पादों, मादक और गैर-मादक पेय आदि के विकास को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है।

158.

उत्तर: B

व्याख्या :

- भारत के सार्वजनिक खाते में राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) को वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था।
- इस कोष को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत कोष (कस्टडी और निवेश) नियम, 2001 के तहत संविधान के अनुच्छेद 283 (1) के अनुसार राष्ट्रपति

द्वारा प्रशासित किया जाता है।इसे वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) राष्ट्रीय लघु बचत कोष (निगरानी और निवेश) नियम, 2001 के अंतर्गत प्रशासित (न की वित्त अधिनियम,1994 के द्वारा) करता है। अत: कथन 1 सही है जबकि 2 सही नहीं है।

- इस कोष का उद्देश्य भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से छोटी बचत लेन-देन को जोड़ना और पारदर्शी तथा आत्मनिर्भर तरीके से उनका संचालन सुनिश्चित करना है।
  - राष्ट्रीय लघु बचत कोष सार्वजनिक खाते के रूप में संचालित होता है, इसलिये इसका लेन-देन सीधे केंद्र के वित्तीय घाटे को प्रभावित नहीं करता है। अत: कथन 3 सही है।

159.

उत्तर : A

व्याख्या:

- RBI की 'मौद्रिक नीति समिति (MPC)' 'भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934' के तहत स्थापित एक वैधानिक एवं संस्थागत निकाय है। यह आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्थिरता को बनाए रखने हेतु कार्य करती है। अत: कथन 1 सही है।
- रिज़र्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- MPC मुद्रास्फीति दर के 4% के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये ब्याज दर (रेपो रेट) के निर्धारण का कार्य करती है।
  - भारत की केंद्र सरकार मुद्रास्फीति के लक्ष्य को निर्धारित करती है। अत: कथन 3 सही नहीं है।
- वर्ष 2014 में तत्कालीन डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली रिज़र्व बैंक की समिति ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की सिफारिश की थी।

160.

उत्तर: B

व्याख्या:

- हाल ही में एशिया एवं प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग (UNESCAP) ने एशिया एवं प्रशांत का आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण (Economic and Social Survey of Asia and the Pacific), 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।
  - इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में 7% रहने का अनुमान है, जबकि सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों (Normal Business Activity) पर महामारी के प्रभाव के कारण पिछले वित्त वर्ष (2020-21) में 7.7% का संकुचन देखा गया था।
- एशिया और प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण की प्रगति पर वर्ष 1947 से प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाने वाली यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी रिपोर्ट है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह सर्वेक्षण क्षेत्रीय प्रगति के बारे में जानकारी देने के साथ वर्तमान व उभरते सामाजिक-आर्थिक मुद्दों तथा नीतिगत चुनौतियों पर अत्याधुनिक विश्लेषण एवं चर्चा के लिये मार्गदर्शन प्रदान करता है और क्षेत्र में समावेशी एवं सतत् विकास का समर्थन करता है।
- इस सर्वेक्षण में वर्ष 1957 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण पहलू और चुनौती से संबंधित अध्ययन को शामिल किया जाता है। अत: कथन 2 सही है।
- वर्ष 2021 का सर्वेक्षण कोविड-19 महामारी के प्रभाव का अध्ययन करता है और कोविड-19 के चलते अर्थव्यवस्थाओं के लचीलेपन हेतु अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

161.

उत्तर: C

व्याख्या:

लोकपाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1809 में स्वीडन में आधिकारिक तौर पर लोकपाल संस्था का उद्घाटन किया गया। अत: कथन 1 सही है।
- 20वीं शताब्दी में एक संस्था के रूप में ओम्बड्समैन का विकास हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसके विकास में तेज़ी आई।
  - वर्ष 1967 में व्हाईट रिपोर्ट (वर्ष 1961) की सिफारिशों पर ग्रेट ब्रिटेन ने लोकपाल संस्था को अपनाया और इस तरह की प्रणाली रखने वाला लोकतांत्रिक दुनिया का पहला बड़ा राष्ट्र बन गया। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- भारत में संवैधानिक ओम्बड्समैन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1960 के दशक की शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया था।
  - लोकपाल और लोकायुक्त शब्द डॉ. एल.एम. सिंघवी द्वारा गढ़े गए थे। अत: कथन 3 सही है।
  - Ombudsman का कार्य कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करना है।

162.

उत्तर: B

व्याख्या:

- चालू खाता के अंतर्गत केवल वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात को रिकॉर्ड किया जाता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - यह विश्व के अन्य देशों के साथ एक देश के लेन-देन का प्रतिनिधित्व करता है तथा पूंजी खाते की तरह देश के भुगतान संतुलन (Balance of Payment) का एक घटक होता है।

- जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है, तो उसके BoP में व्यापार अधिशेष की स्थिति होती है, वहीं जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो उसे (BoP) व्यापार घाटे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
- चालू खाता घाटे को निर्यात को बढ़ावा देने और गैर-आवश्यक वस्तुओं जैसे कि सोना, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात पर अंकुश लगाने से कम किया जा सकता है। अत: कथन 2 सही है।

163.

उत्तर: (B)

व्याख्या

- विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से है, जिसमें बॉण्ड, ट्रेज़री बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल होती हैं।
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:
  - विदेशी परिसंपत्तियाँ (विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, बॉण्ड इत्यादि विदेशी मुद्रा में)
  - स्वर्ण भंडार
  - IMF के पास रिज़र्व ट्रेंच
  - विशेष आहरण अधिकार (SDR)

अत: कथन 1 सही नहीं है।

- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ वे हैं जिनका मूल्यांकन उस देश की अपनी मुद्रा के बजाय किसी अन्य देश की मुद्रा में किया जाता है।
- FCA विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है। इसे डॉलर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। अत: कथन 2 सही है।
- गैर-अमेरिकी मुद्रा जैसे- यूरो, पाउंड और येन की कीमतों में उतार-चढ़ाव को FCA में शामिल किया जाता है।

164.

उत्तर: (C)

व्याख्या

- विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति के रूप में बनाया गया था। अत: कथन 1 सही है।
- SDR न तो एक मुद्रा है और न ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है। बल्कि यह IMF के सदस्यों के स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिये SDR का आदान-प्रदान किया जा सकता है।
- SDR के मूल्य की गणना, 'बास्केट ऑफ करेंसी' में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर की जाती है। इस बास्केट में पाँच देशों की मुद्राएँ शामिल हैं- अमेरिकी डॉलर, यूरोपियन यूरो, चीन की मुद्रा रॅन्मिन्बी, जापानी येन और ब्रिटेन का पाउंड। अत: कथन 2 सही है।
- विशेष आहरण अधिकार ब्याज (SDRi) सदस्य देशों को उनके द्वारा धारण किये जाने वाले SDR पर मिलने वाला ब्याज है।

165.

उत्तर: C

व्याख्या:

- वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का एक सर्वेक्षण है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- इस रिपोर्ट को आमतौर पर अप्रैल और अक्तूबर महीने में क्रमश: दो बार प्रकाशित किया जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- यह भविष्य के चार वर्षों तक के अनुमानों के साथ निकट और मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण तथा भविष्यवाणी करता है। अत: कथन 3 सही है।

166.

उत्तर: C

व्याख्या:

- 12 जुलाई, 1982 को भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (Agricultural Refinance and Development Corporation- ARDC) के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित कर नाबार्ड की स्थापना की गई।
  - यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित किया गया है।
    - यह एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है।
    - यह कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंकिंग संस्थान है।
  - नाबार्ड के प्रमुख कार्य:
    - यह ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करता है। अत: कथन 1 सही है।
    - पुनर्वित्त संस्थान महत्त्वपूर्ण संस्थान होते हैं जो अन्य संस्थानों के माध्यम से अंतिम ग्राहक को ऋण उपलब्ध कराते हैं।

- नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि किसानों एवं ग्रामीण कारीगरों की निवेश गतिविधियों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराए जा सके।
- यह सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पर्यवेक्षण कर उच्च स्तरीय बैंकिंग सुविधाओं को विकसित करने तथा उन्हें कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (Core Banking Solution-CBS) प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने में मदद करता है। अत: कथन 2 सही है।

167.

उत्तर: D

व्याख्या:

- भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (IEX) के विद्युत बाज़ार ने मार्च 2021 के महीने में 8,248.52 MU (मिलियन यूनिट्स) का उच्च स्तर हासिल किया है, जिससे पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं।
  - IEX भारत में विद्युत के भौतिक वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र और ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र के लिये एक राष्ट्रव्यापी, स्वचालित व्यापार मंच प्रदान करने वाला पहला और सबसे बड़ा ऊर्जा एक्सचेंज है।
  - यह एक्सचेंज उचित मूल्य निर्धारण में सक्षम बनाता है और व्यापार निष्पादन की गति और दक्षता को बढ़ाते हुए भारत में विद्युत बाज़ार तक पहुँच और पारदर्शिता को बढ़ाता है।
  - यह 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज' (NSE) और 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज' (BSE) के साथ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है। अत: कथन 1 सही है।
  - यह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) द्वारा अनुमोदित और विनियमित है तथा वर्ष 2008 से कार्यरत है। अत: कथन 2 सही है।
    - यह विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत अर्द्ध-न्यायिक स्थिति के साथ एक सांविधिक निकाय है। अत: कथन 3 सही है।
    - CERC भारत में बिजली क्षेत्र का एक नियामक है।
    - यह थोक बिजली बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, निवेश को बढ़ावा देने और मांग आपूर्ति की खाई को पाटने के लिये संस्थागत बाधाओं को हटाने पर सरकार को सलाह देने का इरादा रखता है।

168.

उत्तर: D

व्याख्या:

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण

- RBI बैंकों को अपने धन का एक निश्चित हिस्सा कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढाँचे, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अन्य क्षेत्रों में उधार देने के लिये बाध्य करता है।
  - सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और विदेशी बैंकों (भारत में एक बड़ी उपस्थिति के साथ) को इन क्षेत्रों में ऋण देने के लिये अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (ANDC) के 40% को अलग करना अनिवार्य है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और लघु वित्त बैंकों को PSL का 75% ANDC आवंटित करना है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- इसके पीछे विचार यह सुनिश्चित करना है कि पर्याप्त संस्थागत ऋण अर्थव्यवस्था के कुछ कमज़ोर क्षेत्रों तक पहुँच सके।

169.

उत्तर: C

व्याख्या:

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है।
  - इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किया जाता है। अत: कथन 1 सही है।
- CPI खाद्य, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में अंतर की गणना करता है, जिसे भारतीय उपभोक्ता उपभोग के लिये खरीदते हैं। अत: कथन 2 सही है।

170.

उत्तर: (B)

व्याख्या

- कई बार ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी के रूप में एक करदाता द्वारा वर्ष भर आय उत्पन्न की जाती है, लेकिन आयकर कानून के विभिन्न प्रावधानों (जैसे छूट, कटौती, मूल्यह्रास, आदि) का लाभ उठाकर इस आय को कम किया जा सकता है। करदाता द्वारा अपनी कर देयता को कम किया जा सकता है या वह किसी भी कर का भुगतान करने करने के लिये बाध्य नहीं है।
- शून्य कर भुगतान करने वाली कंपनियों की संख्या में वृद्धि के कारण वित्त अधिनियम,1987 द्वारा मूल्यांकन वर्ष 1988-89 के प्रभाव से न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) की शुरुआत की गई थी। बाद में इसे वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा वापस ले लिया गया था और फिर वित्त अधिनियम,1996 द्वारा पुन: प्रस्तुत किया गया था। अत: कथन 1 सही है।

- MAT की गणना 15% बुक प्रॉफिट (लाभ और हानि खाते में दिखाया गया लाभ) या सामान्य कॉर्पोरेट दरों पर की जाती है, इसमें से जो भी अधिक है वह कर के रूप में देय है।
- भारत में सभी कंपनियाँ, चाहे वह घरेलू हों या विदेशी, MAT के प्रावधानों के अंतर्गत आती हैं। बाद में MAT के अधिकार क्षेत्र में गैर-कॉरपोरेट संस्थाओं को भी शामिल किया गया। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- MAT एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है जिसकी मदद से कर की चोरी को रोका जा सकता है।

171.

उत्तर: (C)

व्याख्या

- अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्यह्रास का आशय मुद्रा के मूल्य में गिरावट से है।
  - अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में बाज़ार शक्तियाँ (मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर) मुद्रा का मूल्य निर्धारित करती हैं।
- मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण किसी देश की निर्यात गतिविधि बढ़ जाती है, क्योंकि उसके उत्पाद और सेवाएँ तुलनात्मक रूप से सस्ती हो जाती हैं। अत: कथन 1 सही है।
- विदेशी पर्यटकों को मुद्रा के मूल्यह्रास का लाभ मिलता है, क्योंकि इससे भारत की यात्रा सस्ती (न कि महँगी) हो जाती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- रुपए के मूल्यह्रास का प्रभाव
  - निम्नलिखित पर रुपए के मूल्यह्रास का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा
    - विदेशों से आयात करने वाले लोगों पर
    - विदेशों में पढ़ रहे छात्रों पर
    - विदेश यात्रा कर रहे लोगों पर
    - विदेशों में निवेश कर रहे लोगों पर
    - विदेश में चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहे लोगों पर
  - निम्नलिखित पर रुपए के मूल्यह्रास का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा
    - भारत से निर्यात करने वाले लोगों पर
    - अनिवासी भारतीयों (NRIs) से प्रेषण प्राप्त करने वाले लोगों पर अत: कथन 3 सही है।

172.

उत्तर: C

व्याख्या:

- लोकपाल एक सरकारी अधिकारी होता है जो सार्वजनिक संगठनों के खिलाफ आम लोगों द्वारा की गई शिकायतों से निपटता है।
  - लोकपाल (ओम्बड्समैन) का यह कॉन्सेप्ट स्वीडन से आया है।
- लोकपाल किसी सेवा या प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिये विधायिका द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है।
- भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में शिकायतों के समाधान के लिये लोकपाल की नियुक्ति की जाती है।
  - बीमा लोकपाल
  - आयकर लोकपाल
  - बैंकिंग लोकपाल अत: विकल्प C सही है।

173.

उत्तर : A

व्याख्या :

- नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) RBI का एक केंद्रीयकृत भुगतान प्रणाली है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है।
  - नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) में मुद्रा के लेन-देन को बैचेज़ (Batches) अर्थात् समूह में पूरा किया जाता है, यानी इस प्रणाली के तहत एक निश्चित समयसीमा तक प्राप्त सभी लेन-देनों का निपटान एक साथ किया जाता है।
  - इसका उपयोग आमतौर पर 2 लाख रुपए तक के फंड ट्रांसफर के लिये किया जाता है।
  - अत: विकल्प A सही है।
- रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS) RBI का एक केंद्रीयकृत भुगतान प्रणाली है।
  - यह लाभार्थियों के खाते में वास्तविक समय पर धनराशि हस्तांतरण की सुविधा को सक्षम बनाता है और इसका प्रयोग मुख्य तौर पर बड़े लेन-देनों के लिये किया जाता है।
  - यहाँ 'रियल टाइम' अथवा वास्तविक समय का अभिप्राय निर्देश प्राप्त करने के साथ ही उनके प्रसंस्करण (Processing) से है, जबकि 'ग्रॉस सेटलमेंट' या सकल निपटान का तात्पर्य है कि धन हस्तांतरण निर्देशों का निपटान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है।
- विकेंद्रीकरण भुगतान प्रणाली में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समाशोधन व्यवस्था [चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) सेंटर] के साथ-साथ अन्य बैंकों [एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम (ECCS) केंद्रों की जाँच] और किसी भी अन्य प्रणाली के रूप शामिल होंगे जिसमें समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

174.

उत्तर: C

व्याख्या:

- हाल ही में अमेरिका ने भारत समेत 11 देशों को उनकी मुद्रा के व्यवहार को लेकर 'मुद्रा व्यवहार निगरानी सूची' (करेंसी मैनिपुलेटर्स वॉच लिस्ट) में रखा है।
  - दिसंबर 2020 की रिपोर्ट में भारत इस सूची में था। वर्ष 2019 में यूएस ट्रेज़री विभाग ने भारत को अपनी 'करेंसी मैनिपुलेटर्स वॉच लिस्ट' में प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की सूची से हटा दिया था। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- करेंसी मैनिपुलेटर्स:
  - यह अमेरिकी सरकार द्वारा उन देशों का एक वर्गीकरण है, जिनके बारे में अमेरिका यह महसूस करता है कि वे देश डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्रा का जानबूझकर अवमूल्यन करके "अनुचित मुद्रा व्यवहारों" में संलग्न हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
    - इसका कारण यह है कि अवमूल्यन से उस देश से निर्यात की लागत कम हो जाएगी और इसके परिणामस्वरूप कृत्रिम रूप से व्यापार घाटे में कमी दिखाई देगी।

175.

उत्तर: (C)

व्याख्या

- सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (MFI) उन कंपनियों को कहा जाता है जो निम्न आय वर्ग के लोगों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिये सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराते हैं।
  - इसकी सेवाओं में सूक्ष्म ऋण,सूक्ष्म बचत और सूक्ष्म बीमा शामिल है।
- MFI वित्तीय कंपनियाँ उन लोगों को छोटे ऋण प्रदान करती हैं जो समाज के वंचित और कमजोर वर्गों से हैं तथा जिनके पास बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच उपलब्ध नहीं है। अत: कथन 1 सही है।
  - सूक्ष्म ऋण का अभिप्राय अलग-अलग देशों में भिन्न होता है। भारत में 1 लाख रुपए से कम के सभी ऋणों को माइक्रोलोन या सूक्ष्म ऋण माना जा सकता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- पिछले कुछ दशकों में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र तेजी से बढ़ा है और वर्तमान में इनके पास भारत की गरीब आबादी के लगभग 102 मिलियन खाते (बैंकों और छोटे वित्त बैंकों सहित) हैं।
- भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (Non Banking Finance Company) और MFIs का रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2011 द्वारा नियमन किया जाता है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

176.

उत्तर: B

व्याख्या:

- 'वेज़ एंड मीन्स एडवांस' (WMA) की शुरुआत वर्ष 1997 में की गई थी।इसका उद्देश्य सरकार की प्राप्तियों और भुगतान के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल को दूर करना। अत: कथन 1 सही है।
- यदि आवश्यक हो तो सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक से तत्काल नकद ले सकते हैं, लेकिन उसे 90 दिनों के अंदर यह राशि लौटानी होगी। अत: कथन 2 सही है।
- इसमें ब्याज मौजूदा रेपो दर पर लिया जाता है:
  - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (5) केंद्रीय बैंक को केंद्र और राज्य सरकारों को उधार देने के लिये अधिकृत करता है , जो उनके देय (अग्रिम के निर्माण की तारीख से तीन महीने बाद नहीं) के अधीन है।
  - यदि WMA 90 दिनों से अधिक हो जाता है , तो इसे ओवरड्राफ्ट के रूप में माना जाएगा (ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर रेपो दर से 2 प्रतिशत अधिक है)।अत: कथन 3 सही नहीं है।
  - WMA (केंद्र के लिये) की सीमा सरकार और RBI द्वारा पारस्परिक रूप से और समय-समय पर संशोधित की जाती है।
    - WMA (केंद्र के लिये) की सीमा सरकार और RBI द्वारा पारस्परिक रूप से और समय-समय पर संशोधित की जाती है।
    - एक उच्च सीमा तक सरकार को RBI से (बाज़ार से उधार लिये बिना) ऋण लेने की सुविधा प्रदान करती है।
  - वेज़ और मीन्स एडवांस दो प्रकार के होते हैं- सामान्य और विशेष।
    - राज्य द्वारा आयोजित सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ एक विशेष WMA या विशेष आहरण सुविधा प्रदान की जाती है।
    - राज्य द्वारा SDF की सीमा समाप्त हो जाने के बाद, यह सामान्य WMA हो जाता है।
    - SDF के लिये ब्याज दर रेपो दर से एक प्रतिशत कम है।
    - सामान्य WMA के तहत ऋण की संख्या राज्य के वास्तविक राजस्व और पूंजीगत व्यय के तीन साल के औसत पर आधारित है।

177.

उत्तर: B

व्याख्या:

- पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Power Grid Corporation of India) ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) - पॉवर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (Power Grid Infrastructure Investment Trust-PGInvIT) लॉन्च किया है।
  - यह पहली बार है जब एक राज्य के स्वामित्व वाली इकाई 'इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट' के माध्यम से अपनी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण कर रही है।
  - यह 'IRB InvIT' और 'इंडिया ग्रिड ट्रस्ट' के बाद भारतीय बाज़ारों में सूचीबद्ध होने वाला तीसरा InvIT होगा। 'IRB InvIT' और 'इंडिया ग्रिड ट्रस्ट' दोनों को ही वर्ष 2017 में सार्वजनिक किया गया था। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - सरकारी सहायता पर निर्भर हुए बिना धन संबंधी आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिये राज्य-संचालित कंपनियों को एक वैकल्पिक धन संग्रहण मार्ग प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा InvIT मार्ग प्रस्तावित किया गया था।
- पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (PGCIL) यह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अत: कथन 2 सही है।
  - यह देश की सबसे बड़ी बिजली ट्रांसमिशन कंपनी है।
  - इसने अपना व्यावसायिक संचालन वर्ष 1992-93 में शुरू किया था और वर्तमान में यह एक महारत्न कंपनी है।

178.

उत्तर: C

व्याख्या:

- परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ विशेष वित्तीय संस्थान हैं जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 'नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स' (Non Performing Assets- NPAs) खरीदते हैं ताकि वे अपनी बैलेंसशीट को स्वच्छ रख सकें। अत: कथन 1 सही है।
  - जब ऋण लेने वाला व्यक्ति 90 दिनों तक ब्याज अथवा मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसको दिया गया ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति माना जाता है।
  - यह बैंकों को सामान्य बैंकिंग गतिविधियों में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। बैंकों द्वारा बकाएदारों पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने के बजाय वे ARC को अपना NPAs पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर बेच सकते हैं।
- सिक्योरिटाइज़ेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट' (SARFAESI) Act, 2002 भारत में ARCs की स्थापना के लिये कानूनी आधार प्रदान करता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - सरफेसी अधिनियम न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना गैर-निष्पदनकारी संपत्ति के पुनर्निर्माण में मदद करता है। इस अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में ARCs का गठन और उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साथ पंजीकृत किया गया।
  - RBI को ARCs को विनियमित करने की शक्ति मिली है। अत: कथन 3 सही है।

179.

उत्तर: B

व्याख्या :

- कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) को एक प्रबंधन अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके तहत कंपनियाँ अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को उनके हितधारकों के साथ एकीकृत करती हैं।
- भारत में CSR की अवधारणा को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत नियंत्रित किया जाता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - संभावित CSR गतिविधियों की पहचान करके एक रूपरेखा तैयार करने के साथ-साथ CSR को अनिवार्य करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है।
- CSR का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है, जिनका निवल मूल्य (Net Worth) ₹ 500 करोड़ से अधिक हो या कुल कारोबार (Turnover) ₹1000 करोड़ से अधिक हो या शुद्ध लाभ (Net Profit) ₹5 करोड़ से अधिक हो। अत: कथन 2 सही है ।

180.

उत्तर: C

व्याख्या:

- समेकित सिंकिंग फंड (CSF) की स्थापना 1999-2000 में RBI द्वारा राज्यों को बाज़ार ऋणों से मुक्त करने के लिये की गई थी। अत:कथन 1 सही है।
- प्रारंभ में, 11 राज्यों ने सिकिंग निधि की स्थापना की गई। बाद में, 12वें वित्त आयोग (2005-10) ने सिफारिश की कि सभी राज्यों के पास सभी ऋणों के परिशोधन के लिये धनराशि होनी चाहिये, जिसमें बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि (NSSF) के खाते पर देयताएँ आदि शामिल हैं।

- निधि को राज्यों और सार्वजनिक खाते की समेकित निधि से बाहर रखा जाना चाहिये। अत:कथन 2 सही है।
- इसका उपयोग ऋण परिशोधन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
- योजना के अनुसार, राज्य सरकारें प्रत्येक वर्ष कोष में बकाया बाज़ार ऋण का 1-3% योगदान कर सकती हैं।
- इस कोष का संचालन आरबीआई नागपुर के केंद्रीय लेखा अनुभाग द्वारा किया जाता है।

181.

उत्तर: B

व्याख्या:

- इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT), म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) की तरह ही एक सामूहिक निवेश योजना है, जो अवसंरचना परियोजनाओं में व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों निवेशकों से प्राप्त राशि के प्रत्यक्ष निवेश को संभव बनाती है और निवेशकों को इस पर आय का छोटा हिस्सा अर्जित करने का अवसर मिलता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - InvITs को 'रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट' (Real Estate Investment Trust-ReIT) के संशोधित संस्करण के रूप में देखा जा सकता है, जिसे फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है।
  - इसे प्राय: आय सृजन और परिचालन योग्य बुनियादी अवसंरचना जैसे- सड़क, बिजली ट्रांसमिशन लाइनों और गैस पाइपलाइनों आदि के निर्माण के लिये बनाया गया है।
  - इन संपत्तियों के पास मज़बूत और दीर्घकालिक अनुबंध होते हैं, जो दीर्घकाल (15-20 वर्ष) तक स्थिर नकदी प्रवाह प्रदान करते हैं।
- इसे सेबी (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) विनियम, 2014 द्वारा विनियमित किया जाता है। अत: कथन 2 सही है।

182.

उत्तर: A

व्याख्या:

ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट

- ब्रेंट क्रूड ऑयल का उत्पादन उत्तरी सागर में शेटलैंड द्वीप (Shetland Islands) और नॉर्वे के बीच तेल क्षेत्रों में होता है।
- वेस्ट क्रूड इंटरमीडिएट (WTI) ऑयल क्षेत्र मुख्यत: अमेरिकी क्षेत्र टेक्सास, लुइसियाना और नॉर्थ डकोटा में अवस्थित है।

लाइट एंड स्वीट:

- ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI दोनों ही लाइट और स्वीट (Light and Sweet) होते हैं, लेकिन ब्रेंट में अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान (American Petroleum Institute-API) की हिस्सेदारी थोड़ी अधिक होती है।
  - API क्रूड ऑयल या परिष्कृत उत्पादों के घनत्व का एक संकेतक है।
- ब्रेंट (0.37%) की तुलना में WTI में कम सल्फर सामग्री (0.24%) होने के कारण इसे तुलनात्मक रूप में "स्वीट" कहा जाता है।

बेंचमार्क मूल्य:

- OPEC द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्रेंट क्रूड ऑयल मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क मूल्य (Benchmark Price) है, जबकि अमेरिकी तेल कीमतों के लिये WTI क्रूड ऑयल मूल्य एक बेंचमार्क है। अत: कथन 1 सही है।
- भारत मुख्य रूप से क्रूड ऑयल OPEC देशों से आयात करता है, अत: भारत में तेल की कीमतों के लिये ब्रेंट बेंचमार्क है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

शिपिंग लागत

- शिपिंग की लागत आमतौर पर ब्रेंट क्रूड ऑयल के लिये कम होती है, क्योंकि इसका उत्पादन समुद्र के पास होता है, जिससे इसे कार्गो जहाज़ों में तुरंत लादा जा सकता है।
- WTI के शिपिंग का मूल्य अधिक होता है क्योंकि इसका उत्पादन भूमि वाले क्षेत्रों में होता है, जहाँ भंडारण की सुविधा सीमित है।

183.

उत्तर: A

व्याख्या:

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 950 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ वर्ष 2020-21 तक बढ़ा दिया गया है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) ने अपने मूल लक्ष्यों को पूरा करने सहित नई योजनाओं की एक शृंखला के साथ अपने दायरे को बढ़ाने हेतु ULPIN का विस्तार वर्ष 2023-24 तक किये जाने का प्रस्ताव दिया है।
- ULPIN, एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (Integrated Land Information Management System-ILIMS) के विकास हेतु विभिन्न राज्यों में भूमि रिकॉर्ड्स के क्षेत्र में मौजूद समानता पर आधारित होगा, जिसमें अलग-अलग राज्य अपनी विशिष्ट ज़रूरतों के अनुसार, प्रासंगिक और उचित चीज़ों को जोड़ सकेंगे।

- एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली: इस प्रणाली में भूखंड का स्वामित्व, भूमि उपयोग, कराधान, स्थान सीमा, भूमि मूल्य, ऋण भार और कई अन्य जानकारियाँ शामिल होंगी।

- इस कार्यक्रम के तहत कुछ नई पहलें भी शामिल की गई हैं जैसे- नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (National Generic Document Registration System- NGDRS), ULPIN, राजस्व न्यायालय को भू-अभिलेखों से जोड़ना तथा सहमति के आधार पर भू-अभिलेखों को आधार नंबर के साथ एकीकरण करना आदि। अत: कथन 2 सही है।

184.

उत्तर. B

व्याख्या:

- वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीसरी (अक्तूबर-दिसंबर) तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 0.4% दर की वृद्धि और विनिर्माण तथा कृषि में सुधार के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था तकनीकी मंदी (Technical Recession) से बाहर निकल गई है।
- ध्यातव्य है कि जब किसी देश की जीडीपी में एक ही वित्तीय वर्ष की लगातार दो तिमाहियों में गिरावट देखने को मिलती है, तो इस स्थिति को तकनीकी मंदी कहा जाता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- सकल मूल्य वर्धित (GVA) के संदर्भ में विकास दर - जो कि सकल घरेलू उत्पाद में से शुद्ध उत्पाद कर को घटाने से प्राप्त होती है और आपूर्ति में वृद्धि को दर्शाती है, पिछले वर्ष के 7.2% और 3.9% के अनुमानों के मुकाबले वर्ष 2020-21 में 6.5% दर्ज की गई है। अत: कथन 2 सही है।

185.

उत्तर: C

व्याख्या:

- विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना वर्ष 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद (Customs Co-operation Council- CCC) के रूप में की गई। यह एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है, जिसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाना है। अत: कथन 1 सही है।
  - इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में स्थित है।
  - WCO दुनिया भर के 183 सीमा शुल्क प्रशासनों का प्रतिनिधित्व करता है, इनके द्वारा विश्व में सामूहिक रूप से लगभग 98% व्यापार किया जाता है।
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली को एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये विश्व सीमा शुल्क संगठन की क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला के रूप में मान्यता दी गई। अत: कथन 2 सही है।
- भारत को दो साल की अवधि के लिये (जून 2020 तक) WCO के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष (क्षेत्रीय प्रमुख) बनाया गया था।
  - यह सीमा शुल्क मामलों को देखने में सक्षम एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसलिये इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क समुदाय की आवाज़ कहा जा सकता है।

186.

उत्तर: D

व्याख्या:

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme- UNEP) ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट (Food Waste Index Report), 2021 जारी की। अत: विकल्प (D) सही है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में खाने के लिये उपलब्ध भोजन का 17% (घरों में 11%, खाद्य सेवा में 5% और खुदरा क्षेत्र में 2%) बर्बाद हो गया और लगभग 69 करोड़ लोगों को खाली पेट सोना पड़ा था।
  - इस रिपोर्ट में वैश्विक खाद्य अपव्यय का सबसे व्यापक और विश्लेषित डेटा प्रस्तुत होता है।
  - यह देशों के लिये घरेलू खाद्य सेवा और खुदरा स्तर पर खाद्य अपशिष्ट को मापने हेतु एक पद्धति भी प्रकाशित करता है।
  - फूड लॉस इंडेक्स (Food Loss Index) के विपरीत फूड वेस्ट इंडेक्स कुल खाद्य अपशिष्ट (विशिष्ट वस्तुओं से जुड़े नुकसान या कचरे के बजाय) को मापता है।

187.

उत्तर.B

व्याख्या:

- EPFO कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम (Miscellaneous Provisions Act), 1952 को लागू करता है।
- EPFO अधिनियम, 1952 कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को संस्थागत भविष्य निधि प्रदान करता है।
- कर्मचारी के मूल वेतन और महँगाई भत्ते का 12% कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही ईपीएफ में जमा करते हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2016-17 में सुझाव दिया गया था कि कर्मचारियों को अपने वेतन का 12% EPFO में जमा करने या इसे वेतन के रूप में प्राप्त करने का विकल्प को चुनने की अनुमति दी जाए।
- EPFO योजना उन कर्मचारियों के लिये अनिवार्य है जिनका मूल वेतन प्रतिमाह 15,000 रुपए तक है। अत: कथन 2 सही है।

188.

उत्तर: C

व्याख्या:

- केंद्र सरकार द्वारा बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman) की स्थापना बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम (Insurance Regulatory and Development Authority Act), 1999 तथा लोक शिकायत निवारण नियम (Redressal of Public Grievances Rules), 1998 के अंतर्गत की गई।
- इसकी शक्तियाँ, कार्य, कार्यालय की शर्तें आदि बीमा लोकपाल नियम, 2017 द्वारा निर्धारित किये गए थे। अत: कथन 1 सही है।
- इसका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है और अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक यह पद धारण करता है, इसकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा लोकपाल नियम (Insurance Ombudsman Rules), 2017 में संशोधन किया है। इस संशोधन के माध्यम से बीमा लोकपाल के दायरे में बीमा दलालों को लाया गया है और पॉलिसीधारकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की भी अनुमति दी गई है। अत: कथन 3 सही है।

189.

उत्तर: C

व्याख्या:

- ट्रांस यूनियन सिबिल (TransUnion CIBIL) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के साथ संयुक्त रूप से 'MSME क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स' लॉन्च किया है। अत: कथन 1 सही है।
- यह सूचकांक भारत के MSME उद्योग की क्रेडिट स्थिति को दो मापदंडों पर मापता है- वृद्धि और क्षमता। अत: कथन 2 सही है
  - समय के साथ एक्सपोज़र वैल्यू (बकाया शेष) में बढ़ोतरी के अनुसार वृद्धि को मापा जाता है।
  - बढ़ता ग्रोथ इंडेक्स क्रेडिट ग्रोथ में सुधार का संकेत देता है।
  - गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के संदर्भ में क्रेडिट जोखिम में कमी/वृद्धि से क्षमता को मापा जाता है।

190.

उत्तर: B

व्याख्या:

- हाल ही में इनसॉल्वेंसी लॉ कमेटी (ILC) की एक उपसमिति द्वारा 'दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड' (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC), 2016 के मूल ढाँचे के भीतर प्री-पैक ढाँचे (Pre-Pack Framework) की सिफारिश की गई है।
- प्री-पैक का आशय एक सार्वजनिक बोली प्रक्रिया के बजाय सुरक्षित लेनदारों और निवेशकों के बीच एक समझौते के माध्यम से तनावग्रस्त कंपनी के ऋण के समाधान से है। अत: विकल्प (B) सही है।
  - पिछले एक दशक में ब्रिटेन और यूरोप में इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन (Insolvency Resolution) हेतु यह व्यवस्था काफी लोकप्रिय हुई है।
- भारत के मामले में ऐसी प्रणाली के तहत वित्तीय लेनदारों को संभावित निवेशकों से सहमत होना अनिवार्य होगा और समाधान योजना हेतु नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की मंज़ूरी लेनी भी आवश्यक होगी।

191.

उत्तर: D

व्याख्या:

- वर्तमान में खुदरा भुगतान प्रणाली प्रदान करने हेतु NPCI एक अम्ब्रेला एंटिटी है, जो बैंकों के स्वामित्व वाली एक गैर-लाभकारी इकाई है। अत: कथन 1 सही है।
  - यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक पहल है। अत: कथन 2 सही है।
- इसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत 'गैर-लाभकारी संगठन' के रूप में शामिल किया गया है। अत: कथन 3 सही है।
- दस प्रमुख प्रवर्तक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक और एचएसबीसी हैं।

192.

उत्तर: A

व्याख्या:

- उपकर (Cess), उत्पाद शुल्क और व्यक्तिगत आयकर जैसे सामान्य करों तथा शुल्कों से अलग 'कर के ऊपर लगने वाला कर' है जो आमतौर पर विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लगाया जाता है। अत: कथन 1 सही है।
- केंद्र सरकार को करों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों), अधिभार, शुल्क, उपकर, लेवी आदि के माध्यम से राजस्व जुटाने का अधिकार है।
  - सामान्यत: जनता द्वारा भुगतान किया जाने वाला उपकर, उनके कर देयता में जोड़ा जाता है, जो कुल कर भुगतान के हिस्से के रूप में अदा किया जाता है।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-270 के तहत उपकर को उन करों के विभाज्य पूल (Divisible Pool of Taxes) के दायरे से बाहर रखने की अनुमति दी गई है जिन्हें केंद्र सरकार को राज्यों के साथ साझा करना अनिवार्य है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- उपकर को संचित निधि (Consolidated Fund) में एक अलग निधि के रूप में रखा जाना चाहिये, जिसे केवल विशिष्ट उद्देश्य के लिये खर्च किया जाता है।

- उपकर, सरकार के राजस्व को बढ़ाने का एक अस्थायी स्रोत है।
  - उपकर का उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद इस पर रोक लगा दी जाती है।

193.

उत्तर: (A)

व्याख्या

- खुला बाज़ार परिचालन का आशय सरकार द्वारा मुक्त बाज़ार में जारी किये गए बॉण्ड की बिक्री एवं खरीद से है। अत: कथन 1 सही है।
  - मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरण: यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रयोग किये जाने वाला एक मात्रात्मक मौद्रिक उपकरण है, जिसका उपयोग RBI द्वारा वर्ष भर तरलता की संतुलित स्थिति को बनाए रखने और ब्याज़ दर तथा मुद्रास्फीति के स्तर पर इसके प्रभाव को सीमित करने के लिये किया जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - मात्रात्मक मौद्रिक नीति उपकरण का आशय ऐसे उपकरणों से है, जो नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और बैंक दर आदि में परिवर्तन करके मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं।

194.

उत्तर: B

व्याख्या:

- स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉज़िटरी और समाशोधन निगम को सामूहिक रूप से मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन प्रतिभूति के रूप में संदर्भित किया जाता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - बिमल जालान समिति, 2010 के अनुसार, ये संस्थान देश के वित्तीय विकास के लिये महत्त्वपूर्ण हैं जो प्रतिभूति बाज़ार हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचे के रूप में काम करते हैं।
- भारत में शेयर बाज़ार (Stock Exchange) एक ऐसे बाज़ार के रूप में कार्य करता है जहाँ स्टॉक, बॉण्ड और कमोडिटी जैसे वित्तीय दस्तावेज़ों का कारोबार होता है। अत: कथन 2 सही है।

195.

उत्तर: A

व्याख्या:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा पेश की जाने वाली 'बिज़नेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग' के लिये नई आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।
- इस नई रिपोर्ट को 'बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट' (BRSR) कहा जाएगा और यह मौजूदा बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट (BRS) का स्थान लेगी। अत: विकल्प A सही है।
- BRSR जो कि पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) के दृष्टिकोण पर आधारित एक रिपोर्ट है, का उद्देश्य व्यवसायों को अपने हितधारकों के साथ अधिक सार्थक रूप से संलग्न करने में सक्षम बनाना है।
- यह व्यवसायों को विनियामक वित्तीय अनुपालन करने और उनके सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों पर रिपोर्ट करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये स्वैच्छिक आधार पर और वित्तीय वर्ष 2022-23 से अनिवार्य आधार पर BRSR शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं (बाज़ार पूंजीकरण द्वारा) पर लागू होगा।

196.

उत्तर -B

व्याख्या :

- कंपनी अधिनियम, 2013 एक भारतीय कंपनी कानून है, जो एक कंपनी के निगमन, जिम्मेदारियों, निदेशकों और शेयरधारकों के साथ ही इसके विघटन संबंधी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अत: कथन 1 सही है।
  - कंपनी अधिनियम 2013 में शामिल प्रावधान केवल सूचीबद्ध कंपनियों के छोटे शेयरधारकों (अल्पसंख्यक शेयरधारकों को छोड़कर) के अधिकारों की रक्षा करते हैं, ताकि ऐसी कंपनियों को अपने बोर्ड में कम-से-कम एक निदेशक को ऐसे छोटे शेयरधारकों द्वारा चुना जा सके। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - कंपनी अधिनियम के अनुसार, छोटे शेयरधारक वे शेयरधारक या शेयरधारकों के समूह हैं जो केवल 20,000 रुपए से कम मूल्य के शेयर रखते हैं।
- अल्पसंख्यक शेयरधारक किसी फर्म या कंपनी के इक्विटी धारक हैं। यदि ये किसी फर्म की इक्विटी पूंजी के 50% से कम का स्वामित्व रखते है तो उन्हें फर्म में अपने मताधिकार शक्ति का उपयोग करने से वंचित होना पड़ता है।

197.

उत्तर: C

व्याख्या:

- ट्रांस यूनियन सिबिल (TransUnion CIBIL) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के साथ संयुक्त रूप से 'MSME क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स' लॉन्च किया है। अत: कथन 1 सही है।
- यह सूचकांक भारत के MSME उद्योग की क्रेडिट स्थिति को दो मापदंडों पर मापता है- वृद्धि और क्षमता। अत: कथन 2 सही है
  - समय के साथ एक्सपोज़र वैल्यू (बकाया शेष) में बढ़ोतरी के अनुसार वृद्धि को मापा जाता है।
  - बढ़ता ग्रोथ इंडेक्स क्रेडिट ग्रोथ में सुधार का संकेत देता है।
  - गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के संदर्भ में क्रेडिट जोखिम में कमी/वृद्धि से क्षमता को मापा जाता है।

198.

उत्तर: A

व्याख्या:

थोक मूल्य सूचकांक (WPI)

- यह व्यापारियों द्वारा थोक में बेचे गए सामानों की कीमतों में बदलाव को मापता है।
- यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है।
- वर्ष 2017 में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार वर्ष को संशोधित कर वर्ष 2004-05 से वर्ष 2011-12 कर दिया गया था।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

- यह सूचकांक खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के तहत भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं जैसे- खाद्य, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद आदि की कीमत में परिवर्तन की गणना करता है।
- वर्ष 2012 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है।

थोक मूल्य सूचकांक बनाम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

- WPI का प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का प्रकाशन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा किया जाता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- WPI सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को नहीं मापता, जबकि CPI में सेवाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- WPI, उत्पादक स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है, जबकि CPI उपभोक्ता स्तर पर कीमतों में परिवर्तन को मापता है। अत: कथन 3 सही है।

199.

उत्तर: B

व्याख्या:

- लघु वित्त बैंक वे वित्तीय संस्थान हैं जो देश के उन क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं जहाँ बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध नहीं है। अत: कथन 1 सही है।
- लघु वित्त बैंक, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं। अत: कथन 2 सही है।
- लघु वित्त बैंक मुख्य रूप से लघु व्यावसायिक इकाइयों, लघु और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को वित्तीय समावेशन जैसे- जमा करने और ऋण देने की बुनियादी बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करेगा। अत: कथन 3 सही नहीं है।
  - यह अन्य गैर-जोखिम साझाकरण सरल वित्तीय सेवाओं से संबंधित गतिविधियों को भी अपने अंतर्गत ले सकता है, जिसमें स्वयं की निधियों जैसे - म्यूचुअल फंड इकाइयों, बीमा उत्पादों, पेंशन उत्पादों के वितरण की प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं होती है।
  - लघु वित्त बैंक विदेशी मुद्रा व्यापार में अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के लिये एक अधिकृत डीलर भी बन सकता है।

200.

उत्तर: C

व्याख्या:

- भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज़ है।
  - आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज़ मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- इसमें भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित आधिकारिक और अद्यतन डेटा स्रोत को शामिल किया जाता है।
  - यह सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रस्तुत एक रिपोर्ट है जो कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों को प्रस्तुत करती है।
  - यह आमतौर पर संसद में केंद्रीय बजट पेश किये जाने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

- भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 से इसे बजट से अलग कर दिया गया।

201.

उत्तर: C

व्याख्या:

- सरकार का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) दिसंबर 2020 के अंत में बजट अनुमान (Budget Estimate- BE) से बढ़कर 11.58 लाख करोड़ या 145.5% (वर्ष 2020-21 के पहले नौ महीनों का लेखा-जोखा) हो गया है।
- उच्च राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के लिये लाभकारी हो सकता है यदि खर्च किये गए धन का उपयोग राजमार्गों, सड़कों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों जैसी उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं और जिनके परिणामस्वरूप रोज़गार सृज़न को बढ़ावा मिलता हो, में किया गया हो।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 यह प्रावधान करता है कि केंद्र को 31 मार्च, 2021 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक सीमित करने हेतु उचित उपाय करना चाहिये। अत: कथन 1 सही है।
- केंद्र और राज्यों के लिये राजकोषीय समेकन का रोडमैप बनाने के लिये एन.के. सिंह समिति का गठन किया गया था।
  - वर्ष 2016 में गठित एनके सिंह समिति (NK Singh Committee) द्वारा सिफारिश की गई कि सरकार को 31 मार्च, 2020 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक लक्षित किया जाना चाहिये, जिसे वर्ष 2020-21 में 2.8% और वर्ष 2023 तक 2.5% तक कम करना चाहिये। अत: कथन 2 सही है।

202.

उत्तर: C

व्याख्या :

बजट और संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement- AFS) कहा जाता है। अत: कथन 1 सही है।
- यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है (जो चालू वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है)।
- संसद में बजट छह चरणों से गुज़रता है:
  - बजट की प्रस्तुति।
  - आम चर्चा।
  - विभागीय समितियों द्वारा जाँच।
  - अनुदान मांगों पर मतदान।
  - विनियोग विधेयक पारित करना।
  - वित्त विधेयक पारित करना। अत: कथन 3 सही नहीं है।
- वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का बजट डिवीज़न बजट तैयार करने हेतु ज़िम्मेदार केंद्रीय निकाय है।
  - स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में प्रस्तुत किया गया था। अत: कथन 2 सही नहीं है।

203.

उत्तर: C

व्याख्या:

समर्पित माल ढुलाई गलियारा (DFC):

- यह एक उच्च गति और उच्च क्षमता वाला रेलवे कॉरिडोर है जो विशेष रूप से माल और वस्तुओं के परिवहन के लिये समर्पित है। अत: कथन 1 सही है।
  - डीएफसी के तहत बेहतर बुनियादी ढांचे और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का सहज एकीकरण शामिल है।
- समर्पित माल ढुलाई गलियारे (DFC) के दो घटक हैं, पूर्वी DFC और पश्चिमी DFC:
  - पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (EDFC):
    - यह पंजाब में साहनेवाल (लुधियाना) से शुरू होता है और पश्चिम बंगाल के दनकुनी में समाप्त होता है।
  - पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (WDFC):
    - DFC का दूसरा भाग-पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा उत्तर प्रदेश के दादरी से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक लगभग 1,500 किलोमीटर की दूरी तक फैला है जो सभी प्रमुख बंदरगाहों है।
- हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया गया। यह भारत का पहला डिजिटल बजट है। इसके तहत रेलवे के लिये लक्षित प्रमुख प्रस्तावों में कुछ निम्नलिखित हैं:
- राष्ट्रीय रेल योजना (2030): वर्ष 2030 तक 'फ्यूचर रेडी' (Future Ready) रेलवे प्रणाली की स्थापना हेतु।
- दिसंबर 2023 तक ब्रॉड-गेज मार्गों पर शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य पूरा करना।
- पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे (WDFC) और पूर्वी DFC को जून 2022 तक चालू करना। अत: कथन 2 सही है।

204.

उत्तर: (A)

व्याख्या

- हाल ही में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें केंद्र और राज्यों दोनों के वित्तीय घाटे और ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर सिफारिशें प्रदान की गई हैं। अत: कथन 1 सही है।
- केंद्र के लिये लक्ष्य: 15वें वित्त आयोग द्वारा यह अनुशंसा की गई है कि केंद्र सरकार राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2022 के सकल घरेलू उत्पाद के 6.8% से वर्ष 2025-26 में 4% तक ले आएगी। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- राज्यों के लिये लक्ष्य: राज्यों के लिये 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 4%, उसके अगले वर्ष में 3.5% और बाद के अगले तीन वर्षों के लिये 3% राजकोषीय घाटे की सिफारिश की।

205.

उत्तर: C

व्याख्या:

- बजट 2021-22 में परिसंपत्ति पुनर्निमाण कंपनी (Asset Reconstruction Company- ARC) को राज्य के स्वामित्व वाले और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है तथा कहा गया है कि सरकार इसमें कोई इक्विटी योगदान नहीं देगी। अत: कथन 3 सही नहीं है।
- यह एक विशेष वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से 'नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स' (Non Performing Assets-NPAs) खरीदता है ताकि वे अपनी बैलेंसशीट को स्वच्छ रख सकें। अत: कथन 1 सही है।
- सरफेसी अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act, 2002) भारत में ARCs की स्थापना के लिये कानूनी आधार प्रदान करता है। अत: कथन 2 सही है।

206.

उत्तर. B

व्याख्या:

- हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने खुदरा निवेशकों को बिचौलियों की मदद के बिना सीधे सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securit-G-secs) में निवेश करने के लिये अपने यहाँ खाते खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है।
- सरकारी प्रतिभूतियाँ (G-secs) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाने वाली व्यापार योग्य उपकरण.साधन है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- भारत में केंद्र सरकार ट्रेज़री बिल और बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों को जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDL) कहा जाता है। अत: कथन 2 सही है।
- G-secs में प्रायोगिक रूप से कोई जोखिम नहीं होता इसलिये इन्हें जोखिम रहित श्रेष्ठ प्रतिभूति माना जाता है। अत: कथन 3 सही है।

207.

उत्तर: A

व्याख्या:

- केंद्रीय बजट 2021 के तहत आगामी वित्तीय 2021-22 में दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की है।
- कई समितियों ने सार्वजनिक बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव दिया है:
- नरसिम्हन समिति, 1998
  - प्रमुख बैंकों के विलय का उद्योगों पर 'गुणक प्रभाव' होगा।
  - भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार करने हेतु समिति ने पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को बढ़ाने की सिफारिश की थी।
  - प्रबंधन और स्वामित्त्व के रूप में बैंकों पर सरकारी नियंत्रण और बैंकों की स्वायत्तता के बीच असंतुलन की जाँच करने के लिये एक पेशेवर कॉर्पोरेट रणनीति अपनाने हेतु बोर्डों के कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिये।
- पी. जे. नायक समिति
  - कंपनी अधिनियम के अनुरूप सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों का कंपनी के गठन।
  - कंपनी अधिनियम के अधीन एक बैंक निवेश कंपनी (BIC) का गठन करना और PSBs में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को BIC को हस्तांतरित करना।
  - बैंक निवेश कंपनी (BIC) को PSBs के बोर्डों के नियंत्रण की शक्ति दी जानी चाहिये।
  - सभी शेयरधारकों को आनुपातिक मतदान का अधिकार और सरकारी हिस्सेदारी में 40% की कमी।
- अभिजीत सेन समिति (2002) भारत की दीर्घकालिक खाद्य नीति से संबंधित है।
- अभिजीत सेन समिति (2007) का गठन कृषि वस्तु की कीमतों (न कि बैंकिंग सुधार नहीं) पर वायदा कारोबार के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये किया गया था। अत: विकल्प A सही है।

208.

उत्तर. C

व्याख्या:

- हाल ही में ब्रेंट क्रूड आयल की कीमत एक साल के बाद 60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई है। ब्रेंट क्रूड आयल की कीमत में वृद्धि तेल उत्पादक देशों द्वारा उत्पादन में कटौती और कोविड-19 का टीका आने के बाद वैश्विक मांग में सुधार की उम्मीद के कारण देखी गई है।
- तेल की कीमत में वृद्धि का भारत पर प्रभाव:
  - चालू खाता घाटा: देश के आयात बिल में तेल की कीमतों में वृद्धि से बढ़ोतरी होगी, जिससे चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) और बढ़ जाएगा। अत: कथन 1 सही है।
    - तेल बिल में प्रतिवर्ष कच्चे तेल की कीमत में एक डॉलर की बढ़ोतरी से लगभग 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होती है।
    - भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का 80% हिस्सा आयात करता है और भारत में जनवरी 2021 से कच्चे तेल की कीमत 54.8 डॉलर प्रति बैरल हो गई है।
- तेल की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो सरकार को पेट्रोलियम और डीज़ल पर करों में कटौती करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा, जिससे राजस्व का नुकसान हो सकता है। अत: राजकोषीय संतुलन (Fiscal Balance) बिगड़ सकता है।
- भारत को तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से लाभ भी हो सकता है।
  - भारतीय तेल और गैस कंपनियों के मूल्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सरकार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में विनिवेश (Disinvestment) से अधिक राशि प्राप्त हो सकती है। अत: कथन 2 सही है।
  - भारतीयों द्वारा फारस की खाड़ी से भेजी जाने वाली धनराशि बढ़ सकती है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

209.

उत्तर: (A)

व्याख्या

- विश्व खाद्य सुरक्षा समिति (CFS) सभी हितधारकों की खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने हेतु एक साथ काम करने के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और अंतर-सरकारी मंच है।
- यह समिति आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र (UN) महासभा को और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) सम्मेलन को रिपोर्ट करती है। अत: कथन 1 सही है।
- विश्व खाद्य सुरक्षा समिति (CFS) द्वारा 'खाद्य और कृषि संगठन' के रोम स्थित मुख्यालय में प्रत्येक वर्ष अक्तूबर माह में एक वार्षिक सत्र का आयोजन किया जाता है।
- विश्व खाद्य सुरक्षा समिति को 'खाद्य और कृषि संगठन', 'इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट' (IFAD) और 'वर्ल्ड फूड प्रोग्राम' (WFP) द्वारा समान रूप से वित्तपोषित किया जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

210.

उत्तर: D

व्याख्या:

- एफपीआई को प्राय: "हॉट मनी" (Hot Money) कहा जाता है क्योंकि इसमें अर्थव्यवस्था से पलायन करने की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। अत: कथन 1 सही है।
  - एफडीआई, एफपीआई की तुलना में अधिक तरल और कम जोखिम भरा होता है।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) में प्रतिभूतियाँ और विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी गई अन्य वित्तीय संपत्तियाँ शामिल हैं। यह निवेशक को वित्तीय परिसंपत्तियों में सीधे स्वामित्व प्रदान नहीं करता है और बाज़ार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत तरल है। अत: कथन 2 सही है।
  - उदाहरण: स्टॉक, बॉण्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अमेरिकन डिपॉज़िटरी रिसिप्ट (एडीआर), ग्लोबल डिपॉज़िटरी रिसिप्ट (जीडीआर) आदि।
- FPI से संबंधित अन्य विवरण:
  - FPI किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा होता है और यह उस देश के भुगतान संतुलन (BOP) की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अत: कथन 3 सही है।
    - बीओपी सामान्यतया एक वर्ष की समयावधि के दौरान किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी मौद्रिक लेन-देनों के लेखांकन का विवरण होता है।
    - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा वर्ष 2014 के नए एफपीआई विनियमों की जगह वर्ष 2019 में नया एफपीआई विनियम लाया गया।

211.

उत्तर: C

व्याख्या:

- हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा 'ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसएबिलिटीज़: द बर्डन ऑन इंडिया सोसाइटी' (Traffic Crash Injuries And Disabilities: The Burden on India Society) शीर्षक से विश्व बैंक (World Bank) की रिपोर्ट जारीकी गई है। अत: विकल्प C सही है।

- इस रिपोर्ट को एनजीओ- सेव लाइफ फाउंडेशन (Save Life Foundation) के सहयोग से तैयार किया गया है।
- सर्वेक्षण में शामिल किये गए आँकड़ों को भारत के चार राज्यों- उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से एकत्र किया गया था।

212.

उत्तर: B

व्याख्या:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) को निर्देश जारी किया गया है।
- एचएफसी एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (Non-Banking Financial Company) है, जिसकी वित्तीय संपत्ति का लगभग 60% का उपयोग आवासीय व्यवसाय के वित्तपोषण में जाता है। अत: कथन 1 सही है।
- आरबीआई द्वारा एचएफसी की नई परिभाषा दी गई है।
  - एक एनबीएफसी के पास एचएफसी के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिये आवास ऋण के रूप में 50% और व्यक्तिगत आवास खरीदारों के लिये 75% संपत्ति होनी चाहिये। अत: कथन 3 सही है।
- आरबीआई द्वारा वर्ष 2019 में नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) से HFCs को रेगुलेट करने का अधिकार ले लिया। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- आरबीआई द्वारा दिये गए निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, इन निर्देशों का लक्ष्य HFCs के कामकाज से निवेशकों और जमाकर्त्ताओं के हितों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना है।

213.

उत्तर: (C)

व्याख्या

- ब्लू इकॉनमी की अवधारणा को बेल्ज़ियम के अर्थशास्त्री गुंटर पौली द्वारा वर्ष 2010 में प्रकाशित उनकी पुस्तक 'द ब्लू इकॉनमी: 10 इयर्स, 100 इनोवेशन्स और 100 मिलियन जॉब्स' में प्रस्तुत किया गया था। अत: कथन 1 सही है।
- यह अवधारणा आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के सृजन तथा महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिये महासागर संसाधनों का सतत् उपयोग को संदर्भित करती है। अत: कथन 2 सही है।
- ब्लू इकॉनमी, महासागरीय अर्थव्यवस्था के विकास को सामाजिक समावेश और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ एकीकृत करने पर ज़ोर देती है।

214.

उत्तर: D

व्याख्या:

MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये नवीन पहलें:

- उद्योग आधार ज्ञापन (UAM): यह भारत में MSMEs के लिये व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करने हेतु सरल एक-पृष्ठ का पंजीकरण फॉर्म है।
- नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु एक योजना (ASPIRE): यह योजना 'कृषि आधारित उद्योग में स्टार्टअप के लिये फंड ऑफ फंड्स', ग्रामीण आजीविका बिज़नेस इनक्यूबेटर (LBI), प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (TBI) के माध्यम से नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देती है।
- क्रेडिट गारंटी फंड योजना: ऋण के आसान प्रवाह की सुविधा के लिये MSMEs को दिये गए संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिये गारंटी कवर प्रदान किया जाता है।
- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP): यह नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना और ग्रामीण एवं देश के शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (CLCSS): CLCSS का उद्देश्य संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिये 15% पूंजी सब्सिडी प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) को प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है। अत: विकल्प D सही है।

215.

उत्तर: D

व्याख्या:

- बड़ी संख्या में किसान अपनी आजीविका के लिये पशुपालन पर निर्भर हैं। इससे ग्रामीण आबादी के लगभग 55% लोगों को आजीविका मिलती है। आर्थिक सर्वेक्षण-2021 के अनुसार, सकल मूल्य वर्द्धन (निरंतर कीमतों पर) के संदर्भ में कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुधन का योगदान 24.32% (2014-15) से बढ़कर 28.63% (2018-19) हो गया है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- भारत में विश्व का सबसे अधिक पशुधन है। भारत में 20वीं पशुधन जनगणना (20th Livestock Census) के अनुसार, देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है। इस पशुधन जनगणना में वर्ष 2018 की जनगणना की तुलना में 4.6% की वृद्धि हुई है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

216.

उत्तर (A)

व्याख्या:

- ब्लैंक-चेक कंपनी, विशेष रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र में किसी फर्म के अधिग्रहण के उद्देश्य से स्थापित की गई इकाई होती है। अत: कथन 1 सही है।
  - इनको विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी (Special Purpose Acquisition Company- SPAC) के नाम से भी जाना जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- SPAC का उद्देश्य एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (Initial Public Offering- IPO) के माध्यम से धन जुटाना होता है लेकिन उसके पास कोई संचालन या राजस्व नहीं होता है।
  - इसके अंतर्गत निवेशकों से धन लेकर एस्क्रो अकाउंट (Escrow Account) में रखा जाता है, जिसका उपयोग अधिग्रहण करने में किया जाता है।
  - अगर आईपीओ के दो वर्ष के भीतर अधिग्रहण नहीं किया जाता है, तो SPAC को हटा दिया जाता है और धन को निवेशकों को लौटा दिया जाता है।
- शेल कंपनी एक ऐसी फर्म होती है जिसका अर्थव्यवस्था में कोई संचालन नहीं होता है, लेकिन यह औपचारिक रूप से पंजीकृत, निगमित और कानूनी रूप से विद्यमान होती है।

217.

उत्तर: A

व्याख्या:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भारतीय प्रतिभूति बाज़ार में 'मान्यता प्राप्त निवेशक' (Accredited Investor) की अवधारणा पेश करने के प्रस्ताव पर संबंधित पक्षों की राय मांगी है।
- वर्तमान में भारतीय बाज़ारों में योग्य संस्थागत खरीदारों (Qualified Institutional Buyer) की अवधारणा मौजूद है, इसमें म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ या अन्य पोर्टफोलियो निवेशक शामिल होते हैं। इन निवेशकों को बाज़ार में अधिक पहुँच प्राप्त है। अत: कथन 1 सही है।
- एक व्यक्तिगत निवेशक QIB का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता है। मान्यता प्राप्त निवेशक की अवधारणा व्यक्तिगत निवेशकों को QIB जैसी स्थिति प्रदान करेगी। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- योग्य संस्थागत खरीदार: ये संस्थागत निवेशक होते हैं। इनको पूंजी बाज़ार में निवेश और मूल्यांकन करने में विशेषज्ञता प्राप्त होती है।

218.

उत्तर: D

व्याख्या:

- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
  - सेबी एक अर्द्ध-विधायी, अर्द्ध-न्यायिक और अर्द्ध-कार्यकारी निकाय है।
- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में एक पीठासीन अधिकारी और दो अन्य सदस्य होते हैं।
  - केंद्र सरकार द्वारा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को भारत का मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) या उसके द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पास सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ होती हैं। इसके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में अपील की जा सकती है।

219.

उत्तर: A

व्याख्या:

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा देश में डिजिटल/कैशलेस भुगतान की स्थिति के अध्ययन के लिये एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (Digital Payments Index-DPI) जारी किया गया है। अत: विकल्प A सही है।
- सूचकांक के बारे में:
  - RBI द्वारा DPI के मापन में 5 व्यापक पैरामीटर्स को शामिल किया गया है जो देश में विभिन्न समयावधि में हुए डिजिटल भुगतान का गहन अध्ययन करने में सक्षम हैं।
  - 5 व्यापक पैरामीटर्स:
    - भुगतान एनेबलर्स (वज़न 25%)
    - भुगतान अवसंरचना - मांग पक्ष कारक (10%)
    - भुगतान अवसंरचना - आपूर्ति पक्ष कारक (15%)
    - भुगतान प्रदर्शन (45%)
    - उपभोक्ता केंद्रित (5%)।

220.

उत्तर. C

व्याख्या:

- हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने भुगतान अवसंरचना विकास कोष (Payment Infrastructure Development Fund- PIDF) योजना के संचालन की घोषणा की है।
- इसका उद्देश्य देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के साथ ही टियर-3 से टियर-6 शहरों (केंद्रों) में भुगतान स्वीकृति अवसंरचना का विकास करना है।
- PIDF के प्रबंधन के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद (AC) का गठन किया गया है।
- वित्त का उपयोग भुगतान अवसंरचना को अभिनियोजित करने के लिये बैंकों और गैर-बैंकों को सब्सिडी देने हेतु किया जाएगा, जो विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रासंगिक होगा। अत: कथन 1 सही है।
- सलाहकार परिषद विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों में बैंकों तथा गैर-बैंकों के अधिग्रहण के लक्ष्य के आधार पर आवंटन के लिये एक पारदर्शी तंत्र तैयार करेगी।
  - लक्ष्य के कार्यान्वयन की निगरानी RBI द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक एसोसिएशन (IBA) और पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) की सहायता से की जाएगी। अत: कथन 2 सही है।
  - अधिग्राही बैंक (अधिग्राहक अथवा व्यापारी बैंक भी) किसी व्यापारी या व्यवसाय की ओर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेन-देन करने वाले वित्तीय संस्थान हैं।

221.

उत्तर.C

व्याख्या:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी मिलने के बाद देश में 3.92 लाख करोड़ रुपए की लागत की रेडियो तरंगों के स्पेक्ट्रम की नीलामी के छठे दौर के लिये बोली लगाने की प्रक्रिया 1 मार्च, 2020 से शुरू होगी।
  - लंबे समय से प्रतीक्षित यह स्पेक्ट्रम नीलामी चार वर्ष के अंतराल और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा रेडियो तरंगों के लिये आधार/आरक्षित मूल्य की गणना तथा इनकी अनुशंसा किये जाने के दो वर्षों से अधिक समय के बाद आयोजित की जा रही है।
- देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सभी संपत्तियों का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है, जिसमें एयरवेव्स भी शामिल हैं। अत: कथन 1 सही है।
- इस बुनियादी ढाँचे को तैयार करने की इच्छुक कंपनियों को इन संपत्तियों को बेचने के लिये केंद्र सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग (संचार मंत्रालय) के माध्यम से समय-समय पर इन एयरवेव्स की नीलामी की जाती है।
- इन एयरवेव्स को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसे अलग-अलग आवृत्ति के बैंडों में विभाजित किया जाता है।
- इन सभी एयरवेव्स को एक निश्चित अवधि के लिये बेचा जाता है, जिसके बाद उनकी वैधता समाप्त हो जाती है, यह अवधि आमतौर पर 20 वर्षों के लिये निर्धारित की जाती है। अत: कथन 2 सही है।

222.

उत्तर.B

व्याख्या:

- हाल ही में संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (United States Trade Representative- USTR) ने कहा है कि भारत, इटली और तुर्की द्वारा अपनाए गए डिजिटल सेवा कर (Digital services taxes-DSTs) अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कर सिद्धांतों के असंगत हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- डिजिटल सेवा कर कंपनियों द्वारा डिजिटल सेवाएँ प्रदान करने के बदले प्राप्त राजस्व पर अधिरोपित किया जाता है। यह कर मुख्य तौर पर गूगल, अमेज़न और एप्पल जैसी डिजिटल बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लागू होता है।
- सरकार ने वित्त विधेयक 2020-21 में 2 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने वाले गैर-निवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा किये जाने वाले व्यापार और सेवाओं पर 2 प्रतिशत डिजिटल सेवा कर (DST) लागू करने हेतु एक संशोधन किया था। अत: कथन 2 सही है।

223.

उत्तर.C

व्याख्या

- हाल ही में जिनेवा स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Trade Organization- WTO) द्वारा भारत की सातवीं व्यापार नीति समीक्षा की गई है।
- वर्तमान में, विकासशील देशों के सार्वजनिक वितरण कार्यक्रमों को अंबर बॉक्स उपायों के तहत शामिल किया गया है। अत: कथन 1 सही है।
- अन्य विकासशील देशों के साथ भारत भी यह मांग कर रहा है कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों को WTO की सब्सिडी कटौती प्रतिबद्धताओं से मुक्त किया जाना चाहिये।

- भारत ने सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग संबंधी मुद्दों के लिये एक स्थायी समाधान की मांग की है।

व्यापार नीति समीक्षा तंत्र

- व्यापार नीति समीक्षा तंत्र (Trade Policy Review Mechanism-TPRM) उरुग्वे राउंड (Uruguay Round) का शुरुआती परिणाम था। अत: कथन 2 सही है।
- यह सदस्य देशों की व्यापार नीतियों और प्रथाओं के सामूहिक मूल्यांकन की प्रक्रिया हेतु एक अवसर प्रदान करता है।
- उद्देश्य:
  - सदस्य देशों की व्यापार नीति की पारदर्शिता को बढ़ाकर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के सुचारु कामकाज में सहायता करना।
  - बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली पर एक सदस्य देश की व्यापार नीतियों और प्रथाओं के प्रभाव की जाँच करना।

224.

उत्तर: (B)

व्याख्या:

- भारत विश्व में अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक होने के साथ-साथ सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है।
- महत्त्वपूर्ण अनाजों में गेहूँ, धान, सोरगम, जुआर (बाजरा), जौ और मक्का शामिल हैं।
- इससे पहले वर्ष 2008 में भारत ने घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिये चावल और गेहूँ आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था।
  - भारत में अधिशेष उत्पादन और वैश्विक बाज़ार में भारी मांग को देखते हुए सरकार ने गेहूँ के सीमित निर्यात की अनुमति दी।
- भारत के कुल अनाज निर्यात में चावल (बासमती और गैर-बासमती सहित) वर्ष 2019-20 में प्रमुख हिस्सेदारी (95.7%) रखता है, जबकि भारत से निर्यात किये गए कुल अनाज में गेहूँ सहित अन्य अनाजों की वर्ष 2019-20 में केवल 4.3% की हिस्सेदारी थी। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- भारत से गेहूँ का अधिकांश निर्यात (2019-20) नेपाल, बांग्लादेश, UAE, सोमालिया को किया गया।
- भारत से गैर-बासमती चावल का अधिकांश निर्यात (2019-20) नेपाल, बेनिन, संयुक्त अरब अमीरात, सोमालिया को हुआ। अत: कथन 2 सही है।
- भारत से बासमती चावल का अधिकांश निर्यात (2019-20) ईरान, सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात को किया गया।

225.

उत्तर: B

व्याख्या:

- हाल ही में 'नोमुरा इंडिया नॉर्मलाइज़ेशन इंडेक्स' (Nomura India Normalization Index- NINI) के नवीनतम अध्ययन में भारतीय अर्थव्यवस्था पर COVID-19 तथा K-शेप्ड रिकवरी के प्रभाव संबंधी आँकड़े प्रस्तुत किये गए हैं।
- 'इकोनॉमिक रिकवरी' के कई रूप होते हैं, जिसे वर्णमाला संकेतन का उपयोग करके दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिये, Z-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, V-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, U-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, U-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, W-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, L-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी और K-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी।
  - Z-आकार की रिकवरी: यह सबसे आशावादी परिदृश्य होता है जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तेजी से वृद्धि होती है।
    - Z- शेप चार्ट, सामान्य पृवत्ति में आने से पहले अर्थव्यवस्था में पूर्व स्थिति पर तेजी से पहुचने का प्रयास दर्शाता है (जैसे, लॉकडाउन हटाए जाने के बाद भरपाई में की गयी खरीददारी)।
  - V-आकार की रिकवरी: यह Z आकार की रिकवरी के बाद का परिदृश्य होता है जिसमें अर्थव्यवस्था तीव्रता से पूर्व स्थिति को प्राप्त करती है और सामान्य विकास की प्रवृत्ति-रेखा पर वापस आ जाती है।
    - इसमें आय एवं रोज़गार स्थायी रूप से समाप्त नहीं होते हैं और आर्थिक विकास की रिकवरी भी तेज़ी से होती है जिससे अर्थव्यवस्था विकृति के पूर्व की स्थिति में वापस लौट आती है। अत: विकल्प B में दिया गया कथन सही नहीं है।
  - U-आकार की रिकवरी: यह ऐसा परिदृश्य होता है जिसमें अर्थव्यवस्था, गिरने, संघर्ष करने और कुछ अवधि के लिये कम विकास दर के बाद, धीरे-धीरे सामान्य स्तर तक वृद्धि करती है।
    - इस मामले में विभिन्न प्रकार की नौकरियाँ समाप्त हो जाती हैं और लोग अपनी बचत पर निर्भर होते हैं।
  - W-आकार की रिकवरी: इस प्रकार की रिकवरी जोखिम युक्त होती है – इसमें विकास दर में कमी तथा वृद्धि होती है, तथा फिर गिरती है और पुन: वृद्धि करती है, इस प्रकार, इसमें W-आकार का चार्ट बनता है।
    - W-आकार की रिकवरी में दूसरी बार दर्शायी गई गिरावट का कारण महामारी की दूसरी लहर हो सकती है।

- L- आकार की रिकवरी: यह रिकवरी की सबसे खराब स्थिति होती है, जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद विकास एक निचले स्तर पर रुक जाता है और लंबे समय तक इस स्थिति में सुधार नहीं होता है।
  - आकार से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को स्थायी नुकसान पहुँचता है।
- K- आकार की रिकवरी: K- आकार की आर्थिक रिकवरी तब होती है, जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग दर, समय या परिमाण में 'रिकवरी' होती है। यह विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों या लोगों के समूहों में समान 'रिकवरी' के सिद्धांत के विपरीत है।
  - के-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी से अर्थव्यवस्था की संरचना में व्यापक परिवर्तन होता है और आर्थिक परिणाम मंदी के पहले तथा बाद में मौलिक रूप से बदल जाते हैं।

226.

उत्तर: B

व्याख्या:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) के गवर्नर एक बैड बैंक (Bad Bank) बनाने के प्रस्ताव पर ध्यान देने के लिये सहमत हुए हैं।
- बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
  - तकनीकी रूप से एक बैड बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी (Asset Reconstruction Company-ARC) या एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (Asset Management Company- AMC) है जो वाणिज्यिक बैंकों के बैड लोन्स को अपने नियंत्रण में लेकर उनका प्रबंधन और समय के साथ धन की वसूली करती है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- बैड बैंक ऋण देने और जमा स्वीकार करने की प्रकिया का भाग नहीं होता है, लेकिन वाणिज्यिक बैंकों का बैलेंस शीट ठीक करने में मदद करता है। अत: कथन 2 सही है।
- अमेरिका स्थित मेल्लोन बैंक (Mellon Bank) द्वारा वर्ष 1988 में पहला बैड बैंक बनाया गया था, जिसके बाद यह अवधारणा स्वीडन, फिनलैंड, फ्राँस और जर्मनी सहित अन्य देशों में लागू की गई है।
  - अमेरिका में दवाबग्रस्त परिसंपत्ति राहत कार्यक्रम (Troubled Asset Relief Programme- TARP)।
  - आयरलैंड में वित्तीय संकट से उभरने के लिये वर्ष 2009 में राष्ट्रीय परिसंपत्ति प्रबंधन एजेंसी।

227.

उत्तर: D

व्याख्या:

शिक्षा (प्रमाण पत्र), वित्त (आसान ऋण के लिये), सट्टेबाज़ी की अर्थव्यवस्था (ऑनलाइन गेम) और स्वास्थ्य सेवा (ई-फार्मेसी) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर शैडो उद्यमियों (Shadow Entrepreneurship) की उपस्थिति में वृद्धि देखी जा रही है।

- शैडो उद्यमी ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी व्यवसाय का प्रबंधन करता है तथा वैध वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करता है परंतु वह अपने व्यवसायों को सरकार के साथ पंजीकृत नहीं कराता है। अत: कथन 1 सही है।
- इस प्रकार के व्यवसायों में बिना लाइसेंस वाली टैक्सी सेवा, सड़क किनारे भोजन स्टाल लगाना और छोटे भू-निर्माण आदि कार्य शामिल हैं। अत: कथन 2 सही है।
- इंपीरियल कॉलेज बिज़नेस स्कूल (Imperial College Business School) द्वारा 68 देशों पर किये गए एक अध्ययन के अनुसार, इंडोनेशिया के बाद भारत में सबसे अधिक शैडो उद्यमी हैं। अत: कथन 3 सही है।
- लाभ:
  - रोज़गार में वृद्धि: अनौपचारिक क्षेत्र की अधिकांश नौकरियाँ शैडो उद्यमिता के अंतर्गत आती हैं। इसके अन्य लाभ इस प्रकार हैं-
  - आर्थिक विकास का चालक
  - गरीबी में कमी
  - गैर कृषि रोज़गार प्रदान कर कृषि पर दबाव को कम करना।
  - उपभोक्ताओं के लिये विविध विकल्पों की मौजूदगी।

228.

उत्तर: D

व्याख्या:

सीमित देयता भागीदारी: यह एक भागीदारी है जिसमें कुछ या सभी भागीदारों (क्षेत्राधिकार के आधार पर) की सीमित देयताएँ होती हैं।

- किसी LLP में एक भागीदार, दूसरे भागीदार के कदाचार या लापरवाही के लिये ज़िम्मेदार नहीं होता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- भागीदारों में परिवर्तन के बावजूद LLP अपने अस्तित्व को जारी रख सकता है। यह अनुबंधों को स्वीकार करने और अपने नाम पर संपत्ति का स्वामित्त्व रखने में सक्षम है।

- LLP एक पृथक विधिक इकाई है। यह अपनी संपत्ति को पूरी क्षमता तक बढ़ाने के लिये उत्तरदायी है लेकिन LLP में भागीदारों की देयता इनके स्वीकृत योगदान तक सीमित है।
- प्रत्येक भागीदार अन्य सभी भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से और फर्म के सभी कार्यों के लिये व्यक्तिगत रूप से "पारंपरिक भागीदारी फर्म" के तहत उत्तरदायी होता है, जब तक वह एक भागीदार है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

229.

उत्तर: C

व्याख्या

- ग्रीन बॉण्ड ऋण प्राप्ति का एक साधन है जिसके माध्यम से 'हरित परियोजनाओं' के लिये धन जुटाया जाता है, यह मुख्यत: नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित होता है। अत: कथन 1 सही है।
  - बॉण्ड जो कि आय का एक निश्चित साधन होता है, एक निवेशक द्वारा उधारकर्त्ता (आमतौर पर कॉर्पोरेट या सरकारी) को दिये गए ऋण का प्रतिनिधित्व करता है।
  - पारंपरिक बॉण्ड (ग्रीन बॉण्ड के अलावा अन्य बॉण्ड) द्वारा निवेशकों को एक निश्चित ब्याज दर (कूपन) का भुगतान किया जाता है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) द्वारा ग्रीन बॉण्ड जारी करने एवं इन्हें सूचीबद्ध करने हेतु पारदर्शी मानदंडों को लागू किया गया है।
- आमतौर पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण की तुलना में ग्रीन बॉण्ड पर कम ब्याज लिया जाता है।हरित निवेश विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के साथ-साथ पूंजी जुटाने की लागत को कम करने में मदद कर सकता है।
- ग्रीन बॉण्ड अक्षय ऊर्जा जैसे सनराइज़ सेक्टर के वित्तपोषण को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण रहे हैं, इस प्रकार यह भारत के सतत् विकास में योगदान देते हैं। अत: कथन 2 सही है।
  - सनराइज़ उद्योग एक ऐसे क्षेत्र के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है परंतु जिसमे भविष्य में तेजी से उछाल देखा जाता है।
  - इस क्षेत्र के बारे में जागरूकता और निवेशक इस क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को आकर्षित करते हैं।

230.

उत्तर: C

व्याख्या:

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD):

- स्थापना:
  - UNCTAD, एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसके स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी।
- मुख्यालय:
  - UNCTAD का मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में स्थित है।
- उद्देश्य:
  - यह विश्व अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के विकास अनुकूल एकीकरण को बढ़ावा देता है।
- प्रकाशित रिपोर्ट:
  - व्यापार और विकास रिपोर्ट (Trade and Development Report)
  - निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट (Investment Trends Monitor Report)
  - विश्व निवेश रिपोर्ट (World Investment Report)
  - अल्प विकसित देश रिपोर्ट (The Least Developed Countries Report)
  - सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट (Information and Economy Report)
  - प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट (Technology and Innovation Report)
  - वस्तु तथा विकास रिपोर्ट (Commodities and Development Report) अत: विकल्प C सही है।

231.

उत्तर: (C)

व्याख्या

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी नवीनतम 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में तकरीबन 11.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। अत: कथन 1 सही है।
- IMF की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् युद्ध प्रभावित देशों के पुनर्निमाण में सहायता के लिये विश्व बैंक (World Bank) के साथ की गई थी। अत: कथन 2 सही है।

- इन दोनों संगठनों की स्थापना के लिये अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में आयोजित एक सम्मेलन में सहमति बनी। इसलिये इन्हें 'ब्रेटन वुड्स ट्विन्स' (Bretton Woods Twins) के नाम से भी जाना जाता है।

- वर्ष 1945 में स्थापित IMF विश्व के 189 देशों द्वारा शासित है तथा यह अपने निर्णयों के लिये इन देशों के प्रति उत्तरदायी भी है। भारत 27 दिसंबर, 1945 को IMF में शामिल हुआ था।
- IMF का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली से आशय विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की उस प्रणाली से है जो देशों (और उनके नागरिकों) को एक-दूसरे के साथ लेन-देन करने में सक्षम बनाती है।
  - IMF के अधिदेश में वैश्विक स्थिरता से संबंधित सभी व्यापक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों को शामिल करने के लिये वर्ष 2012 में इसे अद्यतन/अपडेट किया गया था।

232.

उत्तर.C

व्याख्या:

- हाल ही में पाकिस्तान ने बासमती (Basmati) चावल को अपने भौगोलिक संकेतक अधिनियम, 2020 के तहत भौगोलिक संकेत (Geographical Indication- GI) का टैग दिया है।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI का विनियमन विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPS) पर समझौते के तहत किया जाता है। अत: कथन 1 सही है।
- वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (Geographical Indications of goods 'Registration and Protection' act, 1999) के तहत किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ।
- भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिये मान्य होता है। अत: कथन 2 सही है।

233.

उत्तर: C

व्याख्या:

- सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना लोगों को भौतिक स्वर्ण के बजाय स्वर्ण बॉण्ड खरीदने के लिये प्रोत्साहित करती है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) केंद्र सरकार की तरफ से इन बॉण्डों को जारी करता है। अत: कथन 1 सही है।
- विशेषताएँ:
  - इस योजना के तहत कम-से-कम दो ग्राम सोना और अधिक-से-अधिक 500 ग्राम सोने के मूल्य के बराबर बॉण्ड खरीदे जा सकते हैं।
  - स्वर्ण बॉण्ड केवल निवासी भारतीय संस्थाओं जैसे- व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों, ट्रस्टों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों को बेचे जाएंगे। अत: कथन 2 सही है।
  - इस बॉण्ड की परिपक्वता अवधि आठ वर्ष होती है जिसमें पाँचवें वर्ष में बाहर निकलने की भी सुविधा है। ये सभी बॉण्ड व्यापार योग्य होते हैं।
  - इन बॉण्डों को ऋण के संदर्भ में संपार्श्विक (Collateral) के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

234.

उत्तर: B

व्याख्या

- फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव (FII) को व्यापक रूप से 'डेज़र्ट इन दावोस' (Davos in the Desert) के रूप में वर्णित किया गया है। यह सऊदी अरब का प्रमुख निवेश सम्मेलन है। अत: कथन 1 सही है।
- इस फोरम का अनौपचारिक नाम यानी 'डेज़र्ट इन दावोस', वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की वार्षिक बैठक से लिया गया है, जो कि स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित होती है, जहाँ विश्व के प्रमुख नेता अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित अपना एजेंडा तय करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं।
- फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव (FII) की शुरुआत वर्ष 2017 में सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोष द्वारा की गई थी, जो कि सऊदी अरब का मुख्य संप्रभु धन कोष है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

235.

उत्तर: (A)

व्याख्या

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच/वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के 'दावोस संवाद' को संबोधित किया।
- दावोस (स्विट्ज़रलैंड) में आयोजित होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की वार्षिक बैठक में वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडों को आकार देने के लिये दुनिया के शीर्ष नेताओं द्वारा हिस्सा लिया जाता है।
- दावोस संवाद 2021 कोरोना वायरस महामारी की समाप्ति के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की 'द ग्रेट रीसेट' पहल की शुरुआत को चिह्नित करता है। अत: विकल्प (A) सही है।

- यह पहल इस आकलन पर आधारित है कि वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था गहरे संकट का सामना कर रही है।
- वैश्विक समाज पर महामारी के विनाशकारी प्रभावों और जलवायु परिवर्तन के परिणामों जैसे विभिन्न कारकों से स्थिति बहुत खराब हो गई है।

236.

उत्तर: C

व्याख्या:

- कोई भी चीज़ जिसे डिजिटल रूप में बदला जा सकता है, वह NFT हो सकती है। अत: कथन 1 सही है।
  - ड्रॉइंग, फोटो, वीडियो, जीआईएफ, संगीत, इन-गेम आइटम, सेल्फी और यहाँ तक कि एक ट्वीट सभी को NFT में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे बाद में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके ऑनलाइन कारोबार किया जा सकता है।
  - एनएफटी अन्य डिजिटल रूपों से इस मायने में अलग हैं कि वे ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा समर्थित होती हैं।
  - NFT में एक समय में केवल एक ही मालिक हो सकता है।
- NFTs नॉन-फंजिबल हैं, जिसका अर्थ है कि एक NFTs का मूल्य दूसरे के समान नहीं होता है।
- नॉन-फंजिबल का अर्थ है कि एनएफटी परस्पर विनिमेय नहीं हैं। अत: कथन 2 सही है।
  - प्रत्येक कलाकृति दूसरों से अलग होती है, जो इसे नॉन-फंजिबल और अद्वितीय बनाती है।

237.

उत्तर: C

व्याख्या:

FRP के बारे में:

- FRP सरकार द्वारा घोषित मूल्य है जिस पर मिलें किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान कानूनी रूप से करने के लिये बाध्य हैं।
  - मिलों के पास किसानों के साथ समझौते के लिये हस्ताक्षर करने का एक विकल्प है, जो मिलों द्वारा किसानों को किश्तों में FRP का भुगतान करने की अनुमति प्रदान करता है।
  - भुगतान में देरी पर 15% तक प्रतिवर्ष ब्याज लग सकता है और चीनी आयुक्त (Sugar Commissioner) मिलों की संपत्तियों को संलग्न कर राजस्व वसूली के तहत बकाया के रूप में अदत्त एफआरपी (Unpaid FRP) की वसूली कर सकते हैं।
- देश भर में FRP का भुगतान आवश्यक वस्तु अधिनियम (EAC), 1955 के तहत जारी गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 द्वारा नियंत्रित होता है, जो गन्ने की डिलीवरी की तारीख के 14 दिनों के भीतर भुगतान को अनिवार्य करता है। अत: कथन 2 सही है।
- यह कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश के आधार निर्धारित तथा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा घोषित किया जाता है।
  - CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह एक सलाहकार निकाय है, अत: इसकी सिफारिशें सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं हैं।
  - CCEA की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
- FRP गन्ना उद्योग के पुनर्गठन को लेकर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। अत: कथन 1 सही है।

238.

उत्तर: A

व्याख्या:

- स्विफ्ट विश्वसनीय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो वित्तीय संस्थानों को धन हस्तांतरण जैसे वैश्विक मौद्रिक लेन-देन के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
- जबकि स्विफ्ट वास्तविक रूप से रुपए का लेन-देन नहीं करता है, यह 200 से अधिक देशों में 11,000 से अधिक बैंकों को सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवाएँ प्रदान करके लेन-देन की जानकारी को सत्यापित करने के लिये एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।
  - अधिकांश विश्व व्यापार स्विफ्ट के माध्यम से वित्तीय संदेश भेजने के साथ होता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी तथा यह बेल्जियम में स्थित है।
- यह बेल्जियम के अलावा कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे 11 औद्योगिक देशों के केंद्रीय बैंकों की देखरेख करता है।
  - भारत की वित्तीय प्रणाली की पहुँच स्विफ्ट तक है। अत: विकल्प A सही है।

239.

उत्तर: A

व्याख्या:

- RBI सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिये अर्थव्यवस्था की कुल धनराशि में परिवर्तन करता रहता है, जैसे- जब RBI आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहता है तो वह तथाकथित "लचीली मौद्रिक नीति" अपनाता है। अत: कथन 1 सही है।
- ऐसी नीति के दो भाग होते हैं:
  - अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना: यह बाज़ार से सरकारी बॉण्ड की खरीद कर ऐसा करता है। जैसे ही आरबीआई इन बॉण्डों की खरीद करता है, यह बॉण्डधारकों को पैसा वापस कर देता है, इस प्रकार अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा का प्रवाह सुनिश्चित करता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

- ब्याज दर कम करना: दूसरा जब आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है तो वह ब्याज दर भी कम कर देता है इस दर को रेपो दर कहा जाता है।
  - जिस ब्याज दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, उस दर पर आरबीआई को वाणिज्यिक बैंकों (और शेष बैंकिंग प्रणाली) से उम्मीद होती है कि बदले में बैंक ब्याज दरों को कम करने के लिये प्रेरित होंगे।
  - कम ब्याज दर और अधिक तरलता दोनों एक साथ अर्थव्यवस्था में खपत एवं उत्पादन दोनों को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं।

- ऐसे में एक उपभोक्ता को बैंक के पास अपना पैसा रखने के लिये कम भुगतान करना होगा जो वर्तमान खपत को प्रोत्साहित करता है। फर्मों और उद्यमियों के लिये एक नया उद्यम शुरू करने हेतु इस स्थिति में पैसे उधार लेना अधिक समझदारी का काम है क्योंकि ब्याज दरें कम होती हैं।
- "कठोर मौद्रिक नीति" (Tight Monetary Policy) एक लचीली मौद्रिक नीति (Loose Monetary Policy) के विपरीत होती है इसमें आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है और बॉण्ड की विक्री करके (सिस्टम से पैसा निकालकर) अर्थव्यवस्था से तरलता को कम किया जाता है।
- जब किसी केंद्रीय बैंक को लगता है कि एक लचीली मौद्रिक नीति प्रतिउत्पादक बनने लगी है (उदाहरण के लिये जब यह उच्च मुद्रास्फीति दर की ओर ले जाती है) तो केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति को कठोर करके "नीति को सामान्य करता'' (Normalises The Policy) है।

240.

उत्तर: A

व्याख्या:

बजट में प्रमुख घोषणाएँ:

- पर्वतमाला: यह एक राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, पर्वतमाला है जिसे पीपीपी मोड पर लिया जाना है।
- किसान ड्रोन: फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों का छिड़काव।
- कौशल विकास: ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों का कौशल बढ़ाने हेतु 'डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड' (DESH-Stack e-Portal) लॉन्च किया जाएगा। अत: युग्म 1 सही सुमेलित है।
- शिक्षा: 'पीएम ई-विद्या' के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा।
- पीएम-डिवाइन: उत्तर-पूर्व में बुनियादी ढाँचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि प्रदान करने हेतु नई योजना 'पीएम-डिवाइन' (PMDevINE) शुरू की गई है। अत: युग्म 2 सुमेलित नहीं है।
- उदीयमान अवसर: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू-स्थानिक प्रणालियों और ड्रोन, सेमीकंडक्टर तथा इसका इकोसिस्टम, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स एवं फार्मास्युटिकल्स, हरित व स्वच्छ ऊर्जा आवागमन प्रणालियों में बड़े पैमाने पर सतत् विकास में सहायता करने और देश के आधुनिकीकरण की अपार संभावनाएँ हैं। अत: युग्म 3 सही सुमेलित है।